दैनिक जागरण

संदेह प्रमाण का पर्याय नहीं हो सकता

एक जरूरी इन्कार

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने राहुल गांधी एवं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात करने में असमर्थता जताकर बिल्कुल सही कदम उठाया। जिस मामले की सुप्रीम कोर्ट पहले से ही सुनवाई कर रहा हो, उसे लेकर किसी दल के नेताओं को मुख्य न्यायाधीश से संपर्क एवं संवाद करना कत्तई उचित नहीं है और न ही ऐसी कोई परंपरा रही है। राहुल गांधी शुद्ध संकीर्ण राजनीतिक कारणों से एक नई, किंतु खराब परंपरा स्थापित करने की जो कोशिश कर रहे थे, उसे खारिज किया जाना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य था। यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने राहुल गांधी के समक्ष उन कारणों को दो टूक ढंग से स्पष्ट किया कि वे उससे मुलाकात क्यों नहीं कर सकते? अच्छा हो कि राहुल गांधी को यह समझ आए कि वे हर मामले में मनमानी नहीं चला सकते। उन्हें सुनिश्चित लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के साथ ही आगे बढ़ना होगा। इसलिए और भी, क्योंकि वे गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार करने के आदी हो चुके हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण अर्थात एसआइआर के मुद्दे पर ही राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद इतना अधिक बेतुका बयान दिया कि राष्ट्रपति भवन को उसका तुर्त खंडन करना पड़ा। इस खंडन ने राहुल गांधी को एक अगंभीर एवं अविश्वसनीय नेता के तौर पर ही रेखांकित किया। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि एक बार वे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भी गलत बयानी कर चुके हैं। इसके लिए उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी थी, लेकिन उनका रवैया सुधरा नहीं। एसआइआर के मुद्दे को अनावश्यक तूल दे रहे राहुल गांधी ने इस तथ्य की अनदेखी ही कि इस मुद्दे को सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की पीठ की ओर से ही की जा रही है। यदि उन्हें इस मामले में कुछ और कहना-बताना था तो उसका तरीका वाचिका ही हो सकता था। आखिरकार उन्हें इसी तरीके का सहारा लेना पड़ा।

वैसे तो राहुल गांधी एक लंबे अर्से से एसआइआर को वोट चोरी बताने में लगे हुए हैं, लेकिन जबसे यह समाचार आया कि एसआइआर के कुछ पहलुओं पर दोनों चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त से असहमत थे, तबसे राहुल गांधी नए सिरे से आक्रामक हो गए। हालांकि इस खबर के बाद तीनों चुनाव आयुक्तों ने यह बयान जारी करके स्पष्ट किया कि जो भी असहमतियां थीं, उनका समाधान कर लिया गया था। कायदे से इसके साथ ही इस प्रसंग का पटाक्षेप हो जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने सड़कों पर उतरना आवश्यक समझा। बहती गंगा में हाथ धोने के लिए कांकरोच जनता पार्टी के लोग भी मैदान में आ गए। राहुल गांधी और सीजेपी के नेता कुछ भी दावा करें, एसआइआर को लेकर उनका शोरगुल एक शिगूफे से अधिक कुछ नहीं।

ठोस समाधान आवश्यक

उत्तराखंड में संपर्क मार्गों का तेजी से विस्तार हो रहा है। प्रति वर्ष नई सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए आधार तैयार कर रही हैं। सड़क नेटवर्क जितना तेजी से विकसित होगा, उतना ही पर्यटन, उद्योग, कृषि एवं अन्य व्यवसायों को भी दूरस्थ शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोत्साहन मिलेगा। सड़कों के निर्माण में प्रगति के साथ ही एक समस्या की ओर भी समुचित ध्यान देने की आवश्यकता है। नई सड़क बनने या पहले से बनी सड़क पर मनमाने तरीके से खोदाई गंभीर समस्या बन चुकी है। विभागों में समन्वय की कमी इसका प्रमुख कारण है। ऐसा नहीं है कि इस समस्या का संज्ञान ही नहीं लिया गया या इसके निदान की दिशा में कदम नहीं उठाए गए, जिलों से लेकर शासन स्तर पर गंभीर चर्चा के बाद इसके निराकरण के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं। इसके बावजूद धरातल पर क्रियान्वयन की स्थिति अत्यंत कमजोर है। परिणामस्वरूप नई बनी सड़कों पर भी जगह-जगह खोदाई नजर आ जाती है। यह सरकारी धन का दुरुपयोग है। साथ ही निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से मुंह मोड़ने का भी यह माध्यम बन चुका है। अब लोक निर्माण विभाग ने सड़क कटान की नीति बनाई है। इस पर अमल हुआ तो मात्र दिसंबर और जनवरी माह में ही सड़क खोदाई की अनुमति कार्यदायी संस्थाओं को मिल पाएगी। साथ में सड़क खोदने वाली संस्था को निर्माण के दो वर्ष बाद उसके रखरखाव की जिम्मेदारी को भी उठाना होगा। इस नीति पर मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिलना शेष है।

> सड़क खोदाई के लिए मानक संचालन प्रविधि यानी एसओपी तैयार की जानी चाहिए और विभागों के लिए इसका पालन अनिवार्य हो

भरोसे के संकट से जूझता विपक्ष



आशुतोष झा

राजनीतिक दल यह समझें कि बगैर विश्वसनीयता के न तो आंदोलन लंबा खिंच सकता है और न ही राजनीति



अवधेश राजपूत

जो बात आज तक बंद कमरे में कही जा रही थी, जिस बात की अटकलें लगती थीं या फिर आरोप लगता था, उसे आखिरकार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने खुद ही स्वीकार कर लिया है। चेन्नई में उन्होंने साफ-साफ कहा कि सरकार विरोधी आंदोलन को वह सत्ता बदलने और जाहिर तौर पर हासिल करने का संग्राम बनाना चाहते हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी अगर मुद्दा आधारित चुनावी राजनीति के बजाय अगले दो-ढाई साल तक इसी तरह आंदोलन करना चाहती है, सड़कों को बंद करना चाहती है, सरकार का विरोध करने के लिए भारतीय कंपनी की बजाय विदेशी कंपनी का स्वागत करना चाहती है तो यह स्वाभाविक रूप से चिंताजनक है। यह सोचना भी खतरनाक है कि पड़ोसी देश नेपाल और बांग्लादेश में जो कुछ और जिस तरह हुआ वह सही था। बहुत जरूरी है कि स्थापित राजनीतिक दल यह समझें कि जनता की उनसे गंभीर अपेक्षाएं होती हैं। अगर वह भी सामान्य छात्र संगठनों से प्रतिस्पर्धा करने लगेंगे तो अपने ही हाथ जलाएंगे।

लोकतंत्र में आंदोलन गैर-कानूनी नहीं है, लेकिन आंदोलन की सियासत राजनीतिक दलों की विश्वसनीयता को ही खत्म करती है। खासतौर से तब जबकि मुद्दे का जमीनी जुड़ाव न हो। उसमें तथ्यों की कमी हो। कांग्रेस और विपक्षी दलों ने यही गलती कर दी। आंदोलन के जरिये उन्होंने सत्ता हासिल करने का मंसूबा तो जाहिर कर दिया, लेकिन मुद्दा गलत चुन लिया। मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) को मुद्दा बना लिया। वोट चोरी का नारा बुलंद किया जा रहा है, लेकिन खुद राहुल गांधी की और से शुरू किए गए सत्याग्रह पोर्टल ने मुद्दे की पोल खोल दी। इसमें लगभग दो प्रतिशत लोगों ने ही वोट चोरी को बड़ा मुद्दा माना है। अगर कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं से इतना भी मैनेज नहीं करवा पाई है तो आश्चर्य है कि ढाई साल तक आंदोलन कैसे चल पाएगा।

राहुल गांधी ने कुछ समय पहले कहा था कि ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और तेजस्वी यादव भी वोट चोरी की बातों से पूरी तरह सहमत नहीं। हाल में आइएनडीआइए की बैठक में भी साफ हुआ कि कांग्रेस के ही कई नेता उनकी बातों से सहमत नहीं हैं। फिर ऐसे मुद्दे का चयन क्यों, जो जमीन से जुड़ा ही न हो। कांग्रेस की रणनीति भी समझ से परे है। छात्रों की गूंज जैसे गंभीर मुद्दे पर फूहड़ हास्य का चयन क्यों किया जाता रहा, जबकि उसका नुकसान ही हुआ। राष्ट्रपति से मिलने के बाद यह कहना कि उन्होंने वोट चोरी का आरोप मान लिया, जैसे बयान भी विश्वसनीयता के लिए घातक हो रहे हैं और बगैर विश्वसनीयता के न तो आंदोलन लंबा खिंच सकता है और न ही राजनीति।

एसआइआर की बात होते ही 13 करोड़ के आंकड़े उछाल दिए जाते हैं। इसे जितनी बार दोहराया जाएगा विश्वसनीयता उतनी कम होती जाएगी, क्योंकि आरोप-प्रत्यारोप के इस दौर में अब आम लोगों को भी आंकड़ा याद होने लगा है कि आपत्ति जताने वालों की संख्या इसके दसवें हिस्से से भी कम है। यह सच है कि कानूनी रूप से वैध एक भी मतदाता सूची से बाहर नहीं छूटना चाहिए। चुनाव आयोग को भी इसकी पूरी फिक्र करनी चाहिए कि हर किसी को पर्याप्त समय मिले और अधिकारी फैसला लेने में सक्षम हों। विपक्षी दलों को बहुत फायदा होता अगर अपने कार्यकर्ताओं को सड़क बंद करने की बजाय इस काम में लगा दिया होता कि उन मतदाताओं को दस्तावेज तैयार कराने से लेकर सुनवाई तक में मदद करें, जिनके नाम कथित रूप से बाहर हो गए हैं, पर ऐसा नहीं किया गया। एसआइआर मामले में विश्वसनीयता तभी बनेगी, जब ये राजनीतिक दल अपने खाते में कम से कम दस-दस हजार ऐसे नाम जोड़ें जो उनके परिश्रम के कारण मतदाता सूची में शामिल हुआ। फिलहाल किसी के खाते में एक भी नाम नहीं है। लिहाजा आंदोलन की राजनीति के बजाय सकारात्मक एजेंडे और रोडमैप की राजनीति पर जाना उनके हित में होगा। वे एंटी इनकंबेंसी के भरोसे न रहें कि सरकारें स्वतः बदल जाती हैं। वही सीच घाटवार के बढ़ाता है। सरकारें तब भी दोबारा आती रही हैं, जब पूर्व में हुए एसआइआर को लेकर विवाद नहीं खड़ा हुआ करता था।

पिछले सप्ताह राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने लगातार तीन दिन तक दिल्ली में आंदोलन किया। रोज दोपहर के बाद विपक्षी दलों में भी सरप्राइज फैक्टर होता था कि आज किस तरफ जाना है और कहां धरना देन है। दो दिन बाद काकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने आंदोलन की घोषणा की और उससे निपटने के लिए शासन-प्रशासन की तैयारी अभूतपूर्व थी। सच्चाई यह है कि राजनीतिक दलों का आचरण और व्यवहार एक सीमा के अंदर होता है। वहां जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति या समूह तक पहुंचती है। सीजेपी जैसे संगठन के आंदोलन में मर्यादा और जिम्मेदारी की यह सीमा नहीं होती।

संविधान में सरकार गिराने और सरकार गठन का रास्ता तय है। दोनों में नंबर से तय होते हैं और नंबर के लिए चुनाव जरूरी होते हैं। चुनाव के लिए वैध मतदाता सूची की जरूरत है और वैध मतदाता की पहचान के लिए एसआइआर जरूरी है। संविधान स्पष्ट करता है कि किसी कानूनी प्रक्रिया की पड़ताल कोर्ट करेगा और कोर्ट ने एसआइआर को वैधानिक माना है। कोई आपत्ति है तो राजनीतिक दलों को कोर्ट जाना चाहिए। आखिर अब तक कोई राजनीतिक दल ज्ञानेश कुमार के खिलाफ शिकायत लेकर कोर्ट क्यों नहीं गया। दूसरों के पीछे छिपने का क्या अर्थ है। जो तथ्य विपक्षी दल राष्ट्रपति को नहीं दे सके, वह कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए। जो लोग सूची से बाहर हुए हैं, ऐसे मतदाताओं को दोबारा शामिल कराने के लिए पर्याप्त मदद देनी चाहिए। राजनीतिक दलों से इस व्यवहार की आशा जनता करती है, राजनीतिक दल से टूट कर बने किसी संगठन से यह आशा अपेक्षा नहीं होती है। वैसे खुद को छात्रों का प्रतिनिधि बताकर अब धीरे-धीरे राजनीति में प्रवेश की महत्वाकांक्षा पाले सीजेपी का चेहरा भी साफ होने लगा है। इसलिए उसे भी जवाब के लिए तैयार होना होगा। इस प्रेशर ग्रुप से अपेक्षा की जाएगी कि वह अपने राजनीतिक साथियों पर दबाव बनाए। सुधार का रास्ता तो विधायिका से ही आएगा।

(लेखक दैनिक जागरण के राजनीतिक संपादक हैं)
response@jagran.com

माता-पिता के रहते भी अनाथ होते बच्चे

हाल में एक वीडियो देखा, जिसमें एक महिला मांग में सिंदूर भरे, काजल, बिंदी और नेल पालिश लगाए, सिर ढके हुए है। साथ में उसका पुरुष मित्र खड़ा है। एक यूट्यूबर उससे सवाल करता है-तो आप अपने पति को छोड़ आई हैं? महिला कहती है-हां। यूट्यूबर फिर पूछता है-कारण क्या था? महिला कहती है-पति से प्यार नहीं करती थी। जिससे प्यार करती थी, उसके साथ आ गई। रिपोर्टर पूछता है-सुना है, आपके कई बच्चे हैं। महिला कहती है-हां, हैं। रिपोर्टर पूछता है-तो उनका क्या होगा? महिला कहती है-जो हो, सो हो। जिसके बच्चे हैं, वह पाले। एक दूसरे वीडियो में मुस्लिम महिला सिंदूर लगाए दिखाई देती है। लड़के की मां उसे भला-बुरा कह रही है। रिपोर्टर लड़के से कहता है-आपकी मां बहुत नाराज हो रही हैं। क्या इन्हें साथ रखेंगे? लड़का कहता है-हां, रखेंगे। एक अन्य वीडियो में देखा कि एक सज्जन साल का लड़का चालीस साल की महिला से मंदिर में शादी कर लेता है। उसे घर लाता है तो घर वाले महिला को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मां कहती है कि यह उम्र में मुझसे कुछ ही छोटी है, मैं इसे अपनी बहू कैसे मान लूं? इस महिला के कई बच्चे भी हैं। इस पर महिला कहती है कि उनकी देखभाल पति करेगा। इन सभी महिलाओं की कहानियों में मोबाइल की प्रमुख भूमिका है। वे बताती हैं कि मिस्ड काल आया था। बातचीत होने लगी, फिर प्यार हो गया।



इन दिनों पति और बच्चों के रहते कुछ महिलाओं का दूसरे पुरुष के साथ शादी करने के मामले बढ़ने लगे हैं

धनंजय शर्मा



बच्चों के पालन-पोषण से जुड़ीं नई चुनौतियां। फाइल

इनसे अलहदा ऐसी कहानियां भी प्रकाश में आई हैं, जहां कोई महिला अपने दामाद के साथ चली गई। उसने अपनी लड़की के भविष्य के बारे में नहीं सोचा। एक महिला तो लड़की की शादी तय होने के बाद होने वाले दामाद से बातचीत करने लगी, फिर उसी के साथ रहने पर अड़ गई। किसी को अपने समधी से मोहब्बत हो गई। वह उसके साथ रहने पर अड़ गई। इन सभी कहानियों में एक जैसी बात जो सुनाई देती है, वह यह है कि शादी इनकी नहीं, इनके माता-पिता की मर्जी से हुई थी। इन्होंने जीवन में जिम्मेदारियों के अलावा प्यार जैसी चीज को कभी महसूस ही नहीं किया। इसलिए जैसे ही लगा कि किसी से प्यार हो गया है तो सब कुछ छोड़कर उसके साथ हो लीं। यह देखना भी दिलचस्प है कि इनमें से शायद ही किसी महिला का अपने पति से संबंध-विच्छेद हुआ है, तलाक लिया है या वे उससे अलग रह रही थीं। सब पति के साथ ही रह रही थीं और मंदिर में जाकर शादी कर ली। ऐसे में कानूनी तौर पर तो इनका विवाह अवैध ही माना जाएगा। कल को यदि वह लड़का, जिसके साथ ये अपने परिवार को छोड़कर चली आई हैं, वह भी इनसे किनारा कर ले तो कानून और पुलिस भी इनकी मदद नहीं कर सकेंगे। हां, यदि ये दुष्कर्म का आरोप लगा दें, तब शायद कुछ मदद हो सके, लेकिन वह भी कितनी होगी, कहा नहीं जा सकता।

इन मामलों का एक दूसरा पहलू भी है कि सभी महिलाओं के कई-कई बच्चे हैं। वे अपनी मां को खोज रहे हैं। वे बच्चे अपने संगी-साथियों, अड़ोस-पड़ोस के ताने एवं मजाक सुन रहे हैं। कइयों ने तो स्कूल तक जाना छोड़ दिया है। वे उस शर्मिंदगी को झेल रहे हैं, जिसमें उन्होंने कुछ नहीं किया। यह भी देखना दिलचस्प है कि ऐसी घटनाएं महानगरों के मुकाबले छोटे शहरों और गांवों में अधिक हो रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, यह समाजशास्त्रीय अध्ययन का विषय भी हो सकता है। पुराने जमाने से सुन रहे हैं कि पुत्र कुपुत्र (बुरा या नालायक) हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता (बुरी) नहीं हो सकती, लेकिन इन घटनाओं ने जैसे इस विचार पर भी विराम लगा दिया है। स्त्रीवादी विचार इसे महिला की पसंद और उसके निर्णय लेने की क्षमता मान सकता है। यह भी कह सकता है कि आखिर स्त्री को भी अपनी जिंदगी चलाने के गलत-सही फैसले लेने का हक है। फिर बच्चों को पालने की जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं की ही तो नहीं है। अर्से से पुरुष अपनी पत्नी के होते हुए भी दूसरी ले आते हैं, तब तो कोई शिकायत नहीं करता, लेकिन आज महिलाएं ऐसा करने लगीं तो सबको शिकायत हो रही है, लेकिन यदि स्त्री के अधिकार हैं तो ऐसे मामलों में उन बच्चों के अधिकारों को कैसे परिभाषित किया जाएगा? उनका तो पूरा जीवन ही दांव पर लग गया है। अब वे किसके पास जाएंगे? यदि अपनी मां ही उन्हें छोड़कर चली गई तो कौन दूसरा है, जो उनकी सुनेगा? कल को यदि पिता भी दूसरी शादी कर ले तो उनका क्या होगा? यदि अपनी मां ही अपने बच्चों को पालना, उनकी देखभाल करना नहीं चाहती तो विमाता ऐसा क्यों करेगी? वह कह सकती है कि वह दूसरों के बच्चे क्यों पाले। ऐसे में उन बच्चों के पास न तो कोई अपना होगा, न कोई घर होगा। फिर उनकी पढ़ाई-लिखाई कैसे होगी? उनके खाने-पीने का ध्यान कौन रखेगा? कल को बीमार पड़ें तो उनकी देखभाल कौन करेगा? कोई मारपीट करे तो उन्हें कैसे बचाया जाएगा?

बच्चों के लिए काम करने वाले संगठन कहते हैं कि बच्चों के समुचित विकास के लिए माता-पिता, दोनों का प्यार और स्नेह चाहिए। उन्हें प्यार के साथ डांटने और समझाने-बुझाने वाला तथा अच्छा करने पर तारीफ करने वाला भी चाहिए, लेकिन ये बच्चे तो माता-पिता के रहते हुए भी जैसे अनाथ होकर जी रहे हैं।

(लेखिका साहित्यकार हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

शरणागत

'शरणागत' शब्द केवल किसी के आश्रय में चले जाने का संकेत नहीं है। शरणागत है, जो अपने अहंकार, भय और सीमित सामर्थ्य को पहचानते हुए किसी उच्चतर सत्य, ईश्वर या सद्गुरु के प्रति श्रद्धापूर्वक स्वयं को समर्पित कर देता है। यह समर्पण कमजोरी नहीं, बल्कि उस आंतरिक शक्ति का परिचायक है, जिसमें मनुष्य अपनी सीमाओं को स्वीकार करके असीम सत्ता पर विश्वास करना सीखता है। गीता में श्रीकृष्ण कहते हैं-शरणागति केवल बाहरी रूप से ईश्वर की शरण ग्रहण करना नहीं है, बल्कि अपने अहंकार, कर्तापन और फल की आसक्ति को परम सत्य के समक्ष अर्पित करना है। जब मनुष्य यह स्वीकार करता है कि वह सब कुछ अपने बल पर नियंत्रित नहीं कर सकता, तभी उसके भीतर वास्तविक विश्वास का जन्म होता है। रामायण में भी शरणागत की रक्षा को धर्म का महान आदर्श माना गया है। श्रीराम का यह भाव कि जो एक बार शरण में आ जाए, उसे अभय देना उनका व्रत है, हमें बताता है कि शरणागति केवल व्यक्ति और ईश्वर के बीच का संबंध नहीं, बल्कि मानव आचरण का भी आदर्श है। जो स्वयं शरणागत होने का अर्थ समझता है, वह दूसरों के प्रति भी करुणा और संरक्षण का भाव विकसित करता है।

शरणागति का अर्थ परिस्थितियों से पलायन नहीं है। सच्चा शरणागत कठिनाइयों के सामने हाथ नहीं छोड़ता। वह ईश्वर में विश्वास रखते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है। उसके कर्म में पुरुषार्थ रहता है, लेकिन परिणाम के प्रति अहंकार नहीं। यही समर्पित कर्म धीरे-धीरे मन को भय, चिंता और अस्थिरता से मुक्त करता है। वास्तविक शरणागति तब जन्म लेती है, जब 'मैं' का आग्रह धीरे-धीरे कम होने लगता है और उसके स्थान पर 'आप' का भाव विकसित होता है। अहंकार के क्षय के साथ विनम्रता आती है, भय के स्थान पर विश्वास और अशांति के स्थान पर आंतरिक शांति।

प्रो. आनंदप्राकाश त्रिपाठी 'रत्नेश'

कैसे सशक्त बनेगी हमारी भावी पीढ़ी

रामबाबू सोनी

यूनेस्को ने कहा है कि वर्तमान समय में शिक्षक एआइ, सम्मेलन, प्रवासन और जलवायु परिवर्तन जैसी कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। दूसरी ओर शिक्षकों की कमी, नियुक्तियों में पारदर्शिता का अभाव और शिक्षकों से बढ़ती अपेक्षाओं के कारण शिक्षकों में नौकरी छोड़ने की प्रवृत्ति बढ़ी है, शिक्षा क्षेत्र में अपना करियर बनाने के प्रति रुचि भी कम होती जा रही है। रिपोर्ट बताती है कि वर्तमान में विश्व में 10.7 करोड़ शिक्षक हैं और वैश्विक स्तर पर शिक्षकों द्वारा नौकरी छोड़ने की दर पूर्व प्राथमिक स्तर पर 7.2 प्रतिशत, प्राथमिक स्तर पर 4.7 प्रतिशत और माध्यमिक स्तर पर 5.4 प्रतिशत है। 2030 तक सभी बच्चों की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए वैश्विक स्तर पर पांच करोड़ अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता होगी।

> 2030 तक सभी बच्चों की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए वैश्विक स्तर पर पांच करोड़ अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता होगी

भारतीय संदर्भ में यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फार्मेशन सिस्टम फार एजुकेशन (यूडाइस) की वर्ष 2025-26 की रिपोर्ट बताती है कि देश में 1,00,843 विद्यालयों में मात्र एक ही शिक्षक है। 2024-25 में यह संख्या 1,04,125 और 2023 में 1,10,974 थी। यह अत्यंत ही गंभीर विषय है। जिस दिन यह एकमात्र शिक्षक अवकाश पर हो तो उस दिन पूरे विद्यालय की छुट्टी हो जाती है। सिर्फ एक शिक्षक को सभी कक्षाएं लेने, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करने, विभागीय रिपोर्ट तैयार करने और समय-समय पर गैर-शिक्षकीय कार्य जैसे सर्वे आदि करने पड़ते हैं, इससे शिक्षा की गुणवत्ता नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही है। शिक्षक जब अपना सर्वाधिक समय विद्यार्थियों को देंगे तभी शिक्षा का उद्देश्य पूरा हो सकेगा। केंद्र सरकार के कम्प्रिहेंसिव माडयूलर सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 30.7 प्रतिशत विद्यार्थी प्राइवेट कोचिंग ले रहे हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंकड़ा 25.5 प्रतिशत है। स्पष्ट है कि विद्यालयों में बच्चों की समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान और शिक्षण नहीं हो पा रहा है, जबकि शिक्षकों का कार्य बच्चों के व्यक्तित्व का विकास करना और उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनाना है।

शिक्षकों को निर्धारित बाला अत्यल्प वेतन भी एक बड़ी चुनौती है। निजी विद्यालयों में वेतन निर्धारण का कोई मापदंड नहीं है, जबकि अपेक्षा यह रहती है कि कम से कम वेतन पर अच्छे से अच्छा शिक्षक मिल जाए। कम वेतन पर नियुक्त शिक्षक अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते हैं। विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्तियां पर्याप्त संख्या में हों, शिक्षकों की सेवानिवृत्ति के पूर्व ही नवीन शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जानी चाहिए और शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों में लगाना बंद कर देना चाहिए तभी हम देश के लिए एक सशक्त भावी पीढ़ी का निर्माण कर सकेंगे।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

विरोध के नाम पर अराजकता

'आंदोलन वही, जो भरोसा पैदा करे' शीर्षक से प्रकाशित डा. रामानंद शर्मा का लेख पढ़ा। कुछ दिनों पहले नीट पेपर लीक से आक्रोशित युवा मन को भुनाने वाले सीजेपी के कथित छात्र आंदोलन को केंद्र सरकार ने दबाया नहीं, बल्कि युवा मन की पीड़ा को समझते हुए वह सब कुछ किया जो उस समय की परिस्थिति में उचित था, लेकिन एक विशुद्ध राजनीतिक मांग के साथ सीजेपी का दिल्ली की बंघक बनाने का मंसूबा था जिसको न तो सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिली और न ही दिल्ली पुलिस ने उसे परवान चढ़ने दिया। अस्त्रमति और विरोध स्वस्थ लोकतंत्र का हिस्सा हैं, लेकिन विरोध के नाम पर अराजकता फैलाने की कोशिश करना राष्ट्र विरोधी कृत्य है। जिस एसआइआर का विपक्षी दलों द्वारा विरोध किया जा रहा है, वह एक कानूनसम्मत प्रक्रिया है। जो कांग्रेस के शासनकाल में भी अपनाई गई थी और अब भी उसी संवैधानिक प्रक्रिया से मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जा रहा है। बावजूद इसके यदि किसी को कोई आपत्ति है तो वह उचित स्थान पर अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए स्वतंत्र है। देश का सर्वोच्च न्यायालय इस तरह की आपत्तियों पर नियमित रूप से सुनवाई कर भी रहा है, फिर देश के माहौल को तनावपूर्ण क्यों बनाया जा रहा है? राजनीतिक दलों का मोहरा बनने वाली सीजेपी को भी यह बात समझनी चाहिए कि भारत जैसे मजबूत लोकतांत्रिक देश को बंधक बनाकर बैंक डोर से सत्ता पर काबिज नहीं हुआ जा सकता। नीट पेपर लीक के जायज मुद्दे पर देश का युवा मन उनके साथ था, लेकिन अब एसआइआर की ओट में 'वोट चोरी' के झूठे आरोप के साथ चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को निशाने पर लेने से वही युवा मन उससे छिटक गया, जिसकी उनकी सुनियोजित मुहिम फ्लाप हो गई। विरोध की ओट में देश को अस्थिर करने वाली अराजकता को समर्थन नहीं मिल सकता।

ज्ञ. वीपी पाण्डेय, अलीगढ़ (उप्र)

मेलबाक्स

नारी शक्ति और वास्तविक नारीवाद

मां दुर्गा की आराधना केवल नारी शक्ति का उत्सव नहीं, बल्कि शक्ति, साहस, मर्यादा और न्याय के वास्तविक अर्थ को समझने का अवसर भी है। आज के समय में कुछ महिलाएं नारीवाद, आजादी और बराबरी के नाम पर न केवल पुरुषों को गलत ठहराती हैं, बल्कि कभी-कभी अपनी गलतियों को भी अधिकार और स्वतंत्रता का नाम देकर सही साबित करने लगती हैं। लेकिन आजादी का अर्थ मनमानी नहीं, बराबरी का अर्थ किसी को नीचा दिखाना नहीं और नारीवाद का अर्थ हर पुरुष को दोषी ठहराना नहीं है। गलत को गलत कहने का साहस ही वास्तविक सम्मानता की पहचान है, चाहे गलती किसी से भी हुई हो। नारी सशक्तीकरण का अर्थ अपनी इच्छानुसार जीने का अधिकार जरूर है, पर उस स्वतंत्रता के साथ दूसरों की गरिमा, सहमति और अधिकारों का सम्मान करना भी उतना ही आवश्यक है। अधिकारों के साथ जिम्मेदारी और स्वतंत्रता के साथ आत्ममंथन भी होना चाहिए। मां दुर्गा शक्ति और न्याय की प्रतीक हैं, अहंकार और द्वेष की नहीं। उनकी उपासना हमें सिखाती है कि असली शक्ति किसी को गिराने में नहीं, बल्कि सत्य के साथ खड़े होने में है। एक सशक्त नारी वह नहीं जो पुरुषों को गलत साबित करके स्वयं को सही ठहराए, बल्कि वह है जो अपने अधिकारों के साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी समझे और अपनी गलतियों को स्वीकार करने का साहस रखे। ऐसी नारी शक्ति का सम्मान करें जो स्वतंत्र भी हो, आत्मनिर्भर भी, आत्मसम्मान से भरी भी और न्यायप्रिय भी। क्योंकि वास्तविक नारीवाद पुरुषों से श्रेष्ठ बनने की नहीं, बल्कि समान अधिकार, समान सम्मान और समान न्याय की बात करता है। समानता का अर्थ किसी एक को ऊपर उठाकर दूसरे को गिराना नहीं, बल्कि दोनों के लिए एक ही नैतिक कसौटी रखना है।

अभिव्यंजना पाण्डेय, सीतापुर

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, अई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : (0120)-4615600, E-mail: delhi@jagran.com. R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायलय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

आजकल

पाकिस्तान को अमेरिकी ड्रोन मिलने के मायने

अमेरिकी ड्रोन कंपनी पावरअस ने भारत के साथ ड्रोन और उसकी तकनीक का समझौता किया है, लेकिन बीते माह इसी कंपनी ने पाकिस्तान की सेना के साथ भी ऐसा ही समझौता किया है। इस कंपनी के प्रस्तावित कारपोरेट विलय से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटों का निवेश सामने आया है। साथ ही, यह कंपनी भारतीय रक्षा बाजार में पूरी तरह से सक्रिय है। फिर 17 सितंबर को इसने वैसा ही समझौता (एमओयू) पाकिस्तान से क्यों किया? एक अमेरिकी कंपनी आखिर दोनों देशों के साथ कैसे कारोबार कर रही है? क्या इससे दोनों देशों की सैन्य गोपनीयता, तकनीकी सुरक्षा और रक्षा जरूरतों को सुरक्षित रखा जा सकेगा



युद्ध के दौरान ड्रोन की महत्ता निरंतर बढ़ रही है, जिससे सभी देश इसे पाने की इच्छा रखने लगे हैं। फाइल



संजय श्रीवास्तव
तकनीकी मामलों के जानकार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटों से जुड़ी पावरअस कंपनी का पाकिस्तान में ड्रोन प्रोडक्शन यूनिट लगाना संबंधित देशों का अपना मामला है और सामान्यतया कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में जब यह कंपनी भारत में एक निजी रक्षा उत्पादन कंपनी से ड्रोन के बाबत करार करती है और वही पाकिस्तान में भी इसके निर्माण का मंसूबा रखती है, तब इसे इतना सामान्य मानना रणनीतिक भूल होगी। इस आसन्न समझौते से तमाम ऐसे सवाल उठे हैं, जिनका जवाब मुश्किल मालूम होता है। जून में पावरअस ने भारत की पारस डिफेंस को 'गार्डियन-1' काउंटर-ड्रोन सिस्टम का एक्सक्लूसिव प्रोडक्शन लाइसेंस दिया। केवल तीन महीने बाद उसका पाकिस्तानी सेना के साथ ड्रोन सिस्टम और निर्माण सहायता उपलब्ध कराने का समझौता करना मात्र संयोग है अथवा सुनियोजित रणनीतिक पैंतरा?

पाकिस्तान को आखिर इतने ड्रोन क्यों चाहिए कि उसकी अमेरिकी फैक्ट्री लगाई जाए? अगर बात संख्या, विविधता, गति और तकनीकी प्रयोग की है, तो क्या तुर्किए और चीनी ड्रोन पर उसका विश्वास डिग रहा है? वे उतने कारगर नहीं, जितनी उसकी मंशा है? पाकिस्तान को भी पता है कि भविष्य के युद्ध में महंगे लड़ाकू विमान से ज्यादा कारगर सैकड़ों सस्ते ड्रोन होंगे, जिन्हें निगरानी, इलेक्ट्रानिक युद्ध, लक्ष्य निर्धारण, वायु रक्षा को बल और सहायता देने तथा आत्मघाती हमलों में इस्तेमाल किया जा सकेगा। भारत के विदेश मंत्रालय ने मई, 2025 में बताया था कि पाकिस्तान की ओर से लगभग 400 ड्रोन भेजे गए, लेकिन भारतीय प्रणालियों ने उन्हें आसानी से बेकार कर दिया। संभव है इस अनुभव ने पाकिस्तान को संदेश दिया हो कि बड़े पैमाने पर ड्रोन उपलब्धता जरूरी है।

यूक्रेन का युद्ध ड्रोन नवाचार की प्रयोगशाला बन चुका है। वहां एफपीवी ड्रोन, स्वायत्त प्रणालियां, इलेक्ट्रानिक युद्ध, एआइ-सहायित लक्ष्य पहचान और कम लागत वाले इंटरसेप्टर लगातार विकसित हुए हैं। पावरअस यूक्रेनी ड्रोन तकनीक के साथ काम कर रही है और उसके पास विभिन्न स्वायत्त प्रणालियों से जुड़े अधिकार हैं। इसलिए पाकिस्तान शायद किसी एक प्लेटफार्म से अधिक सीधे युद्ध से निकली तेजी से बदलती तकनीक तक पहुंच चाहता है।

पाकिस्तान की ड्रोन रणनीति का एक मकसद भू-राजनीतिक हेजिंग, बाड़बंदी का भी है। चीन रक्षा आयात की करीब 80 प्रतिशत आपूर्ति करता है, तुर्किए पाकिस्तान में लड़ाकू ड्रोन असेंबली प्लांट लगाने की योजना बना रहा है और अब अमेरिका पावरअस के जरिये प्रवेश कर रहा है। चीन भारी संख्या में ड्रोन देता है, लेकिन अधिकतर सर्वेक्षण और हमला करने वाले, तुर्किए उच्च स्तरीय लड़ाकू ड्रोन तकनीक मुहैया कराता तो है, लेकिन अमेरिका यूक्रेन के मैदान में परखी हुई कम लागत वाली इंटरसेप्शन तकनीक और इलेक्ट्रानिक युद्ध का अनुभव देगा, जो चीन और तुर्की फिलहाल नहीं दे सकते। इसके अलावा, पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनीर ट्रंप परिवार को मुनाफा देकर इस्लामाबाद के लिए महत्वपूर्ण क्षणों में अमेरिकी की 'सद्भावनापूर्ण तटस्थता' और भविष्य के भारत-पाक संकट में कूटनीतिक छतरी सुरक्षित करना चाहता है, तो साथ ही अमेरिका से रक्षा संबंधों को पुनर्जीवित करके वह चीन पर अत्यधिक निर्भरता को कम करना भी चाहता है।

पाकिस्तान द्वारा पावरअस की ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करने का मतलब है कि एक ही तकनीक के दो संस्करण युद्धक्षेत्र में आमने-सामने हो सकते हैं। प्रश्न है कि यदि भारत-पाक संघर्ष बढ़ा, तो क्या अमेरिका तकनीकी बैकडोर, सप्लाई चेन प्रतिबंध या डाटा लिंक निर्भरता के जरिये 'पक्षपात' करेगा? ड्रोन के मामले में पाकिस्तान चीन से मिली संख्या, तुर्की से प्राप्त गुणवत्ता और यूक्रेनी युद्ध के अनुभव से परिपूर्ण तकनीक- इन तीनों आयामों में एक साथ आगे बढ़ रहा है। ड्रोन को लेकर पाकिस्तान की तेजी से बदलती रणनीति, उस पर निरंतर तेज कारगुजारियां और दक्षिण एशिया में ड्रोन युद्ध को लेकर बढ़ती प्रतिस्पर्धा, साथ ही अमेरिका की उभरती रक्षा-तकनीकी कंपनियों के वैश्विक विस्तार के तहत भारत को वायु रक्षा प्रणाली पर विचार करना होगा।

इस स्थिति में हमें स्वदेशी काउंटर-ड्रोन उद्योग पारिस्थितिकी तंत्र को तेज करने के साथ टिकाऊ रक्षा हेतु काउंटर-ड्रोन सिस्टम की प्रति-इकाई लागत को पाकिस्तानी हमलावर ड्रोन की लागत के बराबर या उससे कम करना होगा। भारतीय खुफिया एजेंसियों को यह गहनता से आंकना होगा कि पावरअस के आने से पाकिस्तान की इलेक्ट्रानिक युद्ध प्रतिरोध, स्वायत्त समन्वय और बड़े पैमाने पर कम लागत वाले ड्रोन उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी। खतरे के इस पुनर्मूल्यांकन के अनुरूप काउंटर-ड्रोन खरीद के तकनीकी मानकों और बजट आवंटन को तय करना होगा।

ट्रंप-शैली की सौदेबाजी कूटनीति में मित्र और शत्रु की सीमाएं धुंधली हैं, केवल मुनाफा और दबाव स्थिर हैं, इसलिए कूटनीतिक माध्यम से वाशिंगटन को साफ बताना होगा कि भारत 'एक ही कंपनी द्वारा भारत और पाकिस्तान दोनों को हथियार बेचने' को सामान्य नहीं मान सकता। यह केवल तकनीकी मुद्दा नहीं, रणनीतिक विश्वास का विषय है। यदि अमेरिका वास्तव में भारत को 'प्रमुख रक्षा साझेदार' मानता है, तो उसे अपनी कंपनियों को व्यापारिक स्वतंत्रता के नाम पर भारत के दुश्मन को भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो सकने वाली तकनीक हस्तांतरित नहीं करनी चाहिए। (ईआरसी)

एक साथ कई मोर्चों पर घिरा पाकिस्तान



प्रेम प्रकाश
वरिष्ठ पत्रकार

सितंबर से शुरू हुआ घटनाक्रम अब भारत पाकिस्तान संबंधों को और संवेदनशील मोड़ पर ले जाता दिख रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कश्मीर के साथ सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भारत की ओर से पाकिस्तान के हिस्से के पानी को रोकने या मोड़ने की कोशिश को 'एक आफ वार' माना जाएगा। इसके जवाब में भारत ने सीमा पार आतंकवाद को केंद्र में रखते हुए साफ किया कि आतंकवाद को सामान्य बनाने या उसके परिणामों से बचने की कोशिश स्वीकार नहीं की जाएगी और भारत को अपनी सुरक्षा के लिए बचाव का अधिकार है। इन घटनाक्रमों को पाकिस्तान के भीतरी हालात से अलग करके भी नहीं देखा जा सकता।

दरअसल आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान की सरकार अब भी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सहायता पर निर्भर है। वहां राजनीतिक मोर्चे पर भी अस्थिरता और गतिरोध है। महंगाई और ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर असंतोष भी सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है। ऐसे में भारत के साथ टकराव का मुद्दा पाकिस्तान की घरेलू राजनीति में कितना उपयोगी बनाया जा रहा है, यह अलग विश्लेषण का विषय है। अलबत्ता इतना स्पष्ट है कि कश्मीर, पानी और भारत विरोधी सुरक्षा विमर्श वहां की राजनीति में लंबे समय से प्रभावी मुद्दे रहे हैं। जब सरकार आर्थिक दबाव, राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा चुनौतियों से एक साथ जूझ रही हो, तब बाहरी खतरे का विमर्श घरेलू असंतोष से ध्यान हटाने और राजनीतिक समर्थन जुटाने का माध्यम बन सकता है। यही वह संदर्भ है जिसमें भारत के साथ बढ़ते टकराव के साथ आतंकवाद का सवाल भी फिर केंद्र में आता है।

इसी कड़ी में मसूद अजहर का मामला खासा अहम है। सितंबर में पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उसकी गिरफ्तारी की सूचना पर इनाम 50 लाख से बढ़ाकर 70 लाख पाकिस्तानी रुपये किया। इसी महीने होने वाली एफएटीएफ बैठक से पहले उठाए गए इस कदम को भारत ने दिखावे की कार्रवाई करार दिया। यह मामला इसलिए गंभीर है, क्योंकि वह जैश ए मोहम्मद से जुड़ा वह नाम है जिस पर भारत लंबे समय से सवाल उठाता रहा है और जिसे संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध व्यवस्था के तहत भी सूचीबद्ध किया जा चुका है। हाल में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच आतंक विरोधी संवाद में दोनों देशों ने आइएसआइएस खुरासान, अल कायदा, तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे संगठनों के खिलाफ सहयोग और आतंकी नेटवर्क को बाधित करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान के सामने आतंकवाद का प्रश्न बहुस्तरीय है।

कश्मीर पर पाकिस्तान की कूटनीतिक सक्रियता, सिंधु जल संधि को लेकर उसकी कठोर भाषा और आतंकवाद के सवाल पर भारत की प्रतिक्रिया एक ऐसे त्रिकोण की ओर संकेत करती है, जिसमें पानी, सुरक्षा और कश्मीर एक-दूसरे से जुड़े पेचीदा मुद्दे बनते जा रहे हैं। वैसे पाकिस्तान की चुनौतियां भारत के साथ तनाव तक सीमित नहीं हैं। अफगानिस्तान के साथ बढ़ता टकराव, आर्थिक दबाव और घरेलू राजनीतिक अस्थिरता भी उसके लिए गंभीर संकट बने हुए हैं। ऐसे में पाकिस्तान के चुनौती सिर्फ इन सुरक्षा संकटों से निपटने की नहीं, बल्कि आतंक के खिलाफ अपने दावों को ठोस कार्रवाई में बदलने की भी है। आतंकवाद के खिलाफ दावों और जमीनी कार्रवाई के बीच की खाई पाकिस्तान की नीतियों की पोल खोल सकती है, जबकि आर्थिक बदहाली और घरेलू राजनीतिक अस्थिरता इन संकटों से उबरने की उसकी गुंजाइश और सीमित कर सकती है।

खरी-खरी

गरबा या नारेबाजी

निमंत गुप्त

नवरात्र आ गए। मेरे मोहल्ले में सुबह से लाउडस्पीकर पर देवी गीत चल रहे हैं और दिनभर आंदोलन स्थल पर इन्कलाबी गीत बजेंगे। दोनों की आवाज इतनी तीव्र है कि बीच वाले घर में पता ही नहीं चल रहा- गरबा करें या नारेबाजी। दोनों काम ही जरूरी हैं। धर्म भी चलता रहे और सरोकारी होने का पता भी। धर्म और आंदोलन दो समानांतर कर्म हैं, जो एक-दूसरे को काटते नहीं।

घर-घर घट स्थापित हो गए। कलश पर नारियल। व्रत शुरू हो गए। मेरी आंटी ने कहा- बेटा, मैं दिन में फलाहार करूंगी। दो घंटे बाद कुटटू की पकौड़ी, साबूदाने की खिचड़ी, व्रत वाले चिप्स और व्रत वाली कोल्ड ड्रिंक लेकर आईं। मैंने कहा- आंटी, ये व्रत है या फूड फेस्टिवल? बोलीं- धर्म में संयम चाहिए, पर स्वाद में समझौता नहीं।

उधर आंदोलन वाले भी सक्रिय हो गए। उन्होंने भी अपना व्रत शुरू किया है- न्याय मिलने तक प्रदर्शन। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां फलाहार नहीं, कैमरा-हार है। हर घंटे एक रील खानी है, नहीं तो कमजोरी आ जाती है। वहीं दुकानदारों की लाटरी लग गई। सुबह ग्राहक आता है- भैया, नवरात्र की चुनरी दिखाओ। शाम को दूसरा ग्राहक- भैया, प्रदर्शन में जाने के लिए काली टी-शर्ट दिखाओ। दुकानदार कन्फ्यूज है कि एक ही दिन में श्रद्धा और आक्रोश दोनों बेचना पड़ रहा है। यही धंधे का दर्शन है।

फिर आया शुभ मुहूर्त। मेरे शहर में एक दिन में हजारों वाहन बिक गए। शौकस वाला बता रहा था- सर, इस बार स्कूटी लेने वाले भी कह रहे हैं कि गाड़ी पर जय माता दी लिख देना, और पीछे छोटा स्टिकर- आई सपोर्ट प्रोटेस्ट। धर्म आगे, आंदोलन पीछे, दोनों एक ही गाड़ी पर सवार।

इस नवरात्र में दो लाइनें समानांतर चल रही हैं। एक लाइन में लोग देवी से मांग रहे हैं, हे माता, देश में शांति रखना। दूसरी लाइन में लोग माइक पर मांग रहे हैं- हे मोडिया, मेरी रील पर शांति से लाइक रखना। बीच में आम आदमी- एक हाथ में कलश, दूसरे हाथ में प्लेकार्ड, जेब में गाड़ी की चाबी और दिमाग में एक ही सवाल कि वह व्रत रखे या प्रदर्शन में शामिल हो या फिर दोनों में?

इस नवरात्र यही यक्ष प्रश्न सबके सामने है।

एक्स पोस्ट



अमेरिका रूस से ईंधन आयात करने पर भारत को दंडित करता है और ऐसा करने वाले अन्य देशों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी देता है और फिर ट्रंप बढ़ी ढीठता के साथ एलान करते हैं कि अमेरिका भी रूस से तेल खरीदेगा।

निकोलस क्रिस्टोफ@NickKristof

अन्ना आंदोलन से जुड़े लोग भी दावा करते थे कि भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, पर सत्ता में आए तो खुद भ्रष्ट हो गए। अब वैसी ही कहानी दोहराई जा रही है। इस सबमें जनता पिटती है और कुछ महत्वाकांक्षी लोगों का राजनीतिक सफर शुरू हो जाता है। वे लोग कब किससे हाथ मिल लेंगे, यह जनता को पता ही नहीं होता। ऋचा अनिरुद्ध@richaanirudh

एसआइआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च करने वाली कांग्रेस यह समझे कि मामला अदालत में विचाराधीन है तो सीजेआइ से मिलने संभव नहीं। अदालतें पर दबाव बनाने का प्रयोजन क्या है? हमारी अदालतें राजनीतिक बहस का अड्डा नहीं हैं। राजनीति करना राजनीतिक दलों का काम है। अदालतों को इसमें घसीटना सही नहीं है।

ब्रज मोहन सिंह@brajjourno



जयकृष्ण वाजपेयी
राज्य ब्यूरो प्रमुख, बंगाल

बंगाल में दुर्गापूजा केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक अस्मिता और सामूहिक उत्सव का विराट रूप है। यहां मां दुर्गा का आगमन घर-घर की भावना से लेकर शहर की अर्थव्यवस्था तक को प्रभावित करता है। ऐसे में महालया के दिन कोलकाता के इंडोर गार्डेंस में आयोजित 'उमा (मां दुर्गा) आगमनी' को महज एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम मानना इसकी व्यापकता को सीमित करना होगा। यह आयोजन बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद दुर्गोत्सव की सरकारी परिकल्पना में आए बदलाव का संकेत भी है। ढाकियों की सामूहिक थाप, हजारों ड्रोनों के माध्यम से आकाश में उकेरी गईं देवी दुर्गा की आकृतियां और विभिन्न जिलों की लोकसंस्कृति का प्रदर्शन- इन सबके बीच नई सरकार ने अपनी सांस्कृतिक प्राथमिकताओं को सार्वजनिक मंच पर प्रस्तुत किया।

बंगाल डायरी

दुर्गोत्सव का नया अध्याय

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा सरकार का यह पहला दुर्गोत्सव है। पिछले वर्षों में पूर्ववर्ती ममता बनर्जी सरकार की ओर से दुर्गापूजा को अनुदान, बिजली बिल में छूट, अग्निशमन संबंधी शुल्क में राहत और विजयदशमी के बाद रेड रोड पर दुर्गापूजा कार्निवल के आयोजन पर विशेष जोर दिया जाता रहा। नई सरकार ने उत्सव के औपचारिक उद्घाटन को ही नए स्वरूप में प्रस्तुत किया।

इस बदलाव का महत्व केवल धार्मिक समय-निर्धारण तक सीमित नहीं है। यह उस सांस्कृतिक दृष्टिकोण को सामने लाता है, जिसमें सरकार दुर्गोत्सव की पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं को सार्वजनिक उत्सव की पहचान से जोड़ना चाहती है। हालांकि, इससे पहले की सरकार के सांस्कृतिक योगदान को नकारना भी उचित नहीं होगा। ईडन के आयोजन की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि तीन हजार ढाकियों का एक साथ वादन और उसे गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड्स में स्थान मिलना रहा।



कोलकाता में महालया के अवसर पर आयोजित भव्य कार्यक्रम। फाइल

यहां एक तथ्य और महत्वपूर्ण है। वर्ष 2021 में कोलकाता की दुर्गापूजा को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में स्थान मिला था। यूनेस्को ने इसे धर्म, कला, शिल्प और सार्वजनिक सहभागिता के अनूठे मेल के रूप में दर्ज किया। यानी बंगाल की दुर्गापूजा की अंतरराष्ट्रीय पहचान किसी एक सरकार के आयोजन से नहीं, बल्कि पीढ़ियों से विकसित हुई सामुदायिक परंपरा से बनी है। नई सरकार के सामने चुनौती इस विरासत को राजनीतिक प्रदर्शन से आगे ले जाकर वैश्विक सांस्कृतिक पहचान और पर्यटन की स्थायी ताकत बनाने की है।

मुख्यमंत्री ने ईडन के मंच से घोषणा की कि राज्य में पिछले वर्ष की लगभग 45 हजार दुर्गापूजाओं की तुलना में इस वर्ष 12,400 नई पूजाओं को अनुमति दी गई है। इससे कुल संख्या 57,400 हो जाती है। सरकार ने नई समितियों को भी एक लाख रुपये के अनुदान देने की बात कही है। नई पूजाओं को अनुमति देना केवल धार्मिक आयोजन बढ़ने का संकेत नहीं है। इसके साथ स्थानीय कलाकारों, मूर्तिकारों, कारीगरों, बिजलीकर्मियों, सजावट करने वालों, परिवहनकर्मियों और छोटे कारोबारियों के लिए आर्थिक अवसर भी जुड़ते हैं। दुर्गापूजा बंगाल की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए सरकारी नीति की सफलता इस बात से भी मापी जानी चाहिए कि आयोजन से कारीगरों को कितना लाभ मिला व सांस्कृतिक पर्यटन को कितना विस्तार मिला।

ईडन के आयोजन ने राजनीतिक बहस को भी जन्म दिया है। तृणमूल कांग्रेस की ओर से इस कार्यक्रम पर लगभग 167 करोड़ रुपये खर्च होने का आरोप लगाया गया है। यह वही नेता हैं, जो ममता के शासनकाल में रेड रोड पर विजयदशमी के बाद होने वाले कार्निवल के खर्च पर कभी एक शब्द नहीं बोलते थे। अब वे महालया पर हुए आयोजन के खर्च पर सवाल उठा रहे हैं। महालया पर विशाल उद्घाटन और विसर्जन के बाद कलाकारों तथा पूजा समितियों को मंच देने वाले कार्निवल की भूमिका अलग-अलग हो सकती है। दोनों आयोजनों को प्रतिस्पर्धी बनाने के बजाय उनके सांस्कृतिक उद्देश्यों को स्पष्ट करना अधिक उपयोगी होगा।

'उमा आगमनी' नई सरकार की सांस्कृतिक प्राथमिकताओं का पहला बड़ा सार्वजनिक प्रदर्शन है। इसने दुर्गोत्सव के उद्घाटन को नई दृश्यता दी और परंपरा के साथ आधुनिक तकनीक के मेल की संभावना दिखाई। मगर किसी सरकार की सांस्कृतिक नीति का मूल्यांकन पूरे वर्ष किए गए कार्यों से होगा। यदि यह पहल स्थानीय कला को स्थायी बाजार, बंगाल के जिलों को पर्यटन के नए अवसर, आयोजकों को सरल प्रशासन और जनता को खर्च का पारदर्शी हिसाब देती है, तो इसका प्रभाव ईडन की सीमाओं से कहीं आगे जाएगा। अंततः दुर्गोत्सव की सबसे बड़ी उपलब्धि कोई रिकार्ड, ड्रोन शो या भव्य मंच नहीं, बल्कि वह सांस्कृतिक विरासत है जो पीढ़ियों को जोड़ती है। नई सरकार के लिए असली चुनौती उसी विरासत की सम्मान, अवसर और जवाबदेही के साथ आगे बढ़ाने की है।

जागरण जनमत कल का परिणाम

आराधना मिश्रा के प्रदेश अध्यक्ष बनने से यूपी कांग्रेस में गुटबाजी बढ़ती दिखी है?



रविवार को आए प्रतिक्रिया में

आज का सवाल

क्या दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर के बजाय तीन अन्य स्थानों को चिह्नित किए जाने का फैसला सही है?

परिणाम जागरण डॉटकॉम संस्करण के पाठकों का मत है

जनपथ

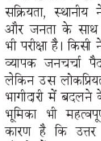
दिखे सगाधा मस्क से पर भारत से रश्क,
हर उन्नति पर देश की दिखे बहादे अश्क।
दिखे बहादे अश्क बिगड़ती इनकी बानी,
एलन मस्क से प्यार और दुश्मन अंबानी!
उद्यमियों का नाम रोज जब करते स्याप,
ट्रंप-मस्क के साथ किसलिए दिखे समाप?

-ओम प्रकाश तिवारी

मंथन

राजनीति में संगठन की भूमिका

जनादेश का मूल मंत्र यही है कि जो राजनीतिक दल अपने संगठन को मजबूत बनाए रखेगा, वह मतदाताओं के अधिकतम निकट होगा। लिहाजा लोकतंत्र में संगठन की भूमिका महत्वपूर्ण है



अनंत अमित
राजनीतिक विश्लेषक

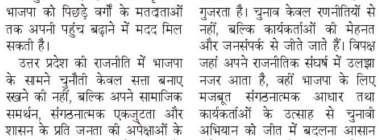
राजनीति में चुनाव केवल नेताओं की लोकप्रियता, जातीय समीकरणों, नारों और जनसभाओं का मुकाबला नहीं है। यह राजनीतिक दलों के संगठनात्मक ढांचे, कार्यकर्ताओं की सक्रियता, स्थानीय नेतृत्व के समन्वय और जनता के साथ निरंतर संवाद की भी परीक्षा है। किसी नेता की लोकप्रियता व्यापक जनचर्चा पैदा कर सकती है, लेकिन उस लोकप्रियता को लोकतांत्रिक भागीदारी में बदलने के लिए संगठन की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के चुनावी संदर्भ में बूथ स्तर से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक की कार्यप्रणाली पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में विधानसभा चुनाव की सफलता के लिए किसी भी राजनीतिक दल के लिए बूथ स्तर पर मजबूत संगठन की अहम भूमिका होती है। प्रदेश की सत्ता पर काबिज भाजपा और विपक्षी दल के रूप में समाजवादी पार्टी एवं कांग्रेस सहित अन्य दलों में जो इसे सबसे अधिक साध लेगा, सत्ता का मार्ग उसके लिए ही प्रशस्त होगा। यही जनादेश का मूल मंत्र माना जाता है।

चुनावी राजनीति में केवल बड़े नेताओं की सभाएं और आकर्षक घोषणाएं पर्याप्त नहीं होतीं। मतदाताओं तक नियमित पहुंच, स्थानीय समस्याओं का समाधान और बूथ स्तर पर प्रभावी समन्वय भी जरूरी है। यदि भाजपा इन मोर्चों पर अपनी पकड़ मजबूत करती है, तो उसे चुनावी मुकाबले में लाभ मिल सकता है। विधानसभा चुनाव 2027 की सियासी बिसात पर भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने कानून-व्यवस्था और बुनियादी ढांचे में बदलाव का दावा किया है। एक्सप्रेसवे, रेल नेटवर्क, हवाई अड्डों और अन्य सुविधाओं के विस्तार को प्रदेश की आर्थिक प्रगति से जोड़ा। विधानसभा चुनाव में कानून-व्यवस्था, रोजगार, किसानों की आय, महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण रहने की संभावना है। भाजपा अपने शासनकाल की उपलब्धियों को सामने रखेगी, वहीं विपक्ष सरकार के दावों और जमीनी परिस्थितियों पर सवाल उठाएगा।

इस लिहाज से चुनावी मुकाबला केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रहेगा। मतदाता यह भी देखेंगे कि विकास का लाभ किस हद तक उन तक पहुंचा है और स्थानीय स्तर पर उनकी समस्याओं का कितना समाधान हुआ है। संगठनात्मक तैयारियों के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने विपक्षी दलों को लेकर भी राजनीतिक बयान दिए हैं। दावा किया कि समाजवादी पार्टी के कई मौजूदा विधायक भाजपा के संपर्क में हैं और पार्टी में शामिल होने के इच्छुक हैं। यदि यह दावा भविष्य में ठोस राजनीतिक घटनाक्रम में बदलता है, तो इसका असर प्रदेश की चुनावी राजनीति पर पड़ सकता है। दल-बदल की संभावनाएं चर्चा का विषय बन सकती हैं, लेकिन किसी भी दल की वास्तविक ताकत का निर्धारण केवल नेताओं के आने-जाने से नहीं होता।

संगठन की स्वीकार्यता, उम्मीदवारों की विश्वसनीयता और मतदाताओं का समर्थन भी निर्णायक होते हैं। पंकज चौधरी अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं और उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण मानी जाती है। भाजपा उन्हें पिछड़े वर्गों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने और समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग आधारित राजनीतिक प्रभाव का मुकाबला करने के एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर रही है। उनके नेतृत्व से भाजपा को पिछड़े वर्गों के मतदाताओं तक अपनी पहुंच बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा के सामने चुनौती केवल सत्ता बनाए रखने की नहीं, बल्कि अपने सामाजिक समर्थन, संगठनात्मक एकजुटता और शासन के प्रति जनता की अपेक्षाओं के बीच संतुलन स्थापित करने की भी है। विधानसभा चुनाव के संदर्भ में रोजगार, किसानों की आय, महंगाई, सामाजिक समीकरण, स्थानीय नेतृत्व और विपक्ष की रणनीति जैसे मुद्दे राजनीतिक विमर्श के केंद्र में रह सकते हैं।



मतदाताओं को बूथ तक लाने में कार्यकर्ताओं का अहम योगदान माना जाता है। फाइल

राजनीति में चुनावी सफलता का रास्ता कार्यकर्ताओं के बीच से होकर गुजरता है। चुनाव केवल रणनीतियों से नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनसंपर्क से जीते जाते हैं। विपक्ष जहां अपने राजनीतिक संघर्ष में उलझा नजर आता है, वहीं भाजपा के लिए मजबूत संगठनात्मक आधार तथा कार्यकर्ताओं के उत्साह से चुनावी अभियान को जीत में बदलना आसान होने की संभावना है। हालांकि, नेतृत्व को वास्तविक कसौटी दावों और रणनीतियों में नहीं, बल्कि चुनावी नतीजों में होगी। ऐसे में प्रदेश संगठन नेतृत्व की असली परीक्षा भी आगामी विधानसभा चुनाव में ही होगी।

इंडियन गैस एक्सचेंज के आईपीओ को मिली मंजूरी

नई दिल्ली: प्राकृतिक गैस की आनलाइन ट्रेडिंग से जुड़े प्लेटफार्म इंडियन गैस एक्सचेंज लिमिटेड (आइजीएक्स) के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आइपीओ) को सोमवार को सेबी से मंजूरी मिल गई। मसौदा दस्तावेजों के अनुसार, यह पूरा आइपीओ आफर फार सेल यानी प्रमोटर शेयरों की बिक्री पर आधारित होगा और इसमें 1.67 करोड़ इक्विटी शेयर बिक्री के लिए पेश किए जाएंगे। आइजीएक्स में इंडिया एनर्जी एक्सचेंज की 47 प्रतिशत हिस्सेदारी है। (भा.)



नई चार मीटर से कम लंबाई वाली एसयूवी 'बिजर' को भारत में स्थानीय बाजार के लिए विकसित और डिजाइन किया गया है। इसमें वैश्विक बाजारों में उतरने की भी क्षमता है।
- फ्रांस्वा प्रोवोस्ट, सीईओ, रेनो समूह

सेंसेक्स	71,924.68 ▼ 547.65	निफ्टी	22,363.35 ▼ 157.10	सोना प्रति दस ग्राम	₹1,53,000 ▼ ₹1,400	चांदी प्रति किलो ग्राम	₹2,26,500 ▼ ₹2,000	डालर	₹95.78 ▼ ₹0.93	क्रूड प्रति बैरल	$105.8

एक नजर में

ईयू को 5,841 टन चीनी निर्यात को दी मंजूरी

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने 2026-27 के लिए टैरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) यूरोपीय संघ (ईयू) को 5,841 टन चीनी निर्यात करने की मंजूरी दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की ओर से जारी एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है। डीजीएफटी की ओर से जारी एक अन्य अधिसूचना के अनुसार, खरपतवार नाशक में इस्तेमाल होने वाले ग्लुफोसिनेट और इसके साल्ट्स पर न्यूनतम आयात मूल्य को 12 अप्रैल, 2027 तक बढ़ा दिया गया है। (भा.)

एचसीएल टेक ने एंथ्रोपिक से की वैश्विक साझेदारी

नई दिल्ली: एचसीएल टेक ने सोमवार को अमेरिका की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) कंपनी एंथ्रोपिक के साथ एक वैश्विक साझेदारी की घोषणा की। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर 2026) के दौरान कंपनी का शुद्ध लाभ 21.18 प्रतिशत बढ़कर 5,132 करोड़ रुपये रहा है। इसी तरह, कंपनी का संचालन राजस्व 11.5 प्रतिशत बढ़कर 35,620 करोड़ रुपये हो गया है। तिमाही के दौरान कंपनी ने 6,450 कर्मचारी जोड़े हैं और कुल कर्मचारियों की संख्या 2,30,339 हो गई है। (भा.)

2026 में 7.9 प्रतिशत बढ़ेगी भारत में स्टील की मांग

नई दिल्ली: उद्योग संगठन वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने सोमवार को कहा कि भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्रमुख स्टील बाजार बना हुआ है और 2026 में इसकी मांग 7.9 प्रतिशत बढ़कर 17.24 करोड़ टन होने का अनुमान है। उद्योग संगठन ने ताजा परिदृश्य रिपोर्ट में कहा कि वर्ष 2027 में देश में स्टील की मांग आठ प्रतिशत बढ़कर 18.62 करोड़ टन होने की उम्मीद है। 2026 में वैश्विक स्टील मांग 172.2 करोड़ टन पर स्थिर रहने और 2027 में 1.7 प्रतिशत बढ़कर 175.2 करोड़ टन पहुंचने का अनुमान है। (भा.)

प्याज ने बढ़ाई महंगाई, सितंबर में 5.54% रही

लगातार चौथे महीने चार प्रतिशत से ज्यादा रही वृद्धि दर, खाद्य वस्तुओं की महंगाई 7.74 प्रतिशत रही

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: प्याज, लहसुन, नींबू और अदरक की कीमतों में आए भारी उछाल से सितंबर में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5.54 प्रतिशत स्तर रही है। यह लगातार चौथा महीना रहा है, जब खुदरा महंगाई दर चार प्रतिशत से ऊपर रही। आरबीआइ ने खुदरा महंगाई दर की अधिकतम सीमा छह प्रतिशत रखी हुई है, लेकिन चार प्रतिशत के बाद इसे चिंताजनक माना जाता है। इसी साल अगस्त में खुदरा महंगाई दर 4.83 प्रतिशत थी।

राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) की ओर से जारी डाटा के अनुसार, सितंबर में खाद्य वस्तुओं की खुदरा महंगाई दर 7.74 प्रतिशत रही है जो इसी वर्ष अगस्त में 5.97 प्रतिशत थी। आंकड़ों के मुताबिक, पिछले महीने जिन पांच वस्तुओं की महंगाई दर सबसे अधिक बढ़ी है उसमें प्याज (108.09 प्रतिशत), चांदी के आभूषण (87.8 प्रतिशत), अदरक (62.85 प्रतिशत), लहसुन (54.62 प्रतिशत) और नींबू (36.41 प्रतिशत) शामिल हैं। हालांकि, इनमें से प्याज को छोड़कर अन्य सभी उत्पादों की घरेलू खपत कम ही होती है। दूसरी तरफ, सितंबर में आलू के खुदरा मूल्य में पिछले वर्ष के समान महीने के मुकाबले 11.50 प्रतिशत, टमाटर में 8.6 प्रतिशत, भिंडी में 4.5 प्रतिशत, नारियल में 4.0 प्रतिशत तो मोटर कार व जीप की कीमतों में 4.5 प्रतिशत की गिरावट रही है। पिछले महीने ग्रामीण क्षेत्रों में खुदरा महंगाई 6.08 प्रतिशत तो शहरी क्षेत्रों में 4.88 प्रतिशत रही है। जनवरी में नया आधार वर्ष 2024 लागू होने के बाद सितंबर में खुदरा महंगाई की दर सबसे अधिक रही है।

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या क्लिक करें jagran.com

फिर रेपो रेट बढ़ा सकता है आरबीआइ

आर्थिक जानकारों का कहना है कि अगले दो माह में भी खुदरा महंगाई दर में बढ़ोतरी का ऐसा ही सिलसिला जारी रहा तो दिसंबर में आरबीआइ एक बार फिर रेपो रेट को बढ़ा सकता है। कुछ दिन पहले ही आरबीआइ ने रेपो रेट में 25 आधार अंक की वृद्धि की है। आरबीआइ ने चालू वित्त वर्ष के लिए औसत खुदरा महंगाई के अनुमान को भी बढ़ाकर 5.2 प्रतिशत कर दिया है। पहले केंद्रीय बैंक ने औसत खुदरा महंगाई पांच प्रतिशत रहने का अनुमान जताया था। वैश्विक हालात और कच्चे तेल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए इस साल महंगाई दर छह प्रतिशत के पार जाने की आशंका है।

- आरबीआइ की अधिकतम सीमा छह प्रतिशत के करीब पहुंची खुदरा महंगाई
- ग्रामीण क्षेत्रों में 6.08% तो शहरी क्षेत्रों में 4.88% रही महंगाई की दर

शीर्ष राज्यों में महंगाई (%में)	
तमिलनाडु	6.81
ओडिशा	6.70
मध्य प्रदेश	6.68
तेलंगाना	6.64
आंध्र प्रदेश	6.29

वस्तुवार वृद्धि (%में)	
फूड व बेवरेज	7.36
कपड़े व फुटवियर	4.0
ट्रांसपोर्ट	5.0
शिक्षा सेवा	3.93
सूचना व संचार	2.44
पर्सनल केयर व सामाजिक सुरक्षा	13.75
स्वास्थ्य सेवा	1.40
बिजली, गैस व अन्य ईंधन	2.74



आरबीआइ के कदमों का दिखा असर, 93 पैसे मजबूत हुआ भारतीय रुपया

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: डालर के मुकाबले रुपये में आ रही लगातार गिरावट को रोकने के लिए आरबीआइ की ओर से हाल में उठाए गए कदमों का असर दिखने लगा है। सोमवार को डालर के मुकाबले रुपये में 93 पैसे की मजबूती दर्ज की गई और यह 95.78 के स्तर पर बंद हुआ। बीते शुक्रवार को एक डालर का मूल्य 96.96 रुपये तक चला गया था। वर्ष 2026 में अब तक डालर के मुकाबले रुपये के मूल्य में करीब सात प्रतिशत की गिरावट आई है जिस कारण आयातित सामान की कीमत बढ़ती जा रही है। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़ने से रुपये में कमजोरी आती है क्योंकि कच्चे तेल की खरीदने में अधिक डालर खर्च होने लगते हैं।

आरबीआइ ने रुपये की गिरावट रोकने के लिए बीते शनिवार को कई उपायों की घोषणा की थी। इसके तहत सोमवार को तीन सरकारी तेल विपणन कंपनियों को सीधे डालर मुहैया कराने के लिए स्पेशल विंडो की शुरुआत की।

इसके अलावा आरबीआइ ने बैंकों को पहले की तुलना में अधिक विदेशी मुद्रा जोखिम रिजर्व रखने के लिए कहा है। साथ ही बैंकों के लिए नकदी आरक्षित अनुपात को 90 प्रतिशत से घटाकर 99 प्रतिशत कर दिया है। जानकारों का कहना है कि आरबीआइ के इन कदमों से रुपये में फिलहाल तो मजबूती दिख रही है, लेकिन स्थायी मजबूती के लिए विदेशी संस्थागत निवेश को बढ़ाना होगा।

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में अमेरिकी डालर के मुकाबले रुपया 95.61 के स्तर पर खुला। दिनभर के कारोबार के दौरान यह 95.57 के उच्च स्तर और 95.96 के निचले स्तर तक पहुंचा। अंत में यह 95.78 के स्तर पर बंद हुआ, जो पिछले बंद से 93 पैसे अधिक है। दो अप्रैल के बाद भारतीय रुपये में यह अब तक की सबसे अधिक एकदिवसीय तेजी है।



- अमेरिकी डालर के मुकाबले 95.78 पर बंद हुई भारतीय मुद्रा
- 2026 में अब तक रुपये में सात प्रतिशत की गिरावट आई

कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से 548 अंक लुढ़का सेंसेक्स

मुंबई, भ्रेट: कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और विदेशी निवेशकों की बिकवाली के चलते सोमवार को भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। बीएसई का मानक सूचकांक सेंसेक्स 547.65 अंक गिरकर 71,924.68 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 796.23 अंक लुढ़ककर 71,676.10 पर पहुंचा था। इसी तरह, एनएसई का निफ्टी 157.10 अंक गिरकर 22,363.35 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स में आइटीसी के शेयरों में सबसे अधिक 3.23 प्रतिशत की गिरावट रही। इसके अलावा, टेक महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, लार्सन एंड टुब्रो, एसबीआइ और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के शेयर भी गिरकर बंद हुए। दूसरी ओर, भारत इलेक्ट्रानिक्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बैंक और एचसीएल टेक में बढ़त रही। बीएसई स्मालकैप सेलेक्ट में 1.65 प्रतिशत और मिडकैप सेलेक्ट में 0.66 प्रतिशत की तेजी रही। ब्रेंट क्रूड 1.14 प्रतिशत उछलकर 105.8 डालर प्रति बैरल पर पहुंच गया।

71,924 अंक पर बंद हुआ बीएसई सूचकांक

157 अंक गिरकर 22,363 पर बंद हुआ एनएसई निफ्टी

सोना-चांदी का मूल्य घटा

वैश्विक बाजारों में कमजोरी के चलते सोमवार को भारतीय सराफा बाजारों में गिरावट का दौर रहा। आल इंडिया सराफा एसोसिएशन के अनुसार, दिल्ली में सोने का मूल्य 1,400 रुपये घटकर 1,53 लाख रुपये प्रति दस ग्राम पर आ गया। इसी तरह, चांदी दो हजार रुपये घटकर 2,26,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई।

सितंबर माह में इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश 31 प्रतिशत बढ़ा

नई दिल्ली, भ्रेट: शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआइ) की बिकवाली के बावजूद निवेशकों ने मिड-कैप और स्माल-कैप फंड में निवेश जारी रखा है। इससे सितंबर में इक्विटी म्यूचुअल फंड योजनाओं में शुद्ध निवेश मासिक आधार पर 31 प्रतिशत बढ़कर 38,306 करोड़ रुपये रहा है। अगस्त में इन योजनाओं में 29,329 करोड़ रुपये का निवेश हुआ था।

एसोसिएशन आफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफआइ) की ओर से सौमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले महीने अप्रैल 2026 के बाद सबसे अधिक निवेश हुआ है। अप्रैल में इक्विटी योजनाओं में 38,440 करोड़ रुपये आए थे। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआइपी) के जरिये मासिक निवेश भी सितंबर में 32,490 करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। अगस्त में यह 32,297 करोड़ रुपये था।

स्माल-कैप फंड में सबसे अधिक 9,039 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश आया, जो अगस्त के 7,973 करोड़ रुपये से ज्यादा था। मिड-कैप फंड में निवेश अगस्त के 6,989 करोड़ रुपये से बढ़कर सितंबर में 7,835 करोड़ रुपये रहा। दोनों श्रेणियों में कुल शुद्ध इक्विटी निवेश का करीब 44 प्रतिशत आया। फ्लेक्सी-कैप फंड में 6,702 करोड़ रुपये का निवेश हुआ। लार्ज-कैप फंड में तीन महीने बाद पहली बार शुद्ध निवेश सकारात्मक होकर 859 करोड़ रुपये रहा है।

गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) में निवेश अगस्त के 2,597 करोड़ रुपये से बढ़कर सितंबर में 4,451 करोड़ रुपये रहा। सिल्वर ईटीएफ में 1,974 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश आया। पिछले महीने इक्विटी के पांच नए फंड आफर (एनएफओ) ने 998 करोड़ रुपये जुटाए।

डेट म्यूचुअल फंड से 1.83 लाख करोड़ की निकासी : डाटा के अनुसार, सितंबर में डेट म्यूचुअल फंड से 1.83 लाख करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी हुई जो अगस्त में 8,127 करोड़ रुपये थी। उद्योग से कुल शुद्ध निकासी 1.33 लाख करोड़ रुपये रही, जबकि अगस्त में 41,354 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश हुआ था। सितंबर अंत में उद्योग का एयूएम 82.64 लाख करोड़ रुपये रहा, जो अगस्त के अंत में 87.07 लाख करोड़ रुपये था।

38,306 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश हुआ पिछले महीने में

32,490 करोड़ के रिकार्ड उच्च स्तर पर पहुंचा एसआइपी निवेश



चार कंपनियों ने तय किया आइपीओ का शेयर मूल्य

नई दिल्ली, भ्रेट: चार कंपनियों- जेटवर्क मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेज लिमिटेड, टोन्वो इमेजिंग, बंगीगियोली ट्रांसमिशंस, सहजानंद मेडिकल टेक्नोलाजिस लिमिटेड ने अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आइपीओ) का शेयर मूल्य तय कर दिया है। चारों निर्गम सब्सक्रिप्शन के लिए 15 अक्टूबर को खुलेंगे। जेटवर्क मैन्युफैक्चरिंग ने अपने 5,012 करोड़ रुपये के आइपीओ का शेयर मूल्य 143- 151 रुपये प्रति इकाई तय किया है। बिजली ट्रांसमिशन उपकरण निर्माता बंगीगियोली ट्रांसमिशंस के 2,534 करोड़ रुपये का आइपीओ का शेयर मूल्य 558-586 रुपये प्रति इकाई तय किया गया है। डिफेंस इलेक्ट्रानियस निर्माता टोन्वो इमेजिंग आइपीओ के जरिये 853 करोड़ जुटाएगी और इसने शेयर मूल्य 665-700 रुपये प्रति इकाई तय किया है। सहजानंद मेडिकल के आइपीओ का आकार 475 करोड़ रुपये है और शेयर मूल्य 327-344 रुपये प्रति इकाई रखा गया है।

राष्ट्रीय फलक

गन्ना किसानों की शिकायतों के लिए एक सप्ताह में बनेगी उच्चस्तरीय समिति

नई दिल्ली, भ्रेट : केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के गन्ना किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए सप्ताहभर में उच्चस्तरीय संयुक्त समिति गठित करने का फैसला किया है। राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय मंत्रियों और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच करीब तीन घंटे चली बातचीत के बाद सोमवार को यह निर्णय लिया गया।

पूसा परिसर में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और खाद्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के किसानों के प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तृत चर्चा की। इसमें विभिन्न संगठनों के करीब 80-90 किसान शामिल हुए। किसानों ने उत्पादन लागत में बढ़ोतरी का हवाला देते हुए समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य (एमएसपी) 31 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 50 रुपये प्रति किलोग्राम करने की मांग भी की है। बैठक के बाद कृषि मंत्री ने कहा, अन्नदाता किसानों का शोषण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पारदर्शी व्यवस्था बनाना जरूरी है ताकि भविष्य में कोई भी मिल किसानों के अधिकारों का उल्लंघन न कर सके।

मंत्रियों ने एक सप्ताह के भीतर विशेष उच्चस्तरीय संयुक्त समिति गठित करने की घोषणा की। इसमें केंद्र और कर्नाटक तथा महाराष्ट्र सरकारों, किसान संगठनों और चीनी मिलों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ संबंधित विषयों के विशेषज्ञ और वैज्ञानी शामिल होंगे। समिति गन्ने की कटाई के समय, चीनी रिकवरी की जांच, आधुनिक लैब टेस्टिंग और वजन मापने की व्यवस्था की समीक्षा करेगी। तय समय में सरकार को सुझाव सौंपे जाएंगे। खाद्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि केंद्र राज्यों और किसानों के साथ तालमेल कर हर स्तर पर पारदर्शिता सुनिश्चित कर रहा है।

- केंद्रीय मंत्रियों और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत के बाद लिया गया निर्णय

पंजाब की मंडियों में भीगा धान, दाने पड़ने लगे काले

जागरण टीम, जालंधर

- राज्य की मंडियों में भीगने के कारण नहीं हुई धान की खरीद
- खुले में भीगे धान से आने लगी बदबू, किसान परेशान



<< पंजाब के फाजिल्का की अनाज मंडी में वर्षा से भीगे धान को बोरियों से निकालकर धूप में सुखाते मजदूर। रविवार को हुई वर्षा से मंडी में धान को काफी नुकसान हुआ था। जागरण

पंजाब में रविवार को हुई जोरदार वर्षा से मंडियों में हजारों क्विंटल धान भीग गया। बठिंडा, फाजिल्का, फरीदकोट, फिरोजपुर, मुक्तसर और गुरदासपुर में मंडियों में धान भीगने से काफी नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा असर फाजिल्का मंडी में पड़ा। यहां जलभराव की स्थिति से मंडी में पड़ी धान की सैकड़ों बोरियां भीग गईं। खुले में पड़े धान के दाने सोमवार को काले पड़ गए।

किसान दिन भर भीगे धान को बोरियां से निकालकर सुखाते नजर आए। राज्य में धान की खरीद सोमवार को लगभग ठप रही। नवांशहर के कांहगढ़ और होशियारपुर की मंडी में धान की खरीद नहीं हो पाई। वर्षा के कारण मंडी में अपनी फसल लेकर पहुंचे किसान अब दोहरी चिंता में हैं। एक तरफ वर्षा से फसल खराब होने का डर है तो दूसरी तरफ नमी की मात्रा अधिक होने के कारण सरकारी खरीद में देरी की आशंका बनी हुई है। किसानों के मुताबिक, सरकारी खरीद के लिए नमी की निर्धारित सीमा 17 प्रतिशत है। ऐसे में भीगी फसल को पहले सुखाना होगा। फिर उसकी नमी जांच के बाद ही खरीद की उम्मीद की जा सकती है। किसान मोहन लाल ने बताया कि वह पांच टाली धान लेकर मंडी में पहुंचे थे। इनमें से दो टालियों की फसल बिक चुकी है, जबकि बाकी फसल भीग गई है।

फाजिल्का में आढ़तिया एसोसिएशन के अध्यक्ष गोल्डी सचदेवा ने बताया कि वर्षा से मंडी में खुले में पड़ी धान की फसल को काफी नुकसान हुआ है। सड़क किनारे पड़ी ढेरियों के अंदर तक पानी पहुंच गया, जिससे कुछ जगह तो धान से बदबू आने लगी है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को जल्द सर्वे करवाकर नुकसान का आकलन करना चाहिए और रिपोर्ट सरकार को भेजनी चाहिए, ताकि प्रभावित किसानों को मुआवजा मिल सके। एसडीएम जुगराज सिंह ने कहा कि वर्षा से धान को हुए नुकसान के आकलन के लिए मार्केट कमेटी के सचिव की निगरानी में सर्वे टीम लगाई जाएगी। इसकी रिपोर्ट सरकार को भेज मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा।

जेनेटिकली माडिफाइड बासमती चावल की 'मंजूरी' पर विवाद

नई दिल्ली, भ्रेट : देश की कृषि परंपरा, बासमती की विशिष्ट पहचान और पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गहरी चिंता व्यक्त की गई है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई कि वह जेनेटिकली माडिफाइड (जीएम) फसलों पर 2024 के अपने फैसले के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली अवमानना याचिकाओं पर जल्द सुनवाई करे। यह मांग जीएम बासमती चावल की खेती की कथित मंजूरी को लेकर जताई जा रही चिंताओं के बीच की गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता अरुणा रोड्डिस की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने जीएम फसलों से जुड़ी अवमानना याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया है। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची व न्यायमूर्ति बी. मोहना की पीठ के समक्ष यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया।

प्रशांत भूषण ने कहा कि सरकार ने हर्बिसाइड-टालरेंट जीएम बासमती चावल की खेती को हरी झंडी दे दी है। उन्होंने गंभीर आशंका जताई कि यह फैसला हमारे पारंपरिक बासमती चावल के वजूद को तबाह कर देगा। इससे फसलों में अपरिवर्तनीय संक्रमण फैलेगा, जो पूरे कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में भारी तबाही मचा सकता है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के 23 जुलाई 2024 के उस फैसले के उल्लंघन से जुड़ा है, जिसमें केंद्र को आदेश दिया गया था कि राज्यों, विशेषज्ञों व हितधारकों के साथ परामर्श के बाद जीएम फसलों पर व्यापक राष्ट्रीय नीति तैयार की जाए। आरोप लगाया गया है कि नीति बनने से पहले 'रोबीनोवीड' ब्रांडेड बासमती (मई 2024), 'कमला' (डीपीआर राइस 100) और 'पूसा डीएसटी राइज 1' (मई 2025) जैसी जीन-संपादित किस्मों को व्यावसायिक रूप से जारी कर दिया गया।

- सुप्रीम कोर्ट से अवमानना याचिका पर जल्द सुनवाई की गुहार
- याचिका में किया आगाह- बासमती के अस्तित्व पर मंडराया खतरा

युवक के शरीर में मिला गर्भाशय और अंडाशय

राज्य ब्यूरो, जागरण : कोलकाता: बंगाल के दक्षिण 24 परगना के बजबज निवासी 24 वर्षीय युवक के शरीर में गर्भाशय, अंडाशय और फैलोपियन ट्यूब होने का दुर्लभ मामला सामने आया है। हर्निया के आपरेशन के लिए जिले के फलता स्थित एक नर्सिंग होम में भर्ती युवक की जांच के दौरान इन अंगों की मौजूदगी का पता चला। इसके बाद चिकित्सक डा एच जमान ने सर्जरी कर इन आंतरिक प्रजनन अंगों को निकाल दिया। नर्सिंग होम के सूत्रों के अनुसार, आपरेशन के बाद युवक की स्थिति सामान्य है।

युवक को पिछले सोमवार को नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। वह हर्निया का आपरेशन कराने आया था। जांच के दौरान चिकित्सकों को उसके शरीर में गर्भाशय, अंडाशय और फैलोपियन ट्यूब की मौजूदगी का पता चला। इसके बाद इन अंगों को निकालने के लिए आपरेशन किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक, युवक के शरीर में अंडकोष भी नहीं हैं। उसकी करीब दो साल पहले शादी हुई थी।

एजेएल के अटैच संपत्ति को छुड़ाने के प्रयास पर रोक से हाई कोर्ट का इन्कार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा- इस स्तर पर नहीं पारित कर सकते किसी प्रकार का कोई अंतरिम आदेश

नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को अपीलीय ट्रिब्यूनल के सामने अपनी अटैच संपत्तियों को छुड़ाने की कोशिश करने पर रोक लगाने से दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को इन्कार कर दिया। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ के समक्ष ईडी की तरफ से पेश एडिशनल सालिसिटर जनरल एसवी राजू ने बताया कि एजेएल अब प्रिवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत गठित अपीलीय ट्रिब्यूनल के सामने संपत्ति को छुड़ाने के लिए ट्रायल कोर्ट के आदेश का सहारा ले रही है। पीठ ने कहा, इस स्तर पर कोर्ट अंतरिम आदेश पारित नहीं कर सकता है।

ईडी की तरफ से पेश एएसजी ने उक्त जानकारी ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेने से इन्कार करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर दी। साथ ही कोर्ट ने मामले की सुनवाई दो नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। ट्रायल कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की ओर से वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी व सोनिया गांधी के साथ ही यंग इंडियन, एजेएल सहित अन्य आरोपितों के खिलाफ दाखिल आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से इन्कार कर दिया था। ईडी ने यंग इंडियन व एजेएल की कई संपत्तियों को जब्त किया था।

नेशनल हेराल्ड मामला पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी की एक निजी शिकायत से जुड़ा था और इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, आस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा व यंग इंडियन पर धोखाधड़ी, साजिश, विश्वासघात और संपत्ति के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है।

ईडी ने कुर्क कीं अर्थ समूह की 140 करोड़ रुपये की संपत्ति

नई दिल्ली, आइएएनएस: ईडी ने 19,425 घर खरीदारों और निवेशकों से 2,004 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी मामले में अर्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर, सब्मिडियरी कंपनियों और प्रमोटरों की करीब 140 करोड़ की अचल संपत्तियां कुर्क की हैं।

एक अधिकारी ने बताया कि ईडी के दिल्ली जोनल कार्यालय-दो ने मनी लांड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत कंपनी और उसके प्रमोटरों अवधेश कुमार गोयल, रजनीश मित्तल, अतुल गुप्ता व विकास गुप्ता के साथ उनके परिवार के सदस्यों की अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं। इस कुर्की के साथ मामले में कुर्क व जब्त संपत्तियों का कुल मूल्य 352 करोड़ हो गया है। अर्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर और उससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी से संबंधित मनी लांड्रिंग मामले की जांच के तहत यह कार्रवाई की गई है।

स्पाइसजेट क्यू400 के 40 पायलट बोले, जब तक वेतन नहीं तब तक काम नहीं

मुंबई, भ्रेट : स्पाइसजेट के क्यू400 एयरक्राफ्ट बेड़े के करीब 40 पायलटों ने तब तक उड़ान भरने से इन्कार कर दिया, जब तक एयरलाइन उनकी बकाया सैलरी का भुगतान नहीं करता। पायलटों के संगठन एएलपीए इंडिया ने भी इस कदम का समर्थन किया है। यह एयरलाइन पिछले कई महीनों से आर्थिक और आपरेशनल चुनौतियों का सामना कर रही है, और एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए एयरलाइन पर कड़ी नजर रखे हुए है।

सूत्रों ने सोमवार को बताया कि हाल ही में क्यू 400 विमान उड़ाने वाले 40 पायलटों ने अपनी बकाया सैलरी का भुगतान होने तक उड़ान भरने से इन्कार कर दिया। इस बारे में और जानकारी तुरंत नहीं मिल सकी। स्पाइसजेट ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। एक फ्लीट ट्रैकिंग वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, एयरलाइन के पास 10 विमानों का आपरेशनल फ्लीट है, जिसमें दो क्यू400 शामिल हैं, जबकि 37 विमान खड़े (पार्क) हैं।

एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन आफ इंडिया (एएलपीए इंडिया) ने नै अक्टूबर को अपने सभी सदस्यों और सिविल एविएशन कम्युनिटी को लिखे पत्र में कहा कि वह इन पायलटों के साथ मजबूती से खड़ा है और उन्हें पूरा नैतिक समर्थन देने का भरोसा दिलाता है।

- एयरलाइन पिछले कई महीनों से आर्थिक और आपरेशनल चुनौतियों का सामना कर रही



प्रतीकात्मक

पूर्व सांसद का दावा, संपत्ति हड़पने के इरादे से की गई थी बेटे की हत्या

जागरण संवाददाता, जयपुर : राजस्थान में कांग्रेस के पूर्व सांसद रतन सिंह ने जयपुर के जवाहर सर्किल पुलिस थाने में अपनी पुत्रवधू और पोते के खिलाफ अपने पुत्र की हत्या करने का गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। रतन सिंह के अनुसार, 11 सितंबर को जब राजेंद्र की संदिग्ध हालात में मौत हुई, तब उसकी पत्नी नीतू और बेटा सौरव घर पर साथ मौजूद थे। पूर्व सांसद का दावा है कि राजेंद्र के होंठ नीले पड़े हुए थे। गौरतलब है कि राजेंद्र सार्वजनिक निर्माण विभाग में अधीक्षण अभियंता पद पर कार्यरत थे। रतन सिंह ने आरोप लगाया कि सौरव ने अनुकंपा नियुक्ति व नीतू ने संपत्ति हड़पने के लिए राजेंद्र की जहरीली पदार्थ पिलाया।

राजेंद्र और नीतू की शादी 11 मई 2005 को हुई थी। दोनों में लंबे समय से विवाद चल रहा था। राजेंद्र ने विवाह विच्छेद के लिए पारिवारिक न्यायालय में साल 2019 में मुकदमा दर्ज किया था।

लोकमानस

loksatta@expressindia.com

देशभरात असंख्य जंतर-मंतर

'जंतर-मंतर-अंतर!' हा अग्रलेख (१२ ऑक्टोबर) वाचला. सीजेपीचे आंदोलन दडपण्यासाठी जे प्रयत्न करण्यात आले, ते पाहता सीजेपीच्या तीन नेत्यांना विमानातून अटक केली जाणे कायदेशीर आहे का, हे तपासून पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. पोलीस प्रशासन असे अचानक विमानात घुसू शकते का? या वेळीदेखील पोलिसांनी महिला आणि मुलींवर अत्याचार केले आहेत. त्यांचा विनयभंग केला आहे. दिल्ली पोलीस आंदोलकांवर अत्याचार करण्यासाठी दंडुका बसलेले असताना कायदा? नेतेमंडळी पकडली गेली तरी बाकीच्या आंदोलकांनी शक्य तिथे आंदोलन करून निषेध व्यक्त केला, ज्यामुळे ठिकठिकाणी जंतर-मंतर तयार झाले आहेत. याचा एवढा धसका दिल्ली प्रशासनाने घेतला आहे की आंदोलनस्थळांच्या यादीतूनच जंतर-मंतरला वगळण्यात आले. एकंदर देशभरात असंख्य जंतर-मंतर तयार होऊ लागल्यामुळे सरकार आणि आंदोलक यांच्यातील अंतर मात्र प्रचंड वाढले आहे.

■ **शुभदा गोवर्धन,** ठाणे

हे भित्र्यापाठी ब्रह्मराक्षस लागल्यासारखेच

'जंतर-मंतर-अंतर!' हा अग्रलेख वाचला. शांततापूर्ण आंदोलनास परवानगीची गरजच काय? या सरकारने देशात 'स्वकीय' शेतकरी आंदोलन करत असताना सीमेवर असते तसे काटेरी कुंपण लावले. विद्यार्थ्यांनी जंतर-मंतरवर महिनाभर शांततापूर्ण आंदोलन केले हे सरकार जाणते, तरीही पुन्हा विद्यार्थ्यांचेच आंदोलन रोखण्यासाठी ४० हजार सैनिकांचा फौजफाटा उभा करण्याची गरज का भासली? याही उपर, विचारधारेशी संलग्न बेलगाम पाळीव गुंडांची फौज आहेच दिमतीला. ही फौज भरदिवसा, कॅमेऱ्यासमोर, पोलिसांच्या उपस्थितीत लहान लहान मुलांवर हल्ला करत आहे, ही वस्तुस्थिती आपल्या कायदा व्यवस्थेबाबत काय सांगते? माकडाच्या हातात कोलीत दिल्यास काय परिणाम होतात याचा प्रत्यय देश आज घेतोय. एकेकाळचे तडीपार कायदा सुव्यवस्थेचे चालक-मालक होतात तेव्हा ते आपल्या अधिकारांचा निरंकुश वरवंटा फिरवण्यासाठी न्यायालयाची तमा बाळगतील अशी अपेक्षा अनाठायी नाही तर काय? म्हणतात ना भित्यापाठी ब्रह्मराक्षस, त्यामुळे जंतर-मंतर १.० ने घाबरलेल्या सरकारला दिपके व त्यांच्या कॉम्रेाच साथीदारांमध्ये राक्षस दिसल्यास नवल ते काय!

■ **ओवी भावे,** पुणे

सोनारानेच कान टोचले ते बरे झाले

'जंतर-मंतर-अंतर' हे संपादकीय वाचले. 'सीजेपी'ने जंतर-मंतर येथे आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आणि मग काय, सरकारने ते आंदोलन मोडून काढण्यासाठी आधी परवानगी नाकारली, मग विमानात घुसून नेत्यांना ताब्यात घेतले. मेट्रो स्थानके, इंटरनेट सेवा, रेल्वे, रस्ते बंद केले. सरकारच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले. कोणालाही विनाकारण ताब्यात घेता येणार नाही, अशीही तंबी दिली. म्हणजे सरकारच्या अनिर्बंध हुकूमशाहीवर अंकुश टेवण्याची सर्वोच्च न्यायालयालाही गरज वाटू लागली. इतकेच नव्हे तर 'संयुक्त राष्ट्र मानवी हक्क रक्षण आयोगा'सही मध्यस्थी करणे भाग पडले. सोनारानेच कान टोचले ते बरे झाले. निरंकुश, मदमस्त सत्ताधीश अन्याय, अत्याचार करीत राहिले तरी आंदोलनाची व्यापी कमी न होता अजून वाढत राहील हे निश्चित. घटनात्मक मागणे आंदोलन करणाऱ्या तरुणांना डांबून ठेवणे हे भारतासारख्या 'लोकशाहीच्या जननी'स अत्यंत लांच्छनास्पद आहे.

■ **उर्मिला पाटील,** कल्याण

असे होणार आपण महासत्ता?

'राम तेरी गंगा' हा 'नदीकारण' या सदराचा लेख (१२ ऑक्टोबर) वाचला. आज बेटावर मोजण्याइतकेच लोक पर्यावरणाचा प्रामाणिकपणे विचार करताना दिसतात. ज्यांच्यावर पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारी आहे, असे मोठमोठ्या पदांवर विराजमान लोक 'जास्तीत-जास्त कसे मिळवता येईल' याचाच विचार करतात. वाळू माफिया सारे नियम धाब्यावर बसवून त्याचा धंदा चालवतो आणि पुढे एखाद्या राजकीय पक्षात प्रवेश करून आपल्या नियमबाह्य कृत्यांना संरक्षण मिळवून देतो. आज धर्माचा वापर मते मिळवण्यासाठी होत आहे, मात्र धर्माचा वापर करून नदी राखावी, असे धोरणकर्त्यांना वाटत नाही. भारत महासत्ता होईल की नाही, माहीत नाही, पण जर झालाच आणि या मूलभूत गोष्टी सुधारलेल्या नसतील, तर अशा बिरुदांचा काय उपयोग?

■ **प्रथमेश वाघ,** अंबड (जालना)

संविधानाच्या चौकटीचा विसर

'कुठले सरन्यायाधीश आंदोलकांना भेटतात?' ही बातमी वाचली. यानिमित्ताने काही प्रश्न उद्भवतात ते म्हणजे - कोणते पंतप्रधान सरन्यायाधीशांच्या घरी त्यांच्या वैयक्तिक धार्मिक समारंभाला आणि आरतीला हजेरी लावतात? - संविधान आणि संस्कृतीच्या गप्पा मारणारे... पण लोकशाहीच्या पवित्र चौकटीला सोयीस्करपणे विसरणारे! कोणते माजी मुख्यमंत्री वेशांतर करून, हुडी घालून रात्री-अपरात्री विरोधी नेत्यांच्या भेटी घेतात? - दिवसा नैतिकतेची आणि उघड राजकारणाची भाषा करणारे... पण रात्रीच्या अंधारात सत्तेसाठी वेशांतर करणारे! कोणते मुख्यमंत्री सकाळी उजाडायच्या आधी छुप्पा पद्धतीने आपल्या पदाची शपथ घेतात? - पारदर्शक कारभाराचा डांगोरा पिटणारे.

■ **कालिदास भाटे,** कोल्हापूर

वैज्ञानिक दृष्टिकोन कसा विकसित होणार?

संविधानाच्या अनुच्छेद २५ नुसार उपासना स्वातंत्र्याचा अधिकार वैयक्तिक आहे. पण उपासनेचा बाजार सार्वजनिक करणे हे संविधानविरोधी नाही काय? व्यक्तीच्या धार्मिक श्रद्धेचा आदर राखणे आणि त्या श्रद्धेचे सार्वजनिक प्रदर्शन यांना अवाजवी प्रसिद्धी देणे, या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. माहूर गडावरील घटस्थापना, तुळजापुरात दाखल झाले हजारो भाविक, अंबाबाई किंवा विठ्ठलाच्या मूर्तीला वज्रलेप लावण्याची प्रक्रिया सुरू, अशा बातम्यांना 'लोकसत्ता'सारख्या वर्तमानपत्राने पहिल्या पानावर स्थान द्यावे का? अशा घटनांचे वृत्तांकन करणे गैर नाही; परंतु त्यांना दिले जाणारे प्राधान्य आणि त्यामागील दृष्टिकोन तपासणे आवश्यक आहे. धार्मिक विधींची छायाचित्रे आणि बातम्या पहिल्या पानावर प्रसिद्ध करून लोकसत्ता वाचकांना कोणता दृष्टिकोन देऊ इच्छिते? संविधानाच्या अनुच्छेद ५१अ(ह) नुसार वैज्ञानिक दृष्टिकोन, मानवतावाद आणि शोधक वृत्ती विकसित करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे मूलभूत कर्तव्य आहे. समाजाचे वैचारिक विश्व घडवणाऱ्या प्रसारमाध्यमांनीही या मूल्यांना पूरक भूमिका घ्यावी, ही अपेक्षा असताना लोकसत्ता दृष्टिकोन देतो सांगत असेल, तर तो दृष्टिकोन चिकित्सक विचारांना चालना देणारा आहे की धार्मिक श्रद्धेच्या सार्वजनिक प्रदर्शनाला प्रतिष्ठा देणारा, हा प्रश्न विचारायलाच हवा.

■ **जगदीश काबरे,** सांगली

आयोगाच्या 'बुद्धिमत्ते'चा जळजळीत प्रत्यय

'**मतदार याद्यांच्या** विशेष सखोल फेरतपासणीतील विनोद' हा अमलेश कणेकर यांचा लेख (११ ऑक्टोबर) वाचला. आणि काही तासांतच हा केवळ विनोद नसून क्रूर विनोद असल्याचा आणि निवडणूक आयोगाच्या 'दिव्य बुद्धिमत्ते'चा जळजळीत प्रत्यय आला. चुकांची दुरुस्ती करवून घेण्यासाठी फॉर्म ६ भरून, विहित कागदपत्रांसहित ८ सप्टेंबर रोजी दिल्यानंतर, त्या चुकांची दुरुस्ती पडताळण्यासाठी घरी आलेल्या गृहस्थांनी दुरुस्तीचा कागद पुढे केला आणि त्यात नवी गंभीर चूक करून ठेवल्याचे आढळले.

आमच्या सोसायटीतील अनेक रहिवाशांचे पते चुकीचे नोंदलेले होते, ते दुरुस्त करून घेण्यासाठी प्रत्येकाने एसआयआरच्या कार्यालयात जाऊन फॉर्म ६ व विहित कागदपत्रे दिली होती. माझाही पत्ता चुकीचा नोंदलेला होता, तसेच वडिलांचे नाव हे नवऱ्याचे नाव म्हणून नोंदले होते आणि आडनावाच्या स्पेलिंगमध्ये चूक केलेली होती. 'देशपांडे' या आडनावाचे इंग्रजी स्पेलिंग डी ई एस एच पी ए एन डी ई वाय - 'देशपांडेय' असे केले होते. मी पासपोर्ट व आधार कार्डांच्या प्रतींवरोबरच एका कोऱ्या कागदावर मोठ्या आणि सुस्पष्ट अक्षरात सगळी माहिती देवनागरी आणि रोमन लिपीत लिहून फॉर्म ६ सहित ८ सप्टेंबर रोजी कार्यालयात नेऊन दिली. त्याची त्यांनी मला पावतीही दिली. परंतु आज पडताळणीसाठी त्यांचा माणूस आला तेव्हा त्या पेपरवर दुरुस्ती केलेल्या ठिकाणी माझ्या आणि माझ्या वडिलांच्या देशपांडे या आडनावेवजी 'दुबे' असे आडनाव आढळले. ही गंभीर चूक निदर्शनाला आणून दिल्यावर हे गृहस्थ विचारतात, 'मग हे दुबे कोण?' हा वर्तमान व्यवस्थेचा क्रूर विनोद म्हणावयचे नाही तर काय म्हणावे?

■ **रेखा देशपांडे,** ठाणे

एसआयआर : वस्तुस्थिती आणि विपर्यास

एसआयआर विशिष्ट पक्षाच्या फायद्यासाठी किंवा तोट्यासाठी नव्हे, तर भारताच्या प्रत्येक वैध नागरिकाच्या मताचे मूल्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी राबवली जाणारी मोहीम आहे. मात्र विरोधी पक्षांकडून या घटनात्मक, तांत्रिक आणि कायदेशीर प्रक्रियेला राजकीय रंगात रंगवले जात आहे.



निरंजन डावखरे
आमदार,
शरदीयपीस, नागपूर, महाराष्ट्र प्रदेश

पहिली बाजू

लोकशाही व्यवस्थेत अद्यवावत, पारदर्शक आणि संपूर्णपणे निर्दोष मतदार यादी हाच निवडणुकीचा मुख्य आधार असतो. या पार्श्वभूमीवर, भारतीय निवडणूक आयोगाने हाती घेतलेली 'एसआयआर' (मतदार याद्यांची विशेष सखोल फेरतपासणी) मोहीम म्हणजे लोकशाहीची पारदर्शकता टिकवून ती अधिक सशक्त करण्यासाठी राबवली जाणारी अनिवार्य प्रशासकीय प्रक्रिया आहे. परंतु दुर्दैवाने सध्या या घटनात्मक, तांत्रिक आणि कायदेशीर प्रक्रियेला राजकीय रंगात रंगवले जात आहे. विरोधकांकडून सातत्याने जनतेच्या मनात संभ्रम आणि भीती निर्माण केली जात आहे.

देशात निष्पक्ष निवडणुका घडवून आणणाऱ्या एका सर्वोच्च स्वायत्त संस्थेच्या हेतूवर आणि कार्यपद्धतीवरच थेट शंका उपस्थित करून लोकशाही व्यवस्थेत अविश्वास आणि अराजकता पसरवण्याचा हा प्रयत्न आहे. राजकीय स्वार्थापोटी या राष्ट्रीयहिताच्या महत्त्वाच्या अभियानाचा केलेला विपर्यास ओळखला पाहिजे. यामागील वस्तुनिष्ठ प्रशासकीय आणि कायदेशीर प्रक्रिया समजून घेतली पाहिजे.

एसआयआरचा इतिहास व आवश्यकता

मतदार याद्यांच्या विस्तृत पुनरीक्षणाच्या प्रक्रियेला भारताच्या निवडणूक व्यवस्थेने अनेक दशकांचा इतिहास आहे. मतदार याद्या अधिक अचूक आणि विश्वासार्ह ठेवण्यासाठी निवडणूक आयोगाने विविध टप्प्यांवर मतदार याद्यांची सखोल फेरतपासणी केली आहे:

■ १९५२ ते १९५६ : या कालावधीत निवडणूक आयोगाने देशातील बहुतांश भागांत मतदार याद्यांची विस्तृत फेरतपासणी केली.

■ १९५७, १९६१, १९६५ आणि १९६६ : या वर्षांमध्येही देशातील बहुतांश भागांत ही फेरतपासणी करण्यात आली.

■ १९८३-८४, १९८७-८९, १९९२, १९९३ आणि १९९५ या कालावधीतही मतदार याद्यांची विस्तृत फेरतपासणी करण्यात आली.

■ २००२, २००३ आणि २००४ या काळातही निवडणूक आयोगाने पुन्हा मतदार याद्यांची सखोल फेरतपासणी केली.

विस्तृत फेरतपासणी करताना घराघरांत जाऊन मतदारांकडून माहिती घेणे, मतदार गणना अर्ज वितरित करणे व जमा करणे, मतदारांच्या नोंदींची पडताळणी करणे आणि मतदार गणनेच्या माध्यमातून याद्या नव्याने तयार करण्याची प्रक्रिया केली जाते.

वेगाने होणारे शहरीकरण, नागरिकांचे वारंवार होणारे स्थलांतर, नवीन पात्र मतदारांची भर, मृत्यू आणि एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी झालेली नोंदणी यामुळे मतदार यादीत मोठे बदल होत असतात. गेल्या २० वर्षांत मतदार यादीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नावे वाढली आणि वगळली गेली आहेत. त्यामुळे वेळोवेळी सखोल पडताळणी आवश्यक ठरते. पात्र नागरिकांचा मतदार यादीत समावेश आणि कोणताही पात्र नागरिक वगळला जाऊ नये, हे निवडणूक आयोगाच्या महत्त्वाच्या उद्दिष्टांपैकी एक आहे. मतदार याद्यांची अचूकता आणि विश्वासार्हता कायम ठेवण्यासाठी ही दीर्घकाळापासूनची प्रक्रिया असून, सध्याची विशेष सखोल फेरतपासणी ही त्याच व्यापक प्रक्रियेचा पुढील टप्पा आहे.

घटनात्मक आधार

संविधानानुसार निवडणूक आयोग ही एक स्वतंत्र आणि स्वायत्त संस्था आहे. कोणत्याही राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय देशात निवडणुका पार पाडू शकणारी सक्षम यंत्रणा आहे.

■ अनुच्छेद ३२४ : हा अनुच्छेद निवडणूक आयोगाला संसदेच्या आणि राज्य विधिमंडळांच्या निवडणुकांसाठीच्या मतदार याद्या तयार करणे, त्यांचे नियंत्रण करणे आणि निवडणुकांचे संचालन करण्याचे पूर्ण अधिकार प्रदान करतो.

■ लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५० : या कायद्यातील कलम २१ नुसार प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी किंवा विशिष्ट कालावधीनंतर मतदार याद्यांची फेरतपासणी करणे हे आयोगासाठी बंधनकारक आहे. आयोगाचे हे कर्तव्य आहे.

एसआयआरचे मूळ उद्दिष्ट

(१) मृत मतदार वगळणे : निधन झालेल्या व्यक्तींची नावे यादीत राहिल्याने संभाव्य बोगस मतदानाला पूर्णपणे आळा घालणे.

(२) स्थलांतरित व दुबार नोंदणी शोधणे : एकाच नागरिकाचे नाव दोन वेगवेगळ्या मतदारसंघांत किंवा एकाच यादीत दोन ठिकाणी असणे ही लोकशाही प्रक्रियेतील मोठी त्रुटी आहे. ती तांत्रिक प्रणालीद्वारे दूर करणे.

(३) अवैध नोंदी रद्द करणे : जे नागरिक भारताचे कायदेशीर नागरिक नाहीत किंवा ज्यांच्या नोंदी तांत्रिकदृष्ट्या अपूर्ण अथवा चुकीच्या आहेत, त्यांची छाननी करून यादी निर्दोष करणे.

प्रशासकीय पारदर्शकता

विरोधकांकडून असा दावा केला जातो की ही मोहीम गुप्त, अपारदर्शक आणि एकतर्फी आहे; मात्र प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती याच्या पूर्णपणे उलट आहे.

■ सर्वपक्षीय सहभाग (बूथ लेव्हल एजन्ट्स-बीएलए) : निवडणूक आयोग ही प्रक्रिया एकतर्फी करत नाही. मान्यताप्राप्त प्रत्येक राजकीय पक्षाला प्रत्येक मतदान केंद्रावर आपले 'बूथ लेव्हल एजंट' (बीएलए) नियुक्त करण्याचा अधिकार असतो. आयोगाचे बीएलए जेव्हा प्रत्यक्ष काम करतात, तेव्हा हे राजकीय प्रतिनिधी त्यांच्याबरोबर उपस्थित राहून यादीतील नावांची पडताळणी करू शकतात.

■ नागरिकांसाठी कायदेशीर मार्ग : मतदार यादीत नवीन नाव नोंदवण्यासाठी (फॉर्म ६), नाव वगळण्यासाठी किंवा हरकत घेण्यासाठी (फॉर्म ७) आणि पत्ता किंवा माहिती दुरुस्तीसाठी (फॉर्म ८) प्रत्येकाला पूर्ण संधी दिली जाते.

■ डिजिटल प्रणाली व ट्रॅकिंग : 'व्होटर हेल्पलाइन ॲप' आणि आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून कोणताही नागरिक आपले नाव, अर्जाची स्थिती आणि यादीतील बदल स्वतः थेट तपासू शकतो. त्यामुळे यात कोणतीही माहिती लपवण्याचा किंवा परस्पर नावे हटवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

संशयाचे राजकारण

सद्य राजकीय स्थितीत वैचारिक विरोधाची जागा दुराग्रही द्वेषाने घेतली आहे. प्रत्येक प्रशासकीय निर्णयाकडे राजकीय चष्म्यातून पाहण्याची वृत्ती वाढीस लागली आहे.

■ परस्परविरोधी आक्षेप : जर मतदार यादीत बोगस नावे राहिली किंवा त्रुटी आढळल्या, तर निवडणूक आयोगावर 'अकार्यक्षम' किंवा 'सत्ताधाऱ्यांशी हातमिळवणी केल्याचा' आरोप केला जातो. आणि जेव्हा आयोग हीच यादी स्वच्छ करण्यासाठी, अद्ययावत करण्यासाठी मोहीम हाती घेतो, तेव्हा त्याला 'विरोधकांना संपवण्याचा राजकीय कट' म्हणून हिणवले जाते. ही दुटप्पी भूमिका राजकीय हेतूने प्रेरित आहे, हे स्पष्ट दिसते.

■ स्वायत्त संस्थांचे खच्चीकरण : निवडणूक आयोग, न्यायव्यवस्था किंवा इतर घटनात्मक संस्थांवर सातत्याने अविश्वास दाखवल्याने संस्थांची जागतिक पातळीवर पत घसरते. यामुळे सामान्य नागरिकांचा संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया आणि लोकशाहीवरील विश्वास डळमळीत होतो, जो देशासाठी अत्यंत घातक ठरू शकतो.

■ अराजकता पसरवण्याचा प्रयत्न : वस्तुस्थितीची शहानिशा न करता केवळ राजकीय प्रसिद्धी, आंदोलने आणि समाजमाध्यमांतून समाजात असंतोष निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. राजकीय टीकेतील संयम आणि तोल पूर्णपणे ढळला असून निवडणूक आयोगविरोधात वैर भावना निर्माण केली जात आहे.

लोकशाहीची चौकट

न्यायव्यवस्थेने मतदार यादीच्या शुद्धीकरणाला लोकशाहीचा मूलभूत आधार मानले आहे.

न्यायालयीन दाखले : सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक महत्त्वाच्या निकालांमध्ये (उदा. मोहिंदर सिंग गिल विरुद्ध मुख्य निवडणूक आयुक्त, १९७८) स्पष्ट केले आहे की, मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका घेणे हा राज्यघटनेच्या मूलभूत चौकटीचा भाग आहे.

निर्दोष यादी हीच निष्पक्षतेची अट : मतदार यादीतच त्रुटी असतील, तर निवडणूक निष्पक्ष होऊच शकत नाही. यादी अद्ययावत करणे लोकशाहीसाठी गरजेचे आहे.

विरोध करताना देशातील सर्वोच्च स्वायत्त संस्थांची विश्वासार्हता धुळीस मिळवणे आणि समाजात संभ्रमाचे वातावरण तयार करणे हे जबाबदार राजकीय वर्तनात बसत नाही.

एसआयआर ही विशिष्ट पक्षाच्या फायद्यासाठी किंवा तोट्यासाठी नसून, भारताच्या प्रत्येक वैध नागरिकाच्या मताचे मूल्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी राबवली जाणारी मोहीम आहे. राजकीय अफवा, सुडबुद्धी आणि पसरवलेल्या संशयाच्या धुक्यापेक्षा देशाचे संविधान, कायद्याचे अधिराज्य आणि पारदर्शक प्रक्रियेचा श्रेष्ठ आहे. विरोधकांनी या प्रक्रियेवर दोषारोप करण्याऐवजी कायदेशीर मागनि यात सहभागी होऊन लोकशाही भक्कम करण्यासाठी सहकार्य करणे आवश्यक आहे. मात्र, लोकशाहीचे सक्षमीकरण करण्याऐवजी विरोधक लोकशाहीचे खच्चीकरण करत आहेत.

कुतूहल

पंख्यामुळे थंड का वाटतं?

लहानपणी आपण सगळ्यांनी हे बडबडगीत नक्की ऐकलं असेल, 'पंखा फिरतो वर छतावर, गोल गोल विजेच्या जोरावर, झोपेतही वारा देतो मंद, रात्री थंडावा, दिवसा आनंद!' असा हा पंखा आपल्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे.

विद्युत पंख्याचे मुख्य तीन घटक आहेत. पहिला घटक म्हणजे विद्युत मोटर. हा पंख्याचा असा मुख्य भाग आहे जो विद्युत ऊर्जेचे रूपांतर पंखा फिरवणाऱ्या यांत्रिक ऊर्जेत करतो. या भागामुळेच आपण बटन दाबल्यावर पंखा सुरू होतो. दुसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे पाती आणि तिसरा घटक म्हणजे कॅपॅसिटर. मोटरमुळे फिरणारी पाती हवा ढकलण्याचं काम करतात तर कॅपॅसिटर मोटर सुरू करण्यास मदत करतो.



आता पंखा हवा कशी फिरवतो ते बघू या. पंख्याची पाती मोटरने गोल फिरवली जातात. पाती फिरताना हवा पुढे ढकलली जाते आणि त्यामुळे पात्याच्या वरच्या बाजूला हवेच्या कमी दाबाचं क्षेत्र तयार होतं. परिणामी खोलीतील हवा पंख्याकडे खेचली जाते आणि जोराने खाली ढकलली जाते. या प्रक्रियेमुळे हवा खोलीत सतत फिरत राहते. गरम हवा वरच्या भागात जमा होत नाही तर सर्वत्र एकसारखी पसरली जाते.

आता पंख्यामुळे थंड वाटण्याचं वैज्ञानिक तत्त्व समजून घेऊ या. पंखा थेट हवा थंड करत नाही पण शरीरावरून गरम आणि ओलसर हवा दूर करतो. यामुळे आपल्या अंगावरचा घाम लवकर सुकतो. यालाच सोप्या भाषेत 'बाष्पीभवन' म्हणतात.

पंख्यामुळे हवेचा वेग वाढतो. त्यामुळे शरीरावरील घामाचं बाष्पीभवन जलद होतं आणि शरीरावरच्या घामरूपी पाण्याचं बाष्पीभवन करण्यासाठी लागणारी उष्णतेच्या रूपातली ऊर्जा ही शरीरातल्या त्वचेच्या पेशींमधून घेतली जाते. त्यामुळे पंखा खोलीचं तापमान प्रत्यक्षात कमी करत नाही.

परंतु आपल्याला मात्र त्वचेच्या पेशींमधली उष्णता ऊर्जा कमी झाल्यामुळे शरीराला थंडावा जाणवतो. हा थंडावा पूर्णपणे नैसर्गिक असतो. अगदी असाच थंडावा आपल्याला कडक उन्हाळ्यात वाळ्याच्या पडद्यामुळे मिळतो. बाहेरच्या कडक उन्हामुळे वाळ्याच्या पडद्यातील पाण्याचं बाष्पीभवन होतं व खोलीमध्ये नैसर्गिक थंडावा तयार होतो.

आता पंखा लावल्यावर आपल्याला थंड का वाटतं हे तुम्हाला कळलं असेल पण आपल्या आजूबाजूची हवा थंड का होत नाही, असा प्रश्न तुम्हाला नक्की पडला असेल. पंखा खोलीतील हवा फक्त फिरवत राहतो. तो वातानुकूलित यंत्रासारखी बाष्पीभवन आणि संकोचन चक्राद्वारे खोलीतील उष्णता प्रत्यक्ष बाहेर काढून हवेचं तापमान कमी करून हवा थंड करत नाही. म्हणूनच पंख्यामुळे आपल्याला थंड वाटतं पण आजूबाजूची हवा मात्र थंड होत नाही.

– नीलम प्रभू
मराठी विज्ञान परिषद
ईमेल : office@mavipa.org
संकेतस्थळ : www.mavipa.org

व्यक्तिवेध

मधु कांबीकर

'**बाळाचे पाय** पाळण्यात दिसतात' हे प्रत्येक कर्तृत्ववान व्यक्तीच्या बाबतीत सत्यच असले पाहिजे, असे नाही. अंगभूत कला आहे किंवा कलेचा वारसा मिळाला आहे म्हणून तोच पुढे नेण्यात धन्यता मानणाऱ्यांची संख्या अधिक असताना, दूर कुठे तरी बीडमधल्या माळेगावसारख्या छोट्याशा खेड्यातून आलेल्या मधु कांबीकर यांनी सत्तरच्या दशकात स्वतःहून आपली वाट निर्माण केली. कला क्षेत्रात त्यांनी पदार्पण केले ते लोककलावंत म्हणून.



पुढे रंगभूमीवर स्वतःला कलाकार म्हणून अजमावले आणि नंतर चित्रपट आणि मालिकांतून स्वतःची विशेष ओळख निर्माण केली, तीदेखील त्या क्षेत्रात कोणीही पाठीराखा नसताना. तीन दशकांहून अधिक काळ त्यांनी केलेल्या भूमिका आणि लावणीला प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी उभारलेले कार्य विलक्षण होते, मात्र त्यांच्या कामाचे हवे तसे कौतुकही झाले नाही आणि त्यांनीही कधी प्रसिद्धी-वलयाचा हव्यास धरला नाही.

मधु कांबीकर यांचे वडीलही लोककलावंत होते, त्यामुळे वय, गवळण आदी पारंपरिक कलाक्षेत्राशी त्यांची लहानपणापासूनच तोंडओळख होती. पण लोककलावंत म्हणून पुढे जाण्याचा निर्णय घेताना फक्त लावणी नृत्य शिकायचे आणि मग पायात घुंगरू बांधून उभे राहायचे, हा माफक दृष्टिकोन त्यांनी ठेवला नाही. लहानपणापासून शिस्तबद्ध पद्धतीने स्वतःला घडवले. शिक्षणात आपल्याला फारसा रस नाही, हे उमजून त्यांनी सातवीपर्यंत शिक्षण पूर्ण केले. अकराव्या वर्षी त्यांनी पुण्यात बाळासाहेब गोखले यांच्याकडे कथ्थक नृत्याचे शिक्षण घेण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर तीन वर्षांनी त्यांनी गुरू पांडुरंग घोटकर आणि लावणीसम्राज्ञी लक्ष्माबाई कोल्हापूरकर यांच्याकडून लावणी नृत्याचे धडे घेतले. लावणी म्हणजे फक्त नृत्य नव्हे, त्यामागे परंपरा आहे, इतिहास आहे, गीतांमध्ये भाषिक सौंदर्य आहे, नृत्यात लय आहे या सऱ्याची जाण आणि भान केले व ते पुस्तक डेक्कन महाविद्यालयाने प्रकाशित केले. या समग्र टीकेत 'मी श्रीपति' असे उल्लेख चार ठिकाणी आले होते. राजवाडेसंहितेत केवळ दोनच ठिकाणी, त्यावरून काढलेल्या निष्कर्षाला डॉ. पानसे संपादित पूर्ण टीकेमुळे दुजोरा मिळत होता. आणि तरीदेखील डॉ. वि. भि. कोलते १९६८ साली प्रकाशित केलेल्या 'प्राचीन मराठी संशोधन' या आपल्या ग्रंथात त्याची वक्तिचितही दखल न घेता 'मी श्रीपती' हे मराठी उल्लेख मूळ संस्कृत संहितेचे अनुवादरूपच आहेत, असा एकांगी निष्कर्ष काढून मोकळे झाले. १९८४ साली प्रसिद्ध झालेल्या 'मराठी वाङ्मयाचा इतिहास' च्या पहिल्या खंडात संपादक डॉ. शं. गो. तुळपुळे यांनी आवर्जून विशेष टीप लिहून डॉ. कोलते यांचीच री ओढली. या दोन्ही विद्वानांनी डॉ. पानसे यांनी संपादित केलेल्या प्रतीचा तटस्थ वृत्तीने अभ्यास केला असता, तर आपले मत बदलणे आणि राजवाडेप्रणीत १९१४ साली केलेला दावा मान्य करणे त्यांना भाग पडले असते!

पंरतु तसे घडले नाही, राजवाडेप्रणीत दावा अधांतरी लोंबकळतच राहिला...

– आनंद हर्डीकर
anand47.hardikar@gmail.com

राजवाडे विचारविश्व

दखलपात्र संशोधनावर झापडबंद अन्याय

'**शक ९६१च्या** (इसवी सन १०३९च्या) सुमारास लिहिलेल्या मूळ पोथीची शक १३६९च्या (इसवी सन १४४७च्या) सुमारास केव्हातरी केलेली नक्कल आपल्या हाती लागली आहे', असे स्पष्ट करून राजवाड्यांनी पुढे लिहिले, 'मूळ मराठी पोथीची ही कितवी नक्कल आहे न कळे, परंतु श्रीपतीची मूळ मराठी टीका मोठ्या अक्षरांनी लिहून नक्कलकाराने स्वतःचे लिहिणे बारीक अक्षरांनी लिहिले आहे व त्यात स्वतःच्या कालाचा सहजगत्या निर्देश करून ठेविला आहे... नक्कलकाराने संस्कृत श्लोक अगदी अशुद्ध लिहिले आहेत; मराठी टीकाही फारशी शुद्ध लिहिली आहे, असे नाही. भाषा शक ९६१मधील कित्येक स्थळी आहे, परंतु नक्कलकाराने लिहिता आधुनिक म्हणजे शक १३६८-६९च्या सुमाराची करण्यास कमी केलेले नाही... या साऱ्या नक्कलकारांची ही खोडच आहे. प्रायः मूळ ग्रंथ जसाच्या तसा बिनचूक काऱ्हामात्रासुद्धा उतरावयाचे वळण या लोकांना नाहीच. इतके मात्र खरे की, या गावठ्या जोशाचे आपल्यावर ही पोथी लिहून ठेवल्याबद्दल फार उपकार आहेत...'

ते उपकार स्मरून राजवाड्यांनी कर्तव्यबुद्धी जागी ठेवून सुमारे ३२ छापील पाने भरतील एवढी मराठी टीका १५७ स्पष्टीकरणात्मक टिपांसह आणि विशेष म्हणजे ज्योतिषशास्त्रावरचे विवेचन असल्यामुळे त्यात असणाऱ्या ग्रहगणितासारखी काही कोष्टकांसह छापून प्रसिद्ध केली. पोथीमध्ये फुलपाखराचे ऊर्फ पतंगाचे एक चित्रदेखील समाविष्ट होते. राजवाड्यांनी ते चित्र तर छापलेच, परंतु त्यासोबत स्पष्टीकरणात्मक तळटीपही जोडली, ती अशी होती की, 'पतंग म्हणजे सूर्य व पतंग म्हणजे फुलपाखरू असे दोन अर्थ मराठीत पतंग या शब्दाचे होत असल्यामुळे पतंगाचे चित्र काढून सूर्याचे व सूर्यमालिकेचे स्मरण पाहणाऱ्याला करून देण्याचा हेतू लेखकाचा किंवा मूळ ग्रंथकाराचा असावा...' राजवाड्यांनी जरी अशा रीतीने आपले कर्तव्य पार पाडले, तरी 'या आद्य मराठी ग्रंथाच्या प्रकाशनाच्या निमित्ताने संशोधनक्षेत्रात राजवाडे यांनी मारलेली झेप व गाठलेली उंची समकालीनांना पेलता आली नाही आणि या ग्रंथाच्या उत्तरकालीन संशोधकांनीही नंतर प्रकाशित झालेल्या पुरवण्यांमध्ये ग्रंथाची फारशी चिकित्सा न करताच 'हा ग्रंथ मराठी भाषेतला आद्य ग्रंथ ठरत नाही', एवढीच 'रत्नमाले'ची बोळवण केली आहे', हे श्रीधर रंगनाथ कुलकर्णी यांनी प्रस्तावनेत केलेले भाष्य बरेच काही सांगून जाते.

संशोधकांच्या झापडबंद प्रवृत्तीमुळे कधीकधी चुकीचेच निष्कर्ष साधार व सप्रमाण सिद्धांतांच्या नावाखाली कसे प्रचलित होतात, याचे सर्व अभ्यासकांनी लक्षात घ्यावे, असे उदाहरण म्हणून राजवाडे यांच्या 'ज्योतिषरत्नमाले'बद्दलच्या दाव्याचा उल्लेख केला पाहिजे. 'ज्योतिषरत्नमाले'वरील मराठी टीका ही श्रीपतीनेच लिहिली आहे, त्यामुळे ती मराठी आद्यग्रंथ मानली जावी. हा १९१४साली राजवाड्यांनी केलेला दावा होता. जरी समकालीनांकडून त्याला लगेच मान्यता मिळाली नसली, तरी पुढे १९५७ साली डॉ. मु. गु. पानसे यांनी आणखी एका हस्तलिखिताच्या मदतीने 'ज्योतिषरत्नमाले'च्या समग्र मराठी टीकेचे संपादन

कुमार-'संभव'!

मुख्य निवडणूक आयुक्तपदावरून ज्ञानेश कुमार यांना दूर करणे सरकारला परवडणारे नसेल; पण त्यांना राहू देणेही सत्ताधाऱ्यांनाच तापदायक...

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षाफुटीची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत या आयोगाचे प्रमुख विवेक भीमनवार यांनी रजेवर जाण्याचा निर्णय घेतला ते योग्य झाले. त्यामुळे गेले १२ दिवस सुरू असलेल्या आंदोलनाची कोंडी फुटेल. आंदोलकांस भीमनवार यांचा राजीनामा हवा होता आणि तो दिला जाणार नाही हे सरकारने स्पष्ट केले होते. आंदोलकांना त्याबरोबर आणखीही बरेच काही हवे होते. त्यातील काही मागण्या सरकारने मान्य केल्या. काही आंदोलकांनी सोडून दिल्या. भीमनवार यांचा राजीनामा न घेता त्यांस चौकशी पूर्ण होईपर्यंत रजेवर पाठवणे हा मध्यममार्ग. सरकार आणि आंदोलक या उभयतांनी तो स्वीकारला. म्हणून तिढा सुटला. त्यासाठी सरकार आणि आंदोलकांनी एक-एक पायरी खाली उतरण्याची तयारी दाखवली. ही बाब निश्चितच शहाणपणाची. 'कॉक्रोच जनता पार्टी'चे आंदोलन देशभर पसरणार अशी लक्षणे असताना महाराष्ट्रात आणखी एक डोकेदुखी नको असेही कदाचित राज्यातील सत्ताधाऱ्यांच्या केंद्रीय धुरीणांस वाटले असणार. त्यामुळेही हे आंदोलन संपवणे महत्त्वाचे वाटले असेल. तेही योग्य. जे झाले त्यातून मध्यम मार्गाचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले. या मार्गाचा स्वीकार करून महाराष्ट्र सरकारने राज्यापुरता तरी प्रश्न मिटवला. आता कसोटी असेल ती केंद्रातील भाजप नेत्यांची. 'सीजेपी'पाठोपाठ काँग्रेस, डावे इत्यादी सगळेच आता मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आंदोलनाची तीव्रता वाढवतील. विरोधात असताना भाजपने हेच केले होते. तेव्हा विरोधक राजकारण करतात अशी छाती पिटण्यात काही अर्थ नाही. ते टाळून केंद्रीय धुरीणांस तडजोडीचा मार्ग स्वीकारावाच लागेल. अशी तडजोड आपण करू शकतो हे केंद्राने वेळोवेळी दाखवलेले आहेच. सत्तेवर आल्या आल्या जमीन हस्तांतरण, कृषी कायदे सुधारणा इत्यादी विधेयकांवर आपण माघार घेऊ शकतो हे सरकारने सिद्ध केलेले आहे. आता आपल्यातील ही तडजोड-क्षमता सरकारला पणास लावावी लागेल. तथापि आताची परिस्थिती 'नीट' आंदोलनापेक्षाही गंभीर आहे. त्या वेळी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा बळी देऊन सरकारला आपली मान वाचवता आली. आताचे निवडणूक आयोगाच्या उद्योगांचे प्रकरण तितके सोपे नाही.

ते तसे का नाही याचा ऊहापोह आधी. शिक्षणमंत्री हे घटनात्मक पद नाही. त्या पदावरील व्यक्तीस मुख्यमंत्री वा पंतप्रधान खड्याप्रमाणे दूर करू शकतात. मुख्य निवडणूक आयुक्तपदाचे तसे नाही. ते देशातील सर्वोच्च घटनात्मक पदांतील एक. त्या पदावरील व्यक्तीची नेमणूक जरी सरकारकडून होत असली तरी ती झाली की या पदावरील व्यक्ती पंतप्रधान वा मंत्रिमंडळास उत्तरदायी नसते. त्यामुळे त्यांस नारळ देण्याचा अधिकार पंतप्रधानांस नाही. बरे तो नाही; म्हणून श्रीमान ज्ञानेश कुमार यांस आहे तेथेच सुखेनैव राहू देणेही सरकारला परवडणारे नाही. जितका अधिक काळ ज्ञानेश कुमार मुख्य निवडणूक आयुक्तपदावर राहतील तितके त्यांच्या विरोधातील आंदोलन अधिक तीव्र आणि व्यापक होत जाईल. ते मोडून काढायचे उपाय योजावयाचे तर न्यायालयही किती काळ रक्षण करणार हा प्रश्न. सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलनासंदर्भातील आपल्या ताज्या निर्णयाद्वारे आपणास सरकारच्या इभ्रतीपेक्षा न्यायालयीन प्रतिष्ठा महत्त्वाची आहे, हे दाखवून दिले. त्यामुळे न्यायालयाकडे किती काणाडोळा करायचा याचा विचार करून सरकारला पावले उचलावी लागणार. दुसरीकडे आंदोलकांस मोकळे सोडावे तर अधिकच अनवस्था प्रसंग निर्माण होणार.

सरकारची हीच अडचण विरोधकांनी हेरली असून ज्ञानेश कुमारांच्या राजीनाम्यासाठी त्यामुळे त्यांच्याकडून दबाव अधिकच वाढत जाणार, हे उघड आहे. या सगळ्यात काही न करावे तर "बघा... सरकारसाठी ज्ञानेश कुमार किती महत्त्वाचे आहेत" हे विरोधक

उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका, मानहानी न होता माघार, नोकरशाहीचे मनोधैर्य, उत्तराधिकाऱ्यांचा 'उपयोगी'पणा आदी शक्यता सरकार पडताळत असले तरी, ज्ञानेश कुमार पदावर असेपर्यंत आंदोलनही दबणार नाही हे पुरेसे स्पष्ट आहे...

पुनःपुन्हा बोलून दाखवणार हा तिसरा मोठा धोका. ज्ञानेश कुमार आहेत म्हणून हे सरकार निवडणुका जिंकते, त्यांच्या अनुपस्थितीत जिंकण्याची सरकारला खात्री नाही, असे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न होणार यात शंका नाही. ते चित्र पूर्णत्वास जाईपर्यंत उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांचे बिगूल वाजेल. या निवडणुकांच्या आधी ज्ञानेश कुमार यांच्याबाबत काही निर्णय घेतला गेल्यास तो निवडणुकीचा मुद्दा होण्याची दाट शक्यता. तसा काही निर्णय नाही घेतला तरी निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी पुन्हा ज्ञानेश कुमारच असणार. म्हणजे ज्ञानेश कुमारांस धरून ठेवायचे तर विरोधक चावणार आणि त्यांस सोडले तर स्वतःलाच पळावे लागणार अशी ही स्थिती. ती हाताळण्यात आणखी एक गुंता आहे.

तो आहे नोकरशाही हा. विरोधकांच्या दबावास बळी पडून ज्ञानेश कुमारांस वाऱ्यावर सोडून दिले तर त्याचा सर्वांत मोठा फटका नोकरशाहीच्या मनोधैर्यास बसेल. सरकार आपणास गरजेपुरते वापरते आणि वेळ आली की फेकून देते असा संदेश त्यातून जाण्याचा धोका आहे. बहुतांश नोकरशाही म्हणजे वातकुक्कुट. सत्तेच्या वाऱ्याची दिशा पाहून हे नोकरशहा आपल्या चारापाण्याची बेगमी करायची/ नाही करायची ते ठरवतात. तेव्हा अशा या नोकरशाहीसमोर सरकार ज्ञानेश कुमारांस बळीचा बकरा बनवू शकत नाही. तसे होऊ दिले तर उर्वरित नोकरशहांवर परिणाम होणार. तसा तो झाल्यावर हे जिवाजी कलमदाने सरकारसाठी साहाय्यक ठरण्याची शक्यता कमी. अंगाशी आल्यावर वाऱ्यावर सोडणाऱ्या सरकारसाठी कोण कशाला काम करेल! हा एक भाग. दुसरे असे की समजा सरकारला ज्ञानेश कुमार यांचा त्याग करावा लागलाच तर त्यांच्या जागी येणारी व्यक्ती ही त्यांच्याइतकी 'उपयोगी' असेलच असे नाही. किंबहुना ती उपयोगी ठरण्याची शक्यता कमी. कारण ज्ञानेश कुमारांचे वा त्यांच्यामुळे सरकारचे पोळलेले तोंड पाहून तसेच त्यांचे जे काही झाले वा होत आहे ते पाहून त्यांचा उत्तराधिकारी ताकही फुंकून पिणार. म्हणजे त्या अर्थानेही सदर अधिकारी निरुपयोगीच. हे सर्व टाळण्यासाठी समजा सरकारने ज्ञानेश कुमारांस पूर्ण अभय देत पदरी राखले तरी आतापर्यंत ते जे काही करू शकले ते करणे यापुढच्या काळात त्यांना शक्य होण्याची शक्यता नाही. इतके तोंड पोळल्यावर खुद्द ज्ञानेश कुमारांसही पुढचा काळ आहे त्याच पदावर काढणे हे तारेवरच्या कसरतीपेक्षाही अवघड असेल.

अशा वातावरणी ज्ञानेश कुमार हे असून अडचण आणि नसून खोळंबा होत जाणार हे निश्चित. त्यांच्या वहाणेने विरोधक सरकारला ठेचण्याचा प्रयत्न करणार कारण मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या वहाणांस लागलेली घाण. अशा वेळी त्यातल्या त्यात आदरणीय मार्गाने या ज्ञानेश कुमारांस निरोप देणे, हे शहाणपणाचे असू शकेल. हे सरकारला ठाऊक नाही, असे अजिबात नाही. पण त्यास मानहानी नको आहे. आताही विरोधकांशी आम्ही बोलणारच नाही, असा आव जरी सरकार आणत असले तरी प्रत्यक्षात पडद्यामागून काही महत्त्वाच्या प्रशासकीय पदांवरील व्यक्ती विरोधकांशी संधान बांधू लागल्या असल्या तर आश्चर्य नाही. यातून सरकारचा अशक्तपणा तेवढा दिसून येईल. तो जसजसा दिसेल तसतसे विरोधक अधिक ताठर होत जातील. त्यातून सरकारची अधिकच कोंडी होईल.

तेव्हा ज्ञानेश कुमारांचे असणे या सरकारच्या अस्तित्वासाठी अपरिहार्य आहे असे चित्र निर्माण होणे सरकारला शोभणारे नाही. या मुद्द्यावर आणखी किती ताणायचे याचा विचार सरकारला करावा लागेल. ताण जितका अधिक तितकी जोखीम अधिक. ती वाढवायची की मुख्य निवडणूक आयुक्तांस दूर करून हे कुमार-'संभव' एकदाचे संपवायचे इतकेच काय ते पर्याय सरकारकडे आहेत.

'अघोषित आणीबाणी'च्या कार्यशैलीचे दुष्परिणाम...

लेख

हर्षवर्धन वानखेडे
दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या 'सेंटर फॉर पोलिटिकल स्टडीज'मध्ये पीएच.डी.संशोधक
harshjnu8@gmail.com

दिल्लीत जे काही झाले आणि सुरू आहे, ते अनेकांना माध्यमे/ समाजमाध्यमे यांतून समजलेले आहेच, 'अघोषित आणीबाणी'च्या आरोपाला प्रत्युत्तर म्हणून सत्ताधाऱ्यांनी 'अराजक' वगैरे म्हटले तरी, 'असहमतीचे गुन्हेगारीकरण आणि दडपशाहीचे सामान्यीकरण' ही आजची स्थिती लोकशाहीवर गंभीर दुष्परिणाम घडवणारी आहे. हे दुष्परिणाम कोणते?

'आणीबाणी'ची सुरुवात नेहमीच नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांच्या औपचारिक निलंबनाने होते असे नाही. राज्यसत्ता जेव्हा असहमती दडपण्यासाठी कायदा आणि सुव्यवस्थेचा आधार घेते, शांततापूर्ण आंदोलने आणि जमावाने एकत्र येण्याच्या जागा बंद करते आणि अटक, स्थानबद्धता व दीर्घकालीन न्यायालयीन खटल्यांची भीती नागरिकांच्या राजकीय सहभागाला आळा घालू लागते, तेव्हा प्रश्न फक्त नागरिकांना आंदोलन करण्याची परवानगी आहे की नाही, एवढाच राहात नाही. ते आपल्या असहमतीची अभिव्यक्ती प्रत्यक्षात आणि निर्भयपणे करू शकतात का, हा मूलभूत प्रश्न बनतो.

भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात राज्य आणि नागरिक यांच्यातील संबंधांचे स्वरूप बदलण्याचे आश्वासन होते. बाहेरून लादलेल्या परकीय सत्तेऐवजी नागरिकांना उत्तरदायी असलेली लोकशाही राज्यव्यवस्था अस्तित्वात येईल, ही त्यामागील अपेक्षा होती. मात्र, स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी निर्माण झालेल्या संस्था जेव्हा स्वातंत्र्यावरच मर्यादा आणण्याची साधने बनतात, शांततापूर्ण आंदोलने धोकादायक ठरवली जातात आणि उत्तरदायित्वाची मागणी केल्याबद्दल फौजदारी कारवाईला सामोरे जावे लागते, तेव्हा या स्वातंत्र्याच्या आश्वासनाचे काय होते? १० ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिल्ली येथे कॉक्रोच जनता पार्टीने (सीजेपी) आयोजित केलेल्या शांततापूर्ण आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर हे प्रश्न अधिकच महत्त्वाचे ठरतात.

पोलिसांच्या उत्तरदायित्वाचा प्रश्न

या एका आंदोलनाला रोखण्यासाठी १० ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत ५७ मेट्रो स्थानके बंद ठेवणे, ४० हजारांहून अधिक सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची तैनाती, जंतर-मंतर परिसरात बहुस्तरीय बॅरिकेडिंग आणि नाकेबंदी, २४० हून अधिक रेल्वेगाड्या रद्द करणे, शाळा-महाविद्यालये आणि मध्य दिल्लीतील बाजारपेठा बंद ठेवणे, इंटरनेटवर निर्बंध आणि सार्वजनिक सभांवर बंदी– अशा 'उपाययोजना' करून जनजीवनच जणू वेठीस धरले गेले. आंदोलनाला आळा घालण्यासाठी उभारलेल्या या सुरक्षा व्यवस्थेचे परिणाम सामान्य नागरिक आणि आंदोलकांना भोगावे लागले.

प्रत्येक ठिकाणी बॅरिकेडिंगसह सुमारे २५ ते ३० पोलीस कर्मचारी; त्यापैकी काहींकडे तर ओळख दर्शवणारी नामपट्टी नसल्याचेसुद्धा आढळून आले, तर काही सुरक्षा कर्मचाऱ्यांकडे सब-मशीन गन असल्याचे दिसून आले. पोलिस कर्मचाऱ्यांकडून आक्रमक आणि उद्धट वर्तन झाल्याचा आरोप काही महिलांनी केला, त्याचबरोबर त्यांच्या खासगी अवयवांवर स्पर्श केल्याचे, मोबाइल फोन आणि बॅग हिसकावून घेण्याचे आरोप पोलिसांवर करण्यात आले. तसेच, कॅनॉट प्लेस जवळ एक गट - ज्याचा कथित भाजप आणि विश्व हिंदू परिषदेशी संबंध असल्याचे म्हटले गेले, ज्यांना 'भाडोत्री संघ' असेही म्हटले गेले- हा समूह दावा करत होता की ते पोलिसांची सुरक्षा करीत आहेत! या गटातील व्यक्तींनी मुलींसह आंदोलनकर्त्यांवर क्रूरपणे हल्ले केले. या घटनांदरम्यान, हल्ले रोखण्यासाठी आणि आंदोलनकर्त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी हस्तक्षेप करण्याऐवजी पोलीस निष्क्रिय राहिल्याचे किंवा हस्तक्षेप करण्यास टाळाटाळ केल्याचे दिसून आले. यावरून पोलिसांच्या पक्षपाती वर्तनाबाबत आणि त्यांच्या उत्तरदायित्वाबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होतात, हेच सर्वोच्च न्यायालयात रविवारी झालेल्या विशेष सुनावणीतून स्पष्ट झाले.

'हे सारे होऊन गेले' म्हणून सोडून देता येणार नाही, कारण असहमतीचा आवाज दडपण्यासाठी 'कायदा आणि सुव्यवस्थे' चा राजकीय साधन म्हणून केला जाणारा वापर; परिणामी लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होण्याच्या व राजकीय असहमती व्यक्त करण्याच्या अधिकारांचा वापर केल्याबद्दल नागरिकांना दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागणे; अशा कारभारामुळे लोकशाहीत अधिकारांचे संरक्षण करण्याऐवजी लोकांवरच निर्बंध लादले जातात आणि लोकशाही सहभागालाच गुन्हेगारी स्वरूप देण्याची प्रक्रिया बळावते. याला अनेकजण 'अघोषित आणीबाणी' म्हणत आहेत आणि हीच जर सरकारची कार्यशैली असेल तर तिचे परिणाम काय होऊ शकतात हे आपण मुद्देसूदपणे लक्षात घेतले पाहिजे.

अधिकारच अमान्य?

पहिली समस्या म्हणजे शांततापूर्ण आंदोलनाला परवानगी नाकारण्यासाठी 'कायदा आणि सुव्यवस्थे' चा सरसकट आधार घेणे. सुरक्षितता, वाहतूक, पूर्वानुभव किंवा संभाव्य धोके यांसारखी कारणे पुढे करून 'जंतर मंतर' सारख्या सर्वज्ञात आंदोलनस्थळाची नाकेबंदी करणे आणि अनेक स्तरांवर बॅरिकेड्स उभारणे, ही बाब मुळातच भारतासारख्या घटनात्मक लोकशाहीत गंभीर प्रश्न उपस्थित करते. शांततापूर्ण विरोधाचा अधिकार मान्य असताना, संभाव्य धोक्यांच्या आधारे आंदोलनाच्या शक्यताच नष्ट करणे हे लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांशी विसंगत आहे.

निवडक अंमलबजावणी

दुसरी समस्या म्हणजे भारतीय न्याय संहितेतील (बीएनएस) तरतुदींच्या निवडक अंमलबजावणीतून निर्माण होणारी कायदेशीर अडवणूक आणि नागरिकांच्या संरक्षणासाठी असलेल्या कायद्याचाच दडपशाहीचे साधन म्हणून वापर होण्याची शक्यता. अशा परिस्थितीत कायद्याची अंमलबजावणी केवळ सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यापुरती मर्यादित राहत नाही, तर असहमती व्यक्त करणाऱ्या नागरिकांच्या लोकशाही सहभागावरही निर्बंध आणते. परिणामी, नागरिकांना संरक्षण देण्यासाठी असलेली कायदेशीर यंत्रणाच त्यांच्या अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याला आणि लोकशाही अधिकारांना मर्यादित करणारे माध्यम ठरू शकते.

यासाठीच कायद्यात बदल?

तिसरी समस्या म्हणजे आंदोलनाच्या मूळ मुद्द्यापासून सार्वजनिक चर्चेचे लक्ष विचलित करणे. इथे देशाच्या सर्वोच्च निवडणूक आयोगाच्या संबंधित कथित निवडणूक अनियमितता आणि त्याबाबत उत्तरदायित्व निश्चित करण्याची मागणी हा आंदोलनाचा केंद्रबिंदू असताना सरकारने चर्चेचा रोख अन्य मुद्द्यांकडे वळवण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसते. या संदर्भात हे लक्षात घ्यावे लागेल की, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवाशर्ती आणि पदावधी) अधिनियम, २०२३ नुसार विद्यमान तसेच माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांना दिवाणी व फौजदारी कार्यवाहीपासून संरक्षण दिले जाते. हे संरक्षण पदावरून निवृत्त झाल्यानंतरही लागू राहाते. कार्यकाळ संपल्यानंतरही त्यांना व्यापक कायदेशीर संरक्षण मिळणे असे दर्शवते की अशा प्रकारच्या अनियमिततांना संरक्षण देण्याच्या दृष्टीने ही तरतूद पूर्वनियोजितच होती की काय? मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत करण्यात आलेले बदलही घटनात्मक संस्थांच्या स्वायत्ततेचा आणि त्यांच्या उत्तरदायित्वाचा प्रश्न ऐरणीवर आणतात. या संस्थांच्या कामकाजावर प्रभावी देखरेख ठेवण्यासाठी आणि त्यांना उत्तरदायी बनवण्यासाठी पुरेशा घटनात्मक व संस्थात्मक यंत्रणा उपलब्ध आहेत का, हा लोकशाहीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

दडपशाहीचे सामान्यीकरण

चौथा पैलू म्हणजे संबंधित संस्थांकडून परिस्थिती सामान्य असल्याचे भासवण्याचा प्रयत्न. शहराची मोठ्या प्रमाणावर नाकेबंदी करणे, सार्वजनिक वाहतूक विस्कळीत करणे, शांततापूर्ण आंदोलनकर्त्यांना ताब्यात घेणे आणि नागरिकांना सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान राज्यसत्तेच्या अस्तित्वाची जाणीव करून देणे–या गोष्टी हळूहळू 'नवीन सामान्य' म्हणून रूढ केल्या जात आहेत. खरे संकट केवळ भारतातील कायदा-सुव्यवस्था यंत्रणांच्या क्रौर्यात नाही, तर अशा दडपशाहीचे आपल्या दैनंदिन जीवनातील सामान्य वास्तवात रूपांतर होण्यात आहे. हॅना अरेन्ट यांनी मांडलेल्या 'दुष्टतेच्या सामान्यीकरणा'च्या (इंग्लं ३८ ऱ्त्र ए५') संकल्पनेच्या संदर्भात पाहता, दडपशाहीचे भयावह स्वरूप केवळ तिच्या तीव्रतेत नसते; तर अन्यायकारक कृतींना रोजच्या प्रशासकीय व्यवहाराचा स्वाभाविक भाग मानण्याच्या प्रक्रियेतही असते. जेव्हा अपसामान्य दडपशाहीला सामान्य मानले जाऊ लागते, तेव्हा तिच्याविरोधात प्रश्न विचारण्याची आणि प्रतिकार करण्याची सामाजिक संवेदनशीलताही क्षीण होऊ शकते.

सरकारप्रणीत विसंवाद

या प्रक्रियेतील आणखी एक गंभीर पैलू म्हणजे नागरिकांच्या घटनात्मक आणि लोकशाही अधिकारांचा वापर केल्याबद्दल त्यांना दंडित करणे. याची अनेक रूपे आहेत. आंदोलनकर्त्यांना 'देशविरोधी', 'दिमागी नक्षल' अशा संज्ञांनी हिणवून त्यांच्या मागण्यांचे गांभीर्य कमी केले जाते. त्यांच्या मागण्यांच्या आशयाऐवजी त्यांच्या देशनिष्ठेवर आणि चारित्र्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते. त्याच वेळी, सार्वजनिक चर्चेत जाणीवपूर्वक गोंधळ आणि विसंवाद निर्माण करून या अराजकतेचाच राजकीय हत्यार म्हणून वापर केला जातो. त्यांच्याविरोधातील कारवाईला सामाजिक मान्यता मिळवून देण्याची शक्यता निर्माण केली जाते. या प्रक्रियेतून निर्माण होणारी भीती केवळ आंदोलनकर्त्यांपुरती मर्यादित राहत नाही; ती व्यापक समाजाच्या मानसिकतेत रुजवली जाते. परिणामी, नागरिकांमध्ये दडपशाहीची शक्यता आणि त्याचे परिणाम यांविषयी भीती निर्माण होते, ज्यामुळे लोकशाही सहभागावर आणि असहमती व्यक्त करण्याच्या स्वातंत्र्यावर अप्रत्यक्षपणे मर्यादा येऊ शकतात.

जेव्हा दडपशाही ही नियमित प्रशासकीय पद्धत बनते, असहमतीला गुन्हेगारीचे स्वरूप दिले जाते आणि घटनात्मक स्वातंत्र्यांचा वापर दिवसेंदिवस कठीण होत जातो, तेव्हा अघोषित आणीबाणी आकार घेते. सत्तेला जाब विचारणाऱ्या नागरिकांनाच कायदा व सुव्यवस्थेसाठी धोका ठरवणे आणि त्याच वेळी संस्थांना सार्वजनिक परीक्षणापासून संरक्षण देणे, हा लोकशाहीपुढील गंभीर धोका आहे. असहमतीचा अधिकार संविधानात मान्य असला, तरी त्याचा वापर केल्याबद्दल नागरिकांना धमकी, स्थानबद्धता किंवा खटल्यांना सामोरे जावे लागत असेल, तर लोकशाही औपचारिकरीत्या निलंबित झालेली नसली, तरी तिचा गाभा हळूहळू पोखरला जात असतो.

रब्बी हंगामासमोरील संकट किती गंभीर?

विश्लेषण

दत्ता जाधव
dattatray.jadhav@expressindia.com

राज्यात पुरेशा पावसाअभावी पिण्याच्या पाण्याचीच टंचाई असेल तर रब्बी पिकांना पाणी कुठून मिळणार, अशी स्थिती आहे...

रब्बी हंगामात लागवड क्षेत्र किती ?

राज्यात ऑक्टोबर, नोव्हेंबर हे रब्बी लागवडीचे महिने. काही ठिकाणी ऊसतोडणी झाल्यानंतर जानेवारी अखेरपर्यंत लागवडी होतात. राज्यभरचे रब्बी लागवड क्षेत्र सरासरी ५३ लाख ९६ हजार ९६९ हेक्टर असून त्यात सर्वाधिक सर्वाधिक लागवड होणारे पीक हरभरा (२१, ५२,० १४ हेक्टर), तर त्याखालोखाल रब्बी ज्वारी (१७, ५३, ११८ हेक्टर), गहू (१०, ४८, ८०७ हेक्टर), मका (२, ५८, ३३१ हेक्टर) असा क्रम लागतो. याखेरीज मटकी/ मसूरसह अन्य कडधान्ये (१, १७, ७५३ हेक्टर), करडई/ जवस/ तीळ/ सूर्यफूल/ मोहरी/ भुईमूग आदी तेलबिया (५५ हजार ६६० हेक्टर), ओट/ बार्ली/राजीगरासह इतर तृणधान्ये (११ हजार २९५ हेक्टर) अशी लागवडीची सरासरी भरते.

पाणी टंचाईमुळे लागवडीवर परिणाम ?

यंदाच्या पावसाळ्यात राज्यात सरासरीच्या तुलनेत १९ टक्के कमी पाऊस झाला आहे. पावसाळ्यात सरासरी ९०४.५ मिमी पाऊस पडतो, यंदा ८०४ मिमी पाऊस झाला आहे. राज्यातील ३६ पैकी २० जिल्ह्यांमध्ये कमी पावसाची नोंद झाली. सरासरीच्या तुलनेत सोलापूर जिल्ह्यात सर्वाधिक ५८ टक्के कमी पाऊस झाला आहे. बीडमध्ये ५१ टक्के, जालन्यात ४८ टक्के, हिंगोलीत ४९ टक्के, धाराशिव ४५ टक्के, अहिल्यानगर ४६ टक्के, परभणी, आमरावतीत ४० टक्के, अकोल्यात ३७ टक्के, सिंधूदुर्गमध्ये ३६ टक्के, नंदूरबारमध्ये ३९ टक्के, सातारा २८ टक्के, सांगली २४ टक्के, लातूर ३८ टक्के, नांदेड ३४ टक्के, वाशिम ३५ टक्के, अकोला ३७ टक्के, नागपूर २८ टक्के, चंद्रपूर २९ टक्के आणि वर्धा जिल्ह्यात सरसारीच्या तुलनेत २८ टक्के कमी पाऊस झाला आहे.

परतीचा पाऊसही नाही, म्हणून?

यंदा १९ सप्टेंबरपासून देशातून मोसमी पावसाचा परतीचा प्रवास सुरू झाला. ३ ऑक्टोबरपर्यंत निम्म्या राज्यातून आणि १० ऑक्टोबरपर्यंत संपूर्ण राज्यातून मोसमी पाऊस माघारी गेला आहे. सप्टेंबरचा अखेरचा आठवडा आणि ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात राज्याच्या विविध भागांत- प्रामुख्याने उत्तर महाराष्ट्राच्या पश्चिमेकडील भागात, पश्चिम महाराष्ट्रात, कोकण किनारपट्टीवर- मेघगर्जना, विजांच्या कडकडाटासह जोरदार पाऊस पडतो. यालाच काही भागात उतरा / हस्ताचा, हत्तीचा पाऊसही म्हटले जाते. खरीप पिकांमुळे शेत जमिनीतील ओलावा कमी झालेला असतो. परतीच्या पावसाने पुन्हा जमिनीचा ओलावा वाढतो. हा पाऊस रब्बी हंगामासाठी पोषक ठरतो. यंदा परतीचा पाऊस न झाल्यामुळे आणि पावसाळ्यात ऑगस्ट, सप्टेंबर महिन्यात खंड पडल्यामुळे जमिनीत मुळातच ओलावा कमी आहे. अशा स्थितीत रब्बी पेरण्या सरासरी ५० टक्क्यांपर्यंतच जाण्याचा अंदाज आहे.

रब्बी ज्वारीच्या पट्ट्यात तूट?

राज्यात रब्बी हंगामात मराठवाडा, विदर्भात हरभरा, तेलबियांची पिके घेतली जातात. विदर्भ, मराठवाड्यासह नाशिक, पश्चिम महाराष्ट्रात पाण्याची उपलब्धता असलेल्या ठिकाणी गहू लावला जातो. नाशिक, पुणे. अहिल्यानगर भागांत कांद्याची लागवड होते. कमी पाण्यात, एक - दोन पावसात येणारे ज्वारीचे पीक पश्चिम महाराष्ट्रात विशेष करून सोलापूर परिसरात मोठ्या प्रमाणावर घेतले जाते. मंगळवेढ्याला ज्वारीचे आगार मानले जाते. पण, यंदा सोलापुरात सरासरीच्या तुलनेत ५८ टक्के कमी पावसाची नोंद झाली आहे. तरीही अन्य भागात कमी पाण्यावर येणारी, पिकाला आली नाही तरी किमान चारा मिळेल, म्हणून शेतकरी ज्वारी लागवडीवर भर देण्याचा अंदाज आहे.

भाजीपाला, फळांची दरवाढ अटळ ?

राज्यातील धरणांमध्ये आजघडीला ७२.९९ टक्के पाणीसाठा आहे. पण गतवर्षी याच दिवशी ९०.७२ टक्के पाणीसाठा होता. म्हणजे गतवर्षीच्या तुलनेत २२ तूट. या उपलब्ध पाण्याचे नियोजन ऑगस्ट २०२७ अखेर पिण्याच्या पाण्यासाठी केले जाणार आहे. सरकारने उपलब्ध पाणी पिण्यासाठी राखून ठेवण्याला प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे धरणांतून शेतीला, सिंचनासाठी पाच- सहा पाण्याची आवर्तने मिळणार नाहीत. पाण्याची उपलब्धता पाहून एक- दोन आवर्तनेच मिळतील. पण हे पाणी गहू, ऊस, डाळिंब, द्राक्ष, केळी सारख्या फळबागांना पुरेसे नाही. अपुऱ्या पाण्यामुळे नदीकाठांवर भाजीपाला पिके घेणेही कठीण आहे. त्यामुळे लागवडच झाली नाहीतर बाजारात तुटवडा निर्माण होऊन भाजीपाल्यांची दरवाढ होण्याची शक्यता आहे.

अन्वयार्थ

कुकी-नागा संघर्षाला जाणीवपूर्वक खतपाणी?

मैतेई आणि कुकी यांमधील वांशिक संघर्षाने धगधगणाऱ्या मणिपूरमध्ये फेब्रुवारीपासून- म्हणजे राज्यात पुन्हा लोकनियुक्त सरकार आल्यापासून- नागा विरुद्ध कुकी संघर्षही पुन्हा सुरू झाला आणि यातून गेल्या दोन दिवसांत नऊ जणांचा बळी गेला. अनधिकृतपणे हा आकडा ११ असल्याचे सांगण्यात येते. कुकी - नागांमधील वांशिक हिंसाचारात आतापर्यंत ५० जण मारले गेले आहेत. परिस्थिती आटोक्यात येत असल्याचा कितीही दावा केंद्र व राज्य सरकार करत असताना या सीमावर्ती भागातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची लक्तरेच आजही दिसतात. केंद्रात व मणिपूरमध्येही भाजपची सत्ता. पण 'डबल इंजिन' असूनही वांशिक संघर्ष संपलेला नाही. वर्षभराच्या राष्ट्रपती राजवटीनंतर मणिपुरात लोकनियुक्त सरकार पुर्नस्थापित करण्यात आले. भाजपने नवे मुख्यमंत्री नेमले. सरकार स्थापनेत वांशिक समीकरण साधण्याचा प्रयत्न केला. पण सारे प्रयत्न व्यर्थ ठरल्याचेच एकूण चित्र आहे.

मणिपूरमधील वांशिक संघर्षाला तिहेरी कडा आहे. मे २०२३ मध्ये मणिपूरमध्ये मैतेई विरुद्ध कुकी-झो यांच्यात वांशिक संघर्ष सुरू झाला. त्यात ३०० पेक्षा अधिक ठार तर हजारो विस्थापित झाले. हा संघर्ष इतका टोकाला गेला की, हिंदू बहुसंख्य असलेल्या मैतेईंचे वास्तव्य असलेल्या राजधानी इम्फाळमध्ये कुकी आजदेखील पाऊल टाकू शकत नाहीत. मैतेई कुकींचे प्राबल्य असलेल्या डोंगराळ भागात प्रवेश करू शकत नाहीत. मैतेई - कुकी-झोंमधील संघर्ष आटोक्यात आला नसतानाच फेब्रुवारी महिन्यापासून कुकी विरुद्ध नागा असा वांशिक संघर्ष सुरू झाला. कुकी आणि नागा यांच्यात १९९३ ते १९९७ दरम्यान झालेल्या वांशिक संघर्षात एक हजारापेक्षा अधिक लोक जिवास मुकले होते तर लाखो लोक विस्थापित झाले. आता पुन्हा, कुकी व नागांमधील संघर्षाला जाणीवपूर्वक खतपाणी घालण्यात आल्याचा आरोप होतो आहे.

परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे. या राज्यात जनगणनेची पहिल्या टप्प्यातील प्रक्रियाही लांबणीवर टाकावी लागली. जनगणनेपूर्वी राष्ट्रीय नागरिकत्व पडताळणी (एन.आर.सी.) करावी, अशी मागणी होत आहे. भाजपला नेमके हेच हवे आहे. मणिपूर विधानसभेची निवडणूक मार्चमध्ये अपेक्षित आहे. सध्याची एकूण परिस्थिती लक्षात घेता ही निवडणूक वेळेत होण्याची शक्यता कमीच वाटते. भाजपला पुन्हा सत्ता मिळण्याची खात्री झाली तरच विधानसभा निवडणूक होईल. अन्यथा राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते. मणिपूरमधील संघर्षाकडे धार्मिक अंगाने बघण्याच्या केंद्र सरकार व गृह मंत्रालयाच्या भूमिकेमुळेच हा प्रश्न चिघळल्याचा आरोप होतो. मैतेई हे बहुसंख्य हिंदू असून, त्यांचा भाजपला पाठिंबा असतो. दुसरीकडे, कुकी-झो व नागादेखील बहुसंख्य ख्रिश्चन समाजाचे. वांशिक संघर्षात सरकारने मैतेईंना झुकते माप दिल्याचा आरोप अन्य समाजांकडून केला जातो.

जम्मू आणि काश्मीरचा प्रश्न तसेच नक्षलवाद हे देशासमोरील मुख्य प्रश्न केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या कठोर भूमिकेमुळे कायमस्वरूपी निकाली निघाल्याचा दावा भाजपकडून केला जातो. पण मणिपूर साडेतीन वर्षे वांशिक संघर्षात होरपळत असताना केंद्राला तोडगा काढता आलेला नाही. केंद्रीय अल्पसंख्याक व संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी मणिपूरमधील वांशिक संघर्षावर कायमस्वरूपी तोडगा हा सैन्य दलाच्या बळापेक्षा तिन्ही समाजांनी संवादातून सोडवावा, अशी भूमिका मांडल्याने नागरी संघटनांनी या वक्तव्याचा निषेध केला आहे. दहशतवादी किंवा बंडखोर संघटनांच्या कारवायांकडे केंद्र सरकारकडून कानाडोळा केला जात असल्याचा आरोप १४ विविध नागरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केला असून नुसत्या चर्चेतून हा प्रश्न कसा सुटणार, असा सवाल केला आहे. खरे तर मैतेईंना 'आदिवासी' दर्जा देण्याच्या निर्णयापासून वांशिक संघर्ष सुरू झाला तेव्हाच केंद्र व राज्याने दोन्ही समाजांना चर्चेसाठी एकत्र आणणे आवश्यक होते. पण चर्चा घडवून आणण्यासही केंद्राने विलंब लावला. केंद्र व राज्याने धार्मिक राजकारणात न अडकता स्वच्छ व नेमकी भूमिका घेतल्याशिवाय हा वांशिक संघर्ष आटोक्यात येणे शक्य नाही. सीमेपलीकडून होणारा अंमली पदार्थांचा व्यापार, बंडखोरांना सहज उपलब्ध होणारी शस्त्रे, शेजरील टपून बसलेली राष्ट्रे अशा कोंडीतून सर्वमान्य तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न झाले तरच मणिपूरमधील धग कमी होऊ शकेल.

अगर आवाज की अनदेखी करने वालों को सुनाना है, तो आवाज बहुत ऊंची करनी होगी।

– भगत सिंह

लोकतंत्र की खातिर

इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि आज देश में एक अहम मुद्दे पर लोग सड़क पर उतर कर अपने सवालों का जवाब मांग रहे हैं, सरकार के रवैये को कठघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो वहीं लोकतंत्र की पहरेदारी की दावा करने वाली सरकार आम जनता की आवाज को खामोश करने की कोशिश कर रही है। यह विचित्र है कि जब लोग शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो बिना किसी तर्क या उकसावे के पुलिस उन्हें हिरासत में लेने में देरी नहीं करती है। जबकि देश का लोकतांत्रिक ढांचा संवैधानिक रूप से जनता को यह अधिकार देता है कि वह किसी मसले पर अपनी राय जाहिर कर सके और सरकार की कमियों पर अंगुली उठा सके। मगर यह अफसोसनाक है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने पहुंचे बहुत सारे लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जबकि प्रदर्शन की प्रकृति के लिहाज से देखें, तो पुलिस को इतना सख्त रुख अख्तियार करने की जरूरत नहीं थी। हैरानी की बात यह भी है कि पुलिस की मौजूदगी के बावजूद कुछ असामाजिक तत्त्व भी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसक तरीके से पेश आ रहे थे।

इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को निर्देश दिया कि शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने वाले लोगों को अवैध रूप से हिरासत में न लिया जाए। कायदे से होना यह चाहिए था कि सरकार को खुद इस जिम्मेदारी का बोध होता कि वह आम जनता के विरोध जताने के अधिकार की कद्र करती। लोगों की मांगों पर विचार किया जाता और शिकायतों को दूर करने की कोशिश की जाती। मगर यह अफसोस की बात है कि सरकार ने विरोध प्रदर्शन के लोकतांत्रिक अधिकारों को न सिर्फ सीमित करने की कोशिश की, बल्कि प्रकारांतर से उसने जनता को अपना प्रतिपक्ष मान लिया लगता है। गौरतलब है कि शनिवार को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए हजारों की संख्या में पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों को तैनात किया गया, वहीं बिना किसी मजबूत आधार के हजारों लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके अलावा, राजधानी दिल्ली में पिछले साढ़े तीन दशक से ज्यादा समय से देश भर के आंदोलनों का केंद्र रहे जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शनों के लिए निर्धारित स्थलों की सूची से हटा दिया गया। सरकार ने तीन अन्य जगह निर्धारित की है, लेकिन बिना किसी मजबूत कारण के इतने बड़े बदलाव के पीछे लोकतांत्रिक विरोध के स्वर को सीमित करने की मंशा साफ झलकती है।

यह बेवजह नहीं है कि मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण यानी एसआइआर में व्यापक पैमाने पर लोगों के नाम काटे जाने के मसले से आम नागरिकों के बीच उठे विरोध का दायरा अब और ज्यादा फैलता जा रहा है तथा सरकार की मंशा को लेकर भरोसा कम होता दिख रहा है। सोमवार को विपक्षी दलों के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने जिस तरह 'मार्च फार डेमोक्रेसी' के तहत सुप्रीम कोर्ट तक जुलूस निकाला, वह सरकार के रवैये के प्रति बढ़ते असंतोष का ही उदाहरण है। अफसोस की बात यह है कि एसआइआर में लाखों लोगों के नाम काटे जाने सहित अन्य त्रुटियों के मसले पर उठे सवालों का अब तक कोई संतोषजनक जवाब सामने नहीं आया है। जवाबदेही तय करने के बजाय लोगों के बीच उभरे विरोध की अनदेखी या प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्ती करना लोकतंत्र की किस परिभाषा में आता है? इस दौरान सरकार की ओर से संवाद के जरिए समाधान की तलाश को लेकर जिस स्तर की उदासीनता दिखी है, उसने समस्या को और जटिल ही बनाया है।

नाकामी की त्रासदी

मणिपुर में फिर से तेज हो रही हिंसक घटनाएं इस बात का संकेत है कि राज्य में शांति एवं सौहार्द की कमजोर पड़ी नींव को नए सिरे से मजबूत करने के प्रयासों को धरातल पर उतारने में संवेदनशीलता, तत्परता और गंभीरता का अभाव बना हुआ है। लंबे समय से जातीय तनाव, आपसी अविश्वास और टकराव का सामना कर रहे इस राज्य में हालात सामान्य होने की उम्मीदें बार-बार टूटती रही हैं। इसी क्रम में बीते शुक्रवार को कामजोंग, उखरुल और कांगपोकपी जिलों में शुरू हुई हिंसा में नौ लोगों की मौत हो गई। ऐसे में यह सवाल अहम है कि आखिर राज्य में हिंसा का सिलसिला क्यों नहीं थम रहा? सरकार के तमाम दावों के बावजूद शांति बहाली की कोशिशें सतही क्यों साबित हो रही हैं? सुरक्षाबलों की इतनी बड़ी तैनाती के बावजूद अगर हिंसक घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है, तो इसे किस तरह देखा जाएगा। जाहिर है, आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाने के साथ-साथ जातीय संघर्ष की जड़ में जाकर समाधान के रास्ते तलाशने होंगे।

मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच मई, 2023 में शुरू हुए जातीय संघर्ष ने राज्य के सामाजिक ताने-बाने को गहरी चोट पहुंचाई है। तब हिंसा में बड़ी संख्या में लोगों की जान गई थी और हजारों लोगों को अपने घर छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी। ऐसे हालात में हिंसा की कोई भी नई घटना तनाव को फिर बढ़ा देती है। खबरों के मुताबिक, पिछले सप्ताह हुई हिंसा में एक व्यक्ति की हत्या कर हमलावर उसके सिर को काटकर अपने साथ ले गए, जिससे क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। हिंसा के लगातार बने रहने के पीछे दोनों समुदायों के बीच भरोसे की कमी, विस्थापित लोगों की घर वापसी, सुरक्षा और पुनर्वास जैसे मसलों का स्थायी हल न हो पाना है। इसके अलावा जमीन, पहचान और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े विवादों ने भी समस्या को जटिल बना दिया है। शांति बहाली के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हिंसा के मामलों की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों को सजा मिले तथा स्थानीय समुदायों और सामाजिक प्रतिनिधियों को विश्वास बहाली के प्रयासों में शामिल किया जाए।

खेत से थाली तक की कमजोर कड़ियां



देश में कृषि को लाभकारी बनाने के लिए उत्पादन के साथ प्रसंस्करण, भंडारण, गुणवत्ता और बाजार तक आसान पहुंच जरूरी है। किसान को मूल्यवर्धन में उचित हिस्सेदारी मिलनी चाहिए।

बलवंत राज मेहता

भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन कृषि अर्थव्यवस्था की सबसे कमजोर कड़ी लंबे समय तक खेत के बाद ही शुरू होती रही। किसान फसल पैदा करता है, मंडी तक पहुंचाता है और फिर मूल्यवर्धन का बड़ा हिस्सा दूसरे हिस्सेदारों के खाते में चला जाता है। फल-सब्जियों जैसी जल्दी खराब होने वाली उपज का एक हिस्सा परिवहन और भंडारण की कमजोर व्यवस्था में नष्ट हो जाता है। जो बचता है, वह भी अक्सर कच्चे माल के रूप में बिकता है। खाद्य प्रसंस्करण की नीति इसी खाई को पाटने की कोशिश रही है। 'मेगा फूड पार्क' इसी सोच का बड़ा प्रयोग था। यह योजना वर्ष 2008 में शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य केवल कुछ बड़े कारखाने खड़े करना नहीं, बल्कि किसान से लेकर प्रसंस्करणकर्ता, वितरक और बाजार तक एकीकृत मूल्य शृंखला तैयार करना था। योजना में संग्रह केंद्र, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र, केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र, प्रशीतन शृंखला और उद्यमियों के लिए विकसित भू-खंड जैसी साझा सुविधाओं की परिकल्पना की गई। यानी लक्ष्य कृषि उपज को खेत से सीधे अधिक मूल्य वाले बाजार तक पहुंचाना था।

सरकार ने इस योजना के तहत सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत का पचास फीसद और कठिन, पहाड़ी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पचहत्तर फीसद तक पूंजीगत अनुदान दिया, जिसकी अधिकतम सीमा पचास करोड़ रुपए थी। यह सरकारी कारखाना खड़ा करने की योजना नहीं थी, बल्कि निजी निवेश से प्रसंस्करण का ढांचा तैयार करना इसका लक्ष्य था। डेढ़ दशक से अधिक समय बाद इसकी तस्वीर मिश्रित है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अनुसार, 41 मेगा फूड पार्कों को सहायता दी गई। उनमें पच्चीस परिचालन में हैं। मंत्रालय की वेबसाइट इस योजना को अप्रैल 2021 से नए परियोजनाओं के लिए बंद बताती है, जबकि जारी परियोजनाओं की प्रतिबद्ध देनदारियां जारी रखने का प्रावधान है। इस लिहाज से योजना को पूरी तरह सफल नहीं कहा जा सकता है। सवाल यह है कि स्वीकृति और वास्तविक आर्थिक गतिविधि के बीच कितनी दूरी रह गई?

राज्यों में भी अंतर साफ है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में कई फूड पार्क परिचालन तक पहुंचे हैं। चित्तूर का श्रीनी मेगा फूड पार्क और उत्तराखंड के पतंजलि तथा हिमालयन मेगा फूड पार्क रोजगार एवं प्रसंस्करण गतिविधि के उदाहरण हैं। हालांकि इनमें रोजगार के आंकड़ों की तुलना सावधानी से करनी चाहिए, क्योंकि कुछ में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार दोनों शामिल हैं। यही योजना की मूल चुनौती है। किसी पार्क का स्वीकृत सूची में होना और उसका वास्तव में उत्पादन, निवेश, किसान-संपर्क तथा बाजार से जुड़ना दोनों अलग बातें हैं। केवल भवन और मशीनें पर्याप्त नहीं, नियमित कच्चा माल, बिजली, प्रशीतन भंडारण, कुशल श्रम, गुणवत्ता नियंत्रण, वित्त, खरीदार और परिवहन भी जरूरी हैं।

फिर भी ऐसे ढांचे की जरूरत पर संशय की गुंजाइश बहुत कम है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार, वर्ष 2023 में फसल कटाई के बाद खेत, परिवहन, भंडारण, थोक और प्राथमिक प्रसंस्करण के स्तरों पर दुनिया में 13.3 फीसद खाद्यान्न की हानि हुई। फल और सब्जियों में यह दर



25.4 फीसद थी। ये वैश्विक आंकड़े भारत की स्थिति का प्रत्यक्ष अनुमान नहीं हैं, लेकिन वे जल्दी खराब होने वाली उपज के लिए बेहतर भंडारण, परिवहन और प्रसंस्करण के महत्त्व को स्पष्ट करते हैं। भारत फल और सब्जियों के उत्पादन में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है। मगर उत्पादन में आगे रहना और मूल्यवर्धित खाद्य का बड़ा निर्यातक होना अलग बातें हैं। कृषि विविध है, घरेलू बाजार विशाल है और प्रसंस्करण के लिए कच्चा माल उपलब्ध है। मगर वैश्विक बाजार में सस्ता उत्पादन पर्याप्त नहीं, इसके अलावा खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता, पैकेजिंग, निर्यात मानक और समय पर आपूर्ति भी जरूरी हैं।

> देश की कृषि अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ने के बावजूद किसान को उपज के बाद होने वाले मूल्यवर्धन का पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाता। इसी कमी को दूर करने के लिए वर्ष 2008 में मेगा फूड पार्क योजना शुरू की गई थी। संग्रह, प्राथमिक प्रसंस्करण, प्रशीतन शृंखला, पैकेजिंग और बाजार तक एकीकृत व्यवस्था बनाने की परिकल्पना के बावजूद डेढ़ दशक बाद इसके परिणाम मिश्रित रहे। इस दौरान कुल 41 परियोजनाओं को सहायता मिली, जिनमें पच्चीस परिचालन में पहुंचीं। इस योजना के अनुभव ने स्पष्ट किया कि केवल बड़े औद्योगिक ढांचे पर्याप्त नहीं। किसानों, प्रसंस्करण इकाइयों, खरीदारों और बाजार के बीच मजबूत संपर्क भी जरूरी है। साथ ही छोटे प्रसंस्करण केंद्रों, किसान उत्पादक संगठनों और गुणवत्ता व्यवस्था को भी मजबूत करना होगा।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन वर्ष 2014-15 के 1.34 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2023-24 में 2.24 लाख करोड़ रुपए हो गया। वर्ष 2014-15 से 2024-25 के बीच इस क्षेत्र में 7.33 अरब डालर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया। इसी अवधि में कृषि-खाद्य निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य की हिस्सेदारी 13.7 फीसद से बढ़कर 20.4 फीसद हो गई। हालांकि खाद्य प्रसंस्करण को अब कृषि नीति का सहायक क्षेत्र मानना पर्याप्त नहीं है। यह विनिर्माण, रोजगार, निर्यात और किसान आय से जुड़ा है। छोटे किसान तभी लाभ पाएंगे, जब उन्हें संग्रह, प्राथमिक प्रसंस्करण, गुणवत्ता मानकों, ऋण, संगठित खरीदारों और बाजार तक पहुंच मिले।

वर्ष 2021 में मेगा फूड पार्क योजना को नए परियोजनाओं के लिए बंद करने के बाद सरकार ने अन्य ढांचों पर जोर बढ़ाया। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत क्लस्टर, एकीकृत प्रशीतन शृंखला और प्रसंस्करण अवसंरचना को बढ़ावा दिया गया। सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों और उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की योजनाओं ने भी दायरा बढ़ाया। जरूरत इसी बहुस्तरीय ढांचे की है। किसान के गांव या उत्पादन क्षेत्र के पास संग्रह और प्राथमिक प्रसंस्करण हो, तहसील या जिले में प्रशीतन भंडारण और पैकेजिंग की सुविधा हो तथा बड़े औद्योगिक केंद्र राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार से जुड़े हों। इससे परिवहन लागत और बर्बादी घट सकती है तथा किसान को कच्चे माल की कीमत से आगे मूल्यवर्धन में हिस्सेदारी मिल सकती है। सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठन और छोटे उद्यम इस कड़ी को मजबूत करने में भूमिका निभा सकते हैं।

सरकारी सफलता की कसौटी यह होनी चाहिए कि कितनी इकाइयां उत्पादन कर रही हैं, कितने किसान जुड़े हैं, किसानों को कितना अतिरिक्त मूल्य मिला, कितनी उपज बची, कितना निजी निवेश आया, कितना निर्यात हुआ और कितने स्थायी रोजगार सृजित हुए। किसी योजना की आर्थिक सफलता कागजी स्वीकृति से नहीं, जमीन पर चलती गतिविधि से मापी जानी चाहिए। मेगा फूड पार्क ने भारत को एक महत्त्वपूर्ण सबक दिया है: कृषि और उद्योग अलग नहीं हैं। आम, टमाटर, दूध, मछली, मसाले या अनाज की आर्थिक क्षमता खेत में उत्पादन के साथ समाप्त नहीं होती। विज्ञान, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, परिवहन, गुणवत्ता और बाजार से जुड़ने पर उसका मूल्य कई गुना बढ़ सकता है। मगर इसके लिए नीति की घोषणा से अधिक जरूरी है उसका समयबद्ध और पारदर्शी क्रियान्वयन।

भारत के सामने अब अवसर बड़ा है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का विस्तार हो रहा है और प्रसंस्कृत खाद्य की निर्यात हिस्सेदारी भी बढ़ी है। मगर क्षमता और उपलब्धि के बीच की दूरी अभी बनी हुई है। अगली कृषि क्रांति केवल अधिक उत्पादन की नहीं, अधिक मूल्यवर्धन की होनी चाहिए। इसके लिए बड़े फूड पार्कों के साथ हजारों छोटे और मध्यम प्रसंस्करण केंद्रों, मजबूत प्रशीतन शृंखला, बेहतर गुणवत्ता व्यवस्था और वैश्विक बाजार से विश्वसनीय जुड़ाव की जरूरत होगी। खेत से दुनिया की थाली तक भारत की यात्रा तभी पूरी होगी, जब किसान मूल्य शृंखला का भागीदार बने। मेगा फूड पार्क उस दिशा में बड़ा प्रयोग थे, ऐसी व्यवस्था चाहिए, जिसमें खेत की उपज उद्योग में मूल्य पाए और स्थानीय उत्पाद दुनिया के बाजार में प्रतिस्पर्धी बने। भारत की खाद्य-प्रसंस्करण क्रांति इसी जुड़ी हुई शृंखला से आएगी।

सपनों का संसार

अशोक कुमार

मानव जीवन की उत्पत्ति के साथ ही उसकी मनोवेशा के कई आयाम उसे अपनी परिधि में बांधे हुए है। व्यक्ति अपनी दिनचर्या के विभिन्न पहलुओं से आबद्ध होकर उसके निर्वहन की दिशा में सतत नैसर्गिक भूमिका में लैस होते हैं। इस दौर में उसके कार्यों में रचनात्मक और नकारात्मक अंशों के मिश्रण से अनुभूति अध्याय के अनेक मर्म निरंतर प्रकट होते रहते हैं। व्यक्ति के जाग्रत अवस्था में रोजमर्रा के वैसे इच्छित मनोभाव, जो मूर्तरूप नहीं ले पाते, वे हमारे अचेतन मन के कोश में संग्रहित हो अक्सर सपनों के रूप में उजागर होते हैं। सपनों के सरोवर में हमारी कल्पनाओं के अंश भी निरंतर यात्रा में लीन रहते हुए मस्तिष्क में जमा हो जाते हैं।

दरअसल, सपने आंखें बंद होने पर खुलने वाली एक ऐसी दुनिया है, जिसे किसी ने देखा नहीं, बल्कि चेतन मन में सिर्फ महसूस किया है। जागी हुई हालत में हम जो देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं या किसी कार्य को अधूरा छोड़ देते हैं, वही रात में अपने रूप बदलकर हमारी अचेतन अवस्था में सपने बुनने लगता है। इस दौर में हमारा मन कई उड़ान भरता है, जैसे कि कभी हम किसी के साथ खुशी के पल जी रहे हैं, कभी किसी से उलझ रहे हैं या कभी बचपन के आंगन में पहुंच कर भूली-बिसरी स्मृतियों में सजीव हो जाते हैं। दिन में समाज से, रिश्तों से, खुद से समझौता कर लेने के बाद जब रात में शरीर नींद में लीन होता है, हमारा संवेदनशील मन ईमानदार हो, तो बीते पलों की आहट सुनते हुए दिन में दबी इच्छा रात में चित्र का आकार ले लेती है। इसका सिरा अतीत का कोई संदर्भ भी हो सकता है।

पूर्व राष्ट्रपति कलाम युवा पीढ़ी को उत्साहित करते हुए कहा करते थे कि 'रात के सपने नींद की हालत में बिस्तर पर भले आते हों, लेकिन नींद से बाहर जागी हुई स्थिति में वैचारिक सपने उस युवक को सोने नहीं देते,जिसने अपने भविष्य निर्माण का दृढ़ संकल्प लिया है। मनोविज्ञान के जनक सिगमंड फ्रायड का कथन है कि 'सपनों की व्याख्या ही अचेतन मन को समझने का मार्ग है।' वे मानते थे कि सपनों की नगरी में हमारी सुषुप्त या दमित इच्छाओं का भेष बदलकर किया गया प्रदर्शन व्यक्ति का चिंतन प्रतिबिंब है।

अध्ययन बताते हैं कि स्वप्न और कल्पना में आंतरिक समन्वय की कड़ी बेहद प्रभावशाली है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सपनों की सूक्ष्म तरंग को लोकहित के लिए आविष्कारों की जननी कहा जा सकता है। व्यक्ति भी इसी प्रक्रिया पथ पर चलकर भविष्य में उद्यमी, विद्यार्थी, डाक्टर, अभियंता, शिक्षक, प्रशासक या वैज्ञानिक बनने का सपना देखता है। कोई युवा कलाकार या खिलाड़ी बनने का सपना देखता है, क्योंकि स्वप्न उसके भीतर भविष्य का एक मानचित्र रेखांकित करते हुए उसे वर्तमान में परिश्रम करने की प्रेरणा भी देता है। निश्चय ही सपने कल्पना को विस्तारित भूमि प्रदान करते हैं। इस दौर में सपने व्यक्ति को असफलता के बाद भी प्रयास जारी रखने के साहस सूत्र से युक्त रखते हैं।

कभी-कभी दिवास्वप्न की स्थिति के शिकार व्यक्ति धरातलीय मूल्यों और श्रम से अलग होकर आत्ममुदित रहते हैं। ऐसे में उन्हें मनोवांछित सफलता ग्रहण करने में फिसलन मिलती है और वे व्यामोह की व्यापक विडंबना में वह सब कुछ खो देते हैं, जिसकी उम्मीद वे बनाए रहते हैं। इसलिए जरूरी है कि व्यक्ति को सपने के साथ धैर्य और असफलता को स्वीकार करने की क्षमता तथा मर्म को पहचानना चाहिए। नींद के दौरान आने वाले भयावह सपने या बार-बार आने वाले दुस्स्वप्न व्यक्ति की नींद और मानसिक शांति को प्रभावित कर सकते हैं। अगर ऐसे अनुभव लगातार हों और दैनिक जीवन पर नकारात्मक असर डालें, तो चिकित्सक की सलाह लेना भी उचित है।

सपना और संकल्प भी एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों समान नहीं हैं। सपना बताता है कि हमें कहां पहुंचना है, जबकि संकल्प बताता है कि वहां पहुंचने के लिए हमें क्या क्या यत्न करना चाहिए। युवा अवस्था सपने देखने की सबसे सुंदर अवस्था है, जिनके पास ऊर्जा, कल्पना और परिवर्तन की अधिक क्षमता होती है। मगर आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया की चमक-दमक ने कई बार सफलता की एक अवास्तविक तस्वीर भी खींच दी है। दूसरों की उपलब्धियों से अपनी तुलना करने के बजाय युवाओं को अपने सामर्थ्य और रुचि के अनुसार लक्षित सपने देखने चाहिए।

> **दुनिया मेरे आगे**
>
> सपना बताता है कि हमें कहां पहुंचना है, जबकि संकल्प बताता है कि वहां पहुंचने के लिए हमें क्या यत्न करना चाहिए। युवावस्था सपने देखने की सबसे सुंदर अवस्था है। मगर आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया की चमक-दमक ने सफलता की एक अवास्तविक तस्वीर भी खींच दी है।

यह समझने की जरूरत है कि सफलता अचानक नहीं मिलती। उसके पीछे वर्षों का अनुशासन, संघर्ष, असफलता और निरंतर सीखना आवश्यक है। बड़े सपने देखना चाहिए, लेकिन छोटे-छोटे कदमों से उसे पूरा करना ही सपने का सम्मान है। सपनों का संसार मनुष्य की चेतना का अत्यंत सुंदर और रहस्यमय संसार है। सपने ही वह पहली चिंगारी हैं, जिससे उपलब्धि की अग्नि प्रज्वलित की जा सकती है, लेकिन केवल सपने देखने से जीवन का पूरा निर्माण नहीं होता, बल्कि सुनहरे सपनों को संकल्प, संकल्प को योजना और योजना को कर्म में बदलने से ही कुछ सार्थक हासिल होता है। वास्तव में मनुष्य की महानता इस बात में नहीं है कि वह कितने बड़े सपने देखता है, बल्कि इसमें है कि वह अपने सपनों को जीवन पथ पर आरूढ़ करने के लिए कितनी ईमानदारी, धैर्य और निरंतरता से परिश्रम करता है। इसलिए सपने देखना बंद न हो, बल्कि ऐसे सपने से साक्षात्कार हो, जो हमें बेहतर मनुष्य बनाएं, हमारे परिवार और समाज के लिए उपयोगी बनाते हुए देश के विकास में योगदान देने की प्रेरणा दे। कल्पना के सांचे में ढाले गए सपने भविष्य की सिर्फ पारदर्शी छवि नहीं हैं, बल्कि वे सुंदर भविष्य के निर्माण का शीतल सूर्योदय है।

अधिकार के बरक्स



गिरफ्तारी पुलिस की सुविधा नहीं, बल्कि संविधान की कसौटी पर परखी जाने वाली शक्ति है। किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने से उसकी स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और परिवार प्रभावित होते हैं। इसलिए गिरफ्तारी का आधार बताना महज कानूनी औपचारिकता नहीं, बल्कि नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। इसके बावजूद जब पुलिस पूछताछ के नाम पर थाने बुलाकर मामले की जानकारी देने से बचती है, तब कानून और व्यवहार के बीच की खाई उजागर होती है। एफआइआर में गंभीर धाराएं जोड़ने के दुरुगामी परिणाम होते हैं। इसलिए उनके इस्तेमाल में पारदर्शिता और गिरफ्तारी के फैसले में जवाबदेही जरूरी है। छोटे-मोटे मामलों में, जहां फरार होने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ के वास्तविक खतरा न हो, वहां गिरफ्तारी के बजाय नोटिस और जांच में सहयोग को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। डिजिटल शिकायत व्यवस्था से भी पारदर्शिता बढ़ सकती है। पुलिस की शक्ति अपराध नियंत्रण के लिए जरूरी है, लेकिन उसका मनमाना इस्तेमाल लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं। नागरिकों को उनके अधिकार बताना और गिरफ्तारी के कारण स्पष्ट करना कानून के प्रति भरोसा बढ़ाएगा।

– विभूति बुपक्या, दिल्ली

दिखावे के समारोह

आज सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं, फिर भी सामाजिक दबाव और परंपराओं के नाम पर बेटी के पिता को शादी में सोना देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। भले ही वर पक्ष खुलकर मांग न करे, लेकिन 'समाज क्या कहेगा' की चिंता और दिखावे की होड़ कन्या पक्ष पर आर्थिक बोझ डालती है। विडंबना यह है कि समाज कुछ दिनों तक चर्चा करके आगे बढ़ जाता है, मगर कर्ज चुकाने का बोझ परिवार वर्षों तक उठाता रहता है। सोना न तो सुखी वैवाहिक जीवन की गारंटी है और न ही रिश्तों की मजबूती का पैमाना। प्रेम, विश्वास, सम्मान और आपसी समझ ही दांपत्य जीवन का आधार हैं। इस कुरीति को बदलने की जिम्मेदारी दोनों पक्षों की है। वर पक्ष को सोना न लेने की पहल करनी चाहिए और कन्या पक्ष को दिखावे के दबाव से मुक्त होना चाहिए। विवाह दो परिवारों का मिलन है, सोने के प्रदर्शन की प्रतियोगिता नहीं। बेटी को कर्ज नहीं, सम्मान और सुरक्षित भविष्य देना चाहिए।

– निराली ठोरिया, मोरबी, गुजरात

अवसाद के पांव

युवाओं को देश की सबसे बड़ी ताकत बताया जा रहा है, लेकिन उनमें बढ़ता मानसिक तनाव गंभीर चिंता का विषय है। बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव, भविष्य की अनिश्चितता, पारिवारिक अपेक्षाएं और रिश्तों में उलझनें युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही हैं। यूनिसेफ के अनुसार, भारत में 15 से 24 वर्ष की आयु के लगभग चौदह फीसद युवा अक्सर उदास महसूस करते हैं या किसी काम में उनकी रुचि नहीं रहती। यह स्थिति बताती है कि युवाओं की मानसिक परेशानियों को नजरअंदाज करना समाज के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। विडंबना यह है कि सामाजिक संकोच के कारण अनेक युवा अपनी समस्याएं परिवार और मित्रों से साझा नहीं कर पाते। इसलिए जरूरी है कि घरों में संवाद का माहौल बने और विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में परामर्श की व्यवस्था मजबूत हो। युवाओं को समझना होगा कि असफलता अंत नहीं, बल्कि सीखने का अवसर है।

– सुमित चंद्र वर्मा, रामपुर, उप्र

किस्तों का बोझ

सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ न मिलने और सीमित आय के कारण मध्य वर्ग के लिए घरेलू खर्चों के बीच संतुलन बनाना कठिन हो जाता है। बढ़ती कीमतें और मकान के कर्ज की किस्तों का बोझ उसकी परेशानियां और बढ़ा देता है। भारतीय रिजर्व बैंक जब रेपो दर बढ़ाता है, तो बैंकों के कर्ज की लागत बढ़ सकती है। इसका असर नए और मौजूदा कर्जदारों की ब्याज दरों तथा मासिक किस्तों पर पड़ सकता है। हालांकि, रेपो दर बढ़ाने का उद्देश्य मांग और महंगाई के दबाव को नियंत्रित करना होता है, लेकिन इसका असर तुरंत दिखाई नहीं देता। उलटे, कर्ज चुकाने वाले परिवारों की आर्थिक मुश्किलें बढ़ सकती हैं। महंगाई पर काबू पाने के लिए केवल मौद्रिक नीतियां पर्याप्त नहीं हैं। सरकार और रिजर्व बैंक को आम लोगों की क्रयशक्ति तथा घरेलू बजट पर पड़ने वाले प्रभावों का भी ध्यान रखना चाहिए।

– राजेश कुमार चौहान, जालंधर



नवरात्रि

अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर में नवरात्रि एवं लांगुल मेला उत्सव के मौके पर भगवान हनुमान की वेशभूषा में कलाकार।

बोल

अगर कानून के शासन का सम्मान नहीं किया जाता है, तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। नेताओं की यह विशेष जिम्मेदारी है कि वे घरेलू कानून और अंतरराष्ट्रीय कानून- दोनों का सम्मान करें। – नवी पिल्लई, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता



बोल

यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के ब्रिटेन के फैसले के लिए हुए जनमत संग्रह में रूस ने हस्तक्षेप किया था। रूस की दखलंदाजी को आधिकारिक तौर पर रिकार्ड में दर्ज करना अहम है। – एंड्रो बर्नहैम, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री



सम-सामयिक

अमेरिकी मध्यावधि चुनाव : ईरान युद्ध से ट्रंप की चुनौतियों में इजाफा

जनसत्ता संवाद

ईरान में लंबा खिंचता युद्ध, महंगाई और गिरती लोकप्रियता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी मुसीबत बन गए हैं। नवंबर के मध्यावधि चुनाव में इन मुद्दों का फायदा डेमोक्रेट्स को मिल सकता है और रिपब्लिकन पार्टी की सत्ता पर पकड़ कमजोर पड़ सकती है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आने वाले अमेरिकी मध्यावधि चुनावों को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। मतदान तीन नवंबर को है। उनकी घबराहट का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हाल में एक सोशल मीडिया पोस्ट में वोटों की गिनती की तुलना करते समय उन्होंने ब्राजील को गलती से भारत समझ लिया। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर इस समय अमेरिकी राजनीति में ज़ोरदार बहस चल रही है। वर्ष 2020 के चुनाव में जो बाइडेन से अपनी हार के बाद से, जिसे ट्रंप 'धांधली वाला चुनाव' कहते आए हैं, वे इस दावे को सार्वजनिक रूप से 100 से भी ज्यादा बार दोहरा चुके हैं और इस लड़ाई को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट तक ले गए हैं। इस पूरे विवाद के केंद्र में 'डाक द्वारा मतदान' का नियम है।



कुछ घटनाक्रमों से ट्रंप काफी परेशान हुए हैं। चालीस से अधिक राज्यों में शुरुआती और डाक द्वारा मतदान प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है (लगभग एक-तिहाई अमेरिकी मतदाता डाक से वोट डालते हैं)। ऊर्जा (तेल और बिजली) की बढ़ती कीमतों और ईरान में एक नए 'कभी न खत्म होने वाले युद्ध' के कारण ट्रंप अपनी सबसे कम लोकप्रियता दर से जूझ रहे हैं। ऐसा माहौल बन रहा है कि डेमोक्रेट्स प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों में रिपब्लिकन पार्टी को मामूली बढ़त से हरा सकते हैं।

मार्च 2026 में ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश जारी किया, जिसका मकसद अमेरिकियों के वोट डालने के तरीके, खासकर डाक से वोट डालने पर रोक लगाना था। उन्होंने वोटिंग मशीनों को खत्म करने का वादा किया। इसके जवाब में, सुप्रीम कोर्ट ने मेल से वोट डालने पर पाबंदी लगाने के ट्रंप के प्रयासों को खारिज कर दिया। तेईस से ज्यादा राज्य ट्रंप के इस आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए एक साथ आए, जिसे अब पूरे देश में रोक दिया गया है और यह लगभग तय है कि इस नवंबर के चुनाव में यह लागू नहीं होगा।

अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घटती लोकप्रियता एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गई है। सितंबर के अंत तक उनकी अप्रूवल रेटिंग गिरकर 38 फीसद पर पहुंच गई, जो उनके दूसरे कार्यकाल का सबसे निचला स्तर है। केवल 35 फीसद अमेरिकी मानते हैं कि देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। संसदीय रुझानों में डेमोक्रेटिक पार्टी 52 फीसदत समर्थन के साथ रिपब्लिकन पार्टी (43 फीसद) से आगे चल रही है।

ऐतिहासिक दृष्टिकोण भी डेमोक्रेट्स के पक्ष में दिखता है। 1950 के दशक से अब तक, सत्तारूढ़ राष्ट्रपति की पार्टी मध्यावधि चुनावों में औसतन 25 से अधिक सीटें हारती रही है, और राष्ट्रपति की लोकप्रियता 50 फीसद से कम होने पर यह नुकसान और बढ़ जाता है। वर्ष 2018 में ट्रंप ने 40 सीटें खोई थीं, जबकि ओबामा ने 2010 में 63 और क्लिंटन ने 1994 में 54 सीटें गंवाई थीं। केवल 1998 और 2002 के चुनाव इसके अपवाद रहे हैं। वर्तमान में, जहां ट्रंप विदेश में युद्ध में उलझे हैं, वहीं स्वदेश में बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था और जीवन यापन का खर्च इस राजनीतिक मुकाबले के सबसे बड़े मुद्दे हैं।

नीतियों पर असर

ट्रंप की उम्मीदों के उलट, ईरान में लंबे समय से चल रही जंग का असर धीरे-धीरे देश की घरेलू कीमतों पर पड़ने लगा है। जहां पेट्रोल और बिजली के बढ़ते बिल आम परिवारों को प्रभावित कर रहे हैं, वहीं डीजल के दामों में उछाल से आपूर्ति शृंखला और खेती पर असर पड़ रहा है, जिससे रिपब्लिकन पार्टी पर दबाव और बढ़ रहा है।

शोध

युद्ध से ढाई लाख वर्ग किलोमीटर खेती की जमीन बर्बाद

जनसत्ता संवाद

युद्ध का असर केवल लोगों की जान जाने, घरों के उजड़ने और शहरों के तबाह होने तक सीमित नहीं है। इसका असर खेती की जमीन पर भी पड़ता है। युद्ध के कारण खेती बंद हो जाती है, जमीन खराब हो जाती है और किसानों को अपना घर छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता है। इसका नुकसान लंबे समय तक बना रहता है। 'नेचर फूड' पत्रिका में प्रकाशित एक नए अध्ययन में यह बात सामने आई है। अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2000 से 2020 के बीच दुनिया के संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर खेती की जमीन कम हुई। इससे भविष्य में खाद्य उत्पादन और करोड़ों लोगों की भोजन संबंधी जरूरतों पर असर पड़ सकता है।

यह अध्ययन चीन के विज्ञान अकादमी के 'इंस्टीट्यूट आफ जियोग्राफिक साइंसेज एंड नेचुरल रिसोर्सेज रिसर्च' के शोधकर्ताओं की अगुआई में किया गया है। शोधकर्ताओं ने साल 2000 से 2020 तक के उपग्रह आंकड़ों का इस्तेमाल किया। इसमें 30 मीटर के स्तर पर खेती की जमीन में होने वाले बदलावों का अध्ययन किया गया। साथ ही, 155 देशों में हुई 4.6 लाख से अधिक सशस्त्र संघर्ष की घटनाओं के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया।

शोधकर्ताओं ने संघर्ष वाली जगहों के पांच किलोमीटर के दायरे में खेती की जमीन में हुए बदलावों को देखा। उन्होंने सांख्यिकीय तरीकों से यह समझने की कोशिश की कि जमीन में कितनी कमी सीधे संघर्ष के कारण हुई और कितनी कमी दूसरे कारणों से आई। अध्ययन के अनुसार, संघर्ष प्रभावित क्षेत्र दुनिया की कुल जमीन का लगभग तीन फीसद हैं। वर्ष 2020 में दुनिया की छह फीसद से अधिक कृषि भूमि इन्हीं क्षेत्रों में थी। वर्ष 2000 से 2020 के बीच दुनिया में खेती की जमीन का कुल क्षेत्रफल बढ़ा। इसके उलट, संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में खेती की जमीन कम होती गई। शोधकर्ताओं के मुताबिक, संघर्ष से प्रभावित इलाकों में खेती की जमीन में औसतन लगभग तीन फीसद की कमी आई। हर प्रभावित क्षेत्र में औसतन सालाना करीब 14.5 हेक्टेयर जमीन कम हुई।

शांतिपूर्ण क्षेत्रों की तुलना में संघर्ष प्रभावित इलाकों में खेती की जमीन का नुकसान 23.7 फीसद अधिक था। पश्चिमी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया में इसका असर खास तौर पर देखा गया। कुल मिलाकर, इन दो दशकों में संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में लगभग 2.49 लाख वर्ग किलोमीटर खेती की जमीन का नुकसान हुआ। खेती की जमीन कम होने का असर केवल किसानों की आजीविका पर नहीं पड़ता, बल्कि इससे दुनिया की खाद्य आपूर्ति भी प्रभावित होती है। अध्ययन के अनुसार, खोई हुई जमीन पर जितना भोजन पैदा किया जा सकता था, उससे लगभग 25.5 करोड़ लोगों की न्यूनतम सालाना ऊर्जा संबंधी खाद्य जरूरतें पूरी हो सकती थीं।

हालांकि शोधकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि यह संभावित खाद्य उत्पादन का अनुमान है। इसका अर्थ यह नहीं है कि इतने लोग सीधे भूखे रह गए। लोगों तक भोजन पहुंचना व्यापार, कीमतों, वितरण व्यवस्था और उनकी खरीदने की क्षमता पर भी निर्भर करता है। अध्ययन में पाया गया कि हर संघर्ष का असर एक जैसा नहीं होता। जिन क्षेत्रों में बार-बार लड़ाई हुई, वहां खेती की जमीन का नुकसान लगभग एक-तिहाई तक पहुंच गया। लंबे समय तक चलने वाले और अधिक तीव्र संघर्षों में नुकसान ज्यादा हुआ। कई जगह सिंचाई व्यवस्था, सड़कें और कृषि से जुड़ा बुनियादी ढांचा भी प्रभावित हुआ है। इससे खेती दोबारा शुरू करना मुश्किल हो गया।

'नेचर फूड' पत्रिका में प्रकाशित एक नए अध्ययन में बताया गया है कि युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में 20 साल में 2.49 लाख वर्ग किलोमीटर खेती की जमीन घट गई है। युद्ध के कारण बर्बाद हुई खेती की जमीन पर पैदा होने वाला भोजन लगभग 25.5 करोड़ लोगों की न्यूनतम सालाना खाद्य ऊर्जा जरूरतें पूरी कर सकता था। दुनिया की कुल जमीन का तीन फीसद हिस्सा युद्ध प्रभावित क्षेत्र हैं।



(फाइल फोटो)

विश्व परिक्रमा

यूरोपीय संघ का 1600 रूसियों, रूसी हथियार कंपनियों पर प्रतिबंध

जनसत्ता संवाद

यूरोपीय संघ (ईयू) ने सोमवार को रूस के हथियार उद्योग से जुड़े लगभग 1,600 रूसी लोगों और उन कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए, जिनपर ड्रोन और मिसाइल के पुर्जे बनाने में शामिल रहने का संदेह है। पांच साल पहले रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण शुरू किए जाने के बाद से प्रतिबंधों की सबसे लंबी सूची में, यूरोपीय संघ ने यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों में 'छद्म चुनाव' कराने, काम करने या उनमें हिस्सा लेने के आरोपी 77 लोगों को भी निशाना बनाया है।

प्रतिबंधों की घोषणा करते हुए, ईयू की विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास ने कहा कि इनमें से आधे से अधिक प्रतिबंध 'उन बैलिस्टिक मिसाइलों की उत्पादन शृंखला से जुड़े हैं, जिनका इस्तेमाल रूस प्रतिदिन यूक्रेनी नागरिकों की जान लेने के लिए करता है।' उन्होंने कहा, 'यह मास्को पर दबाव कम करने का नहीं, बल्कि उसे बढ़ाने का समय है।' ईयू ने कहा कि ये कंपनियां खुद रूस सरकार द्वारा तैयार की गई उस सूची में शामिल हैं, जो उन्हें रूसी सैन्य औद्योगिक समूह का हिस्सा बताती है, और इसलिए सब्सिडी पाने की हकदार हैं।



ईयू का मानना है कि इन कंपनियों को संचालित करने वाले अधिकारी रूस के सैन्य एवं औद्योगिक समूह का समर्थन कर रहे हैं। उसने कहा कि ये प्रतिबंध मध्य स्तर के उन आपूर्तिकर्ताओं को लक्षित हैं, जो रूस के सैन्य उद्योग का मुख्य हिस्सा हैं। वे इलेक्ट्रानिक्स, संचार उपकरण, रडार और दिशासूचक या मार्ग बताने वाली प्रणाली, उपग्रह और मिसाइल प्रणाली तथा विस्फोटक और गोला-बारूद मुहैया करते हैं। इस कदम के बाद, ईयू की कार्रवाई का सामना करने वाले रूसी अधिकारियों और कंपनियों की कुल संख्या बढ़कर 4,500 से ज्यादा हो गई है। इनमें राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन, उनका कथित तौर पर समर्थन करने वाले अमीर कारोबारी और कई सांसद शामिल हैं।

जानें-समझें

रूस से अमेरिका का डीजल खरीद सौदा

खुद के लिए छूट भारत पर अंकुश

जनसत्ता संवाद

हाल में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से डीजल के आयात सौदे का एलान किया है। भारत के संदर्भ में उनका यह कदम पूर्व की कई घोषणाओं से एकदम उलट है। अमेरिका ने रूस से कच्चे तेल की भारी मात्रा में खरीद को लेकर भारत को बार-बार निशाना बनाया है। अमेरिका ने पिछले साल दंडात्मक शुल्कों का एलान किया था। हाल में वह कानून भी बना डाला, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूसी ऊर्जा के शीर्ष खरीदारों पर एक सौ फीसद तक शुल्क लगाने का अधिकार देता है। अमेरिकी प्रशासन अक्सर यह तर्क देता रहा है कि भारत मास्को से कच्चा तेल खरीदकर यूक्रेन में रूस के युद्ध को प्रभावी रूप से वित्त पोषित कर रहा है। अब अप्रत्याशित रूप से रुख बदलते हुए, ट्रंप ने ऐसे समझौते की घोषणा की है जिसके तहत रूस अमेरिका और वैश्विक बाजारों को लाखों टन डीजल की आपूर्ति करेगा।

ट्रंप पर बढ़ता दबाव

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर घरेलू स्तर पर ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर दबाव बढ़ता जा रहा है। पश्चिम एशिया में उनके द्वारा शुरू किए गए युद्ध के कारण कीमतें बढ़ रही हैं और अमेरिका में अहम मध्यावधि चुनाव बस कुछ ही हफ्तों दूर हैं। ऐसे में अमेरिका का नीतिगत स्तर पर विरोधाभास सामने आया है। अमेरिका ने रूसी ऊर्जा खरीदने वाले देशों को दंडित किया है, लेकिन अब जब उसके अपने आर्थिक हित की बात आई तो वह रूस से डीजल खरीद को तैयार है। सवाल उठने लगा है कि क्या रूसी ऊर्जा संपदा खरीद को अमेरिकी प्रतिबंध सिर्फ भारत व कुछ देशों को निशाना बनाने के लिए हैं? ऊर्जा बिक्री से रूसी राजस्व को सीमित करने के अमेरिकी तर्क का क्या होगा?

डीजल की जरूरत

अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से, डीजल महत्त्वपूर्ण ईंधन है। यह अमेरिका में राजनीतिक रूप से संवेदनशील विषय है। डीजल की कीमतों में उछाल उपभोक्ता स्तर पर मुद्रास्फीति को तेजी से बढ़ा रहा है। होर्मुज से ईंधन की आवाजाही पर प्रतिबंध और रूस के तेल और गैस बुनियादी ढांचे पर यूक्रेन के हमलों के कारण अमेरिका और यूरोप में डीजल की कीमतों में भारी उछाल आया है। अमेरिका में डीजल की कीमतें रिकार्ड स्तर पर पहुंच गई हैं, लगभग 6.5 डालर प्रति गैलन।



फाइल फोटो



समझौते से मास्को को राजस्व प्राप्त होगा, ठीक वैसे ही जैसे भारत द्वारा कच्चे तेल की खरीद से होता है। यह एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है, जिसे भारत अब रूस से तेल आयात और रूस व ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों से संबंधित अमेरिकी परामर्श में उठा सकता है और छूट देने का आग्रह कर सकता है।

– अजय बिसारिया, पूर्व राजदूत

भारत के मामले में बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा कि अमेरिका इसे कैसे देखता है। वह तर्क दे सकता है कि रूस से डीजल आयात असाधारण बाजार परिस्थितियों के कारण उचित है, और इसे आपात स्थिति के लिए व्यावहारिक बता सकता है। – *मीरा शंकर, अमेरिका में भारत की पूर्व राजदूत*



भारत की स्थिति

भारत के लिए रूसी तेल बेहद महत्त्वपूर्ण है, अगस्त में इसके तेल आयात का लगभग आधा हिस्सा रूसी तेल से आया था। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद पश्चिमी देशों के एक बड़े हिस्से ने रूसी तेल का बहिष्कार करना शुरू कर दिया, जिससे रूस को कीमतें कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा और भारत ने इन रियायती मात्राओं को तुरंत खरीद लिया। पश्चिम एशिया युद्ध से पहले के महीनों में, रूस से तेल आयात में उल्लेखनीय कमी आई क्योंकि अमेरिका ने रूसी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध लगा दिए थे।

यूरोप पर दबाव

ट्रंप लंबे समय से यूरोप पर अपने डीजल भंडार जारी करने के लिए दबाव डाल रहे थे, और यहां तक कि उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि अमेरिका – जो स्वयं एक प्रमुख डीजल निर्यातक है – घरेलू आपूर्ति को मजबूत करने के लिए डीजल निर्यात पर प्रतिबंध लगा सकता है। पिछले सप्ताह, सात देशों के समूह (जी7) ने आपातकालीन भंडार से 10 करोड़ बैरल कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों को जारी करने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें डीजल की पर्याप्त मात्रा भी शामिल है।

– प्रस्तुति : दीपक रस्तोगी

प्रतिबंध और छूट

फरवरी में भारत का रूसी कच्चे तेल का आयात 2025 के अपने उच्चतम स्तर (20 लाख बैरल प्रति दिन से अधिक) से घटकर आधा हो गया। इसके बावजूद, फरवरी में रूस भारत के कच्चे तेल का सबसे बड़ा स्रोत था, जो उसके कुल तेल आयात का लगभग पांचवां हिस्सा था। हालांकि, पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण होर्मुज से तेल आपूर्ति बाधित होने के चलते भारत का रूसी तेल आयात फिर से बढ़ गया। वैश्विक बाजारों में पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने के प्रयास में अमेरिका ने भी प्रतिबंधों में छूट जारी की। पिछले महीने उस समय यह सिलसिला रुक गया जब ट्रंप ने 'लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट आफ 2026' पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया। यह कानून अमेरिका को भारत और चीन समेत उन देशों पर एक सौ फीसद तक शुल्क लगाने की अनुमति देता है, जो रूस से तेल और गैस खरीदते हैं। महत्त्वपूर्ण बात है कि यह कानून अमेरिकी राष्ट्रपति को इसके प्रावधानों को रद्द करने का अधिकार देता है – जिसके लिए भारत निश्चित रूप से दबाव डालेगा।

व्यक्तित्व

नीरू : निशानेबाजी की ट्रैप स्पर्धा में खत्म किया चीन व कुवैत का दबदबा

जनसत्ता संवाद

एशियाई खेलों में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने से दस दिन पहले नीरू ढांडा को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। बीमार होने के कारण साढ़े तीन सप्ताह तक उन्होंने कोई अभ्यास नहीं किया था, न ही प्रशिक्षण ले पाई थीं। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिविर के दौरान, उन्होंने अपना अधिकांश समय अपने कमरे में ही बिताया। पांच दिनों तक उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, केवल पानी पीकर ही जीवित रहीं। जब वे एशियाई खेलों के लिए जापान पहुंचीं, तब तक उन्हें तैयारी करने का मुश्किल से ही मौका मिल पाया था। उसके बाद जब टोयोटा के उरेनोचो में शूटिंग रेंज में बारिश हो रही थी, तब ढांडा पोडियम के शीर्ष पर खड़ी थीं, उन्होंने वह कर दिखाया था जो इससे पहले किसी भी भारतीय महिला ने नहीं किया था। 1978 के बाद से किसी भी भारतीय निशानेबाज ने, चाहे वह पुरुष हो या महिला, नहीं किया था। उन्होंने एशियाई खेलों में ट्रैप शूटिंग में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीत लिया था। फाइनल में उन्होंने अपने 30 में से 28 निशाने साधे, एशियाई खेलों का रिकार्ड बनाया और चीन की युन युनींग से आगे रहीं, जिन्होंने 26 निशाने साधकर रजत पदक जीता। ढांडा की जीत का महत्व भारत के पदक तालिका से कहीं अधिक था। न केवल किसी भारतीय महिला ने एशियाई खेलों में पहली बार यह खिताब जीता था, बल्कि इसने इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने के लिए देश के दशकों लंबे इंतजार को भी समाप्त कर दिया था।

ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले अंतिम भारतीय रणधीर सिंह थे, जिन्होंने 1978 में यह उपलब्धि हासिल की थी। पिछले 30 वर्षों में इस स्पर्धा में चीन और कुवैत का दबदबा रहा है। महिलाओं की प्रतियोगिता, जिसे 1990 में एशियाई खेलों में शामिल किया गया था, में चीन ने 2010 को छोड़कर हर संस्करण में स्वर्ण पदक जीता है, जब जापान की युकी नाकायमा ने खिताब अपने नाम किया था। भारतीय महिला निशानेबाज नीरू ढांडा ने एशियाई खेल में दो स्वर्ण और एक पदक जीते। उन्होंने महिलाओं की ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण जीतकर इस इवेंट में भारत का 36 साल का पदक सूखा खत्म किया। उन्हें एशियाई खेल के समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक होने का सम्मान मिला। उनके कोच, अर्जुन पुरस्कार विजेता मनशेर सिंह, लगातार यह सुनिश्चित करते रहे कि वे मानसिक रूप से मजबूत रहें। भारत के ट्रैप शूटिंग कोच पीटर विल्सन कहते हैं, वे बहुत प्रतिभाशाली हैं।

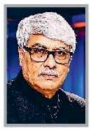


नीरू ढांडा ने टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता था। नीरू धांडा (118), आशिमा अहलावत (106) और मनीषा कीर (104) की भारतीय टीम ने कुल 328 अंक जुटाकर दूसरा स्थान हासिल किया था। नीरू भारतीय सेना की कोर आफ मिलिट्री पुलिस में नायब सूबेदार के पद पर तैनात हैं। वे मध्य प्रदेश के मंडू में 'आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट' में ट्रेनिंग लेती हैं। नीरू ने आइएसएसएफ विश्व कप के महिला ट्रैप इवेंट में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रचने में सफलता हासिल की थी। उन्होंने यह बड़ी कामयाबी इटली के लोनाटो में हुए आइएसएसएफ शाटगन विश्व कप में हासिल की।

चिंतन

अब पेश करने ही होंगे सबूत

लोकतंत्र में सवाल उठाना विपक्ष का अधिकार है और उनका जवाब देना सरकार व संवैधानिक संस्थाओं की जिम्मेदारी। लेकिन जब सवाल चुनावी व्यवस्था की विश्वसनीयता से जुड़ा हो, तो आरोपों के साथ प्रमाण भी जरूरी होते हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित गड़बड़ियों को लेकर इंडिया ब्लॉक के 11 नेताओं का सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करना इसी कसौटी पर परखा जाएगा। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव समेत विपक्षी नेताओं ने निर्वाचन आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भी याचिका में पक्षकार बनाया है। अब विपक्ष को बताना होगा कि गड़बड़ी कहां हुई, कितने मतदाता प्रभावित हुए और उसके समर्थन में क्या सबूत हैं। सियासी शक्ति प्रदर्शन से मुद्दा चर्चा में आ सकता है, लेकिन आरोप प्रमाणों से ही सिद्ध होते हैं। याचिका दाखिल करने से पहले विपक्षी नेताओं ने प्रधान न्यायाधीश से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपने का समय मांगा था। इसके बाद बाराखंबा से सर्वोच्च न्यायालय तक मार्च निकाला गया। राहुल गांधी ने इस मार्च की तुलना 'शिवजी की बारात' से की। विभिन्न दलों की भागीदारी और नेताओं की मौजूदगी ने इसे राजनीतिक घटनाक्रम जरूर बनाया, लेकिन मार्च का आकार आरोपों की सत्यता का प्रमाण नहीं है। विपक्ष को अब राजनीतिक नारों से आगे बढ़कर तथ्य सामने रखने होंगे। चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग करना अलग बात है और चुनावी प्रक्रिया में अनियमितता साबित करना अलग। दोनों को एक मानना उचित नहीं होगा। हालांकि, विपक्ष से प्रमाण मांगने का अर्थ उसकी शिकायतों को खारिज करना भी नहीं है। मतदाता सूची से किसी पात्र नागरिक का नाम गलत तरीके से हटना गंभीर मामला है। निर्वाचन आयोग का दायित्व है कि वह प्रक्रिया में पारदर्शिता रखे, शिकायतों का निपटारा करे और त्रुटियां मिलने पर पूरी जवाबदेही के साथ सुधार सुनिश्चित करे। किसी संस्था को सवालों से परे नहीं रखा जा सकता, लेकिन बिना प्रमाण लगाए गए आरोपों को भी अंतिम सच नहीं माना जा सकता। न्यायिक जांच का उद्देश्य ही आरोपों और तथ्यों के बीच अंतर स्पष्ट करना है। कुल मिलाकर अब विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सबूत पेश करने ही होंगे। इसी बीच जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का फैसला भी चर्चा में है। गृह मंत्रालय की समिति की सिफारिश पर रामलीला मैदान, बुराड़ी और पूर्वी दिल्ली के सीबीडी मैदान को प्रदर्शन का वैकल्पिक स्थल बनाया गया है। अण्णा आंदोलन से लेकर पहलवानों के प्रदर्शन तक, जंतर-मंतर लंबे समय से विरोध की आवाज का प्रमुख केंद्र रहा है। संसद के निकट होने के कारण इसका प्रतीकात्मक महत्व भी है। सुरक्षा, यातायात और सार्वजनिक व्यवस्था की चिंताएं अपनी जगह हैं, लेकिन इनके समाधान के नाम पर शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। वैकल्पिक स्थलों पर पर्याप्त सुविधाएं और स्पष्ट नियम सुनिश्चित करना भी जरूरी है। लोकतंत्र में सरकार की जवाबदेही और विपक्ष की जिम्मेदारी, दोनों अनिवार्य हैं। निर्वाचन आयोग को पारदर्शिता से काम करना होगा और विपक्ष को आरोपों के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। यदि गड़बड़ी हुई है तो उसका खुलासा और सुधार हो; यदि आरोप प्रमाणित नहीं होते तो राजनीतिक दावों की समीक्षा भी हो। लोकतंत्र की विश्वसनीयता शोर से नहीं, तथ्यों, पारदर्शिता और जवाबदेही से मजबूत होती है।



मुद्दा
ओमकार चौधरी

पश्चिम एशिया में युद्ध का खतरा बढ़ा

रियाद के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हूती विद्रोहियों के लगातार हमलों ने पश्चिम एशिया को बड़े क्षेत्रीय संघर्ष के मुहाने पर ला खड़ा किया है। दो दिन में हुए हमलों में 13 लोगों की मौत और सैकड़ों के घायल होने से नागरिकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठे हैं। मृतकों में एक भारतीय भी शामिल है। हवाई सेवाएं बाधित हैं और सऊदी अरब की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका की संभावित सैन्य भागीदारी से टकराव के और व्यापक होने का खतरा है। इसका असर खाड़ी देशों में काम कर रहे भारतीयों की सुरक्षा से लेकर वैश्विक तेल आपूर्ति और व्यापार तक पड़ सकता है। ऐसे में सैन्य जवाबी कार्रवाई के बजाय संघर्ष को फैलने से रोकना और यमन संकट का राजनीतिक समाधान तलाशना अंतरराष्ट्रीय समुदाय की प्राथमिकता होनी चाहिए।

सऊदी अरब की राजधानी रियाद के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यमन के हूती विद्रोहियों के लगातार हमलों ने पश्चिम एशिया में सुरक्षा संकट गहरा दिया है। शनिवार, 10 अक्टूबर 2026 को हुए हमले में 13 लोगों की मृत्यु हुई और 309 लोग घायल हुए। मृतकों में एक भारतीय नागरिक भी शामिल है। रविवार, 11 अक्टूबर को लगातार दूसरे दिन हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया। इन घटनाओं से अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं प्रभावित हुई हैं और सऊदी अरब की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे हैं। अमेरिका की संभावित सैन्य कार्रवाई से संघर्ष के व्यापक क्षेत्रीय युद्ध में बदलने की आशंका बढ़ा दी है। रियाद का किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा सऊदी अरब के प्रमुख विमानन केंद्रों में शामिल है। शनिवार को हुए हमले से तीसरे और चौथे यात्री भवन के आसपास भारी नुकसान हुआ। विस्फोटों के बाद परिसर में अफरातफरी मच गई। यात्रियों और कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। बचाव दलों ने घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया। सऊदी अधिकारियों के अनुसार, हमले में प्रारंभिक रूप से 12 लोगों की मृत्यु हुई थी। मृतकों में चार सऊदी नागरिक, दो बांग्लादेशी तथा अमेरिका, मिस्र, जॉर्डन, फलस्तीन, सीरिया और सूडान के एक-एक नागरिक शामिल थे। बाद में अस्पताल में एक भारतीय नागरिक की मृत्यु होने से मृतकों की संख्या 13 हो गई। इस हमले का शिकार विभिन्न देशों के निर्दोष नागरिक बने।

शनिवार की तबाही से हवाई अड्डा उबर भी नहीं पाया था कि रविवार को दोबारा हमला हो गया। सऊदी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन के अनुसार, एक प्रक्षेपास्त्र चौथे यात्री भवन से टकराया, जिससे आग लग गई। अधिकारियों ने एक अन्य प्रक्षेपास्त्र को हवाई अड्डे के समीप रोकने की जानकारी दी। दूसरे हमले में भी लोग घायल हुए, हालांकि उनकी अंतिम संख्या स्पष्ट नहीं थी। लगातार हमलों ने अत्याधुनिक हवाई रक्षा व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े कर दिए। भारत के लिए यह घटना विशेष चिंता का विषय है। शनिवार के हमले में घायल भारतीय नागरिक की रविवार को उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। उसकी पहचान हैदराबाद निवासी मोहम्मद यूसुफ अली के रूप में सामने आई। परिवार के अन्य सदस्य भी घायल हुए। भारतीय दूतावास ने पीड़ित परिवार से संपर्क कर आवश्यक सहायता और पार्थिव शरीर भारत पहुंचाने का आश्वासन दिया। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। भारतीय हताहतों की संख्या को लेकर प्रारंभिक सूचनाओं में अंतर था। उपलब्ध विवरणों के अनुसार, एक भारतीय की मृत्यु हुई और दस अन्य घायल हुए। रविवार के दूसरे हमले में अलग से 12 भारतीयों के घायल होने के दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने नागरिकों और नागरिक सुविधाओं पर हमलों की कड़ी निंदा की। मंत्रालय ने ऐसे हमले तत्काल रोकने की मांग करते हुए सऊदी अरब की संप्रभुता और सुरक्षा के प्रति समर्थन दोहराया। रियाद स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों तथा अस्पतालों के संपर्क में है। भारत की चिंता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सऊदी अरब सहित खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं। ये कर्मचारी भारत में अपने परिवारों को धन भेजते हैं। संघर्ष बढ़ने से उनकी सुरक्षा, रोजगार और आवागमन प्रभावित हो सकता है। भारत के सामने अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और क्षेत्रीय संबंधों में संतुलन बनाए रखने की चुनौती है। हूती विद्रोहियों ने हमलों की जिम्मेदारी स्वीकार की है। यमन में सक्रिय इस संगठन का सऊदी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन के साथ लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन प्राप्त है।



उनका आरोप है कि यमन में सऊदी सैन्य हस्तक्षेप से व्यापक जनहानि हुई है। संगठन ने रियाद पर हमलों को उसी कार्रवाई का जवाब बताया और भविष्य में भी सऊदी ठिकानों पर हमले जारी रखने की धमकी दी। लेकिन किसी संघर्ष में नागरिक हवाई अड्डों और यात्रियों को निशाना बनाना अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के गंभीर प्रश्न खड़े करता है। सैन्य संघर्ष में भी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने हमलों को युद्ध अपराध बताते हुए कठोर जवाब देने की चेतावनी दी। इसके बाद यमन में सैन्य कार्रवाई तेज होने की खबरें आईं। दोनों पक्षों की जवाबी कार्रवाई संघर्ष को अधिक खतरनाक बना सकती है। रियाद हवाई अड्डे पर हमलों का सिलसिला अक्टूबर में अचानक शुरू नहीं हुआ। सितंबर में ईंधन भंडारण क्षेत्र के समीप हमले और आग लगने की खबर आई थी। अक्टूबर के पहले सप्ताह में रियाद तथा आभा के हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। आठ अक्टूबर को एक खड़े यात्री विमान को नुकसान पहुंचने तथा सऊदी विमान चालक सहित तीन नागरिकों की मृत्यु की जानकारी सामने आई। इन घटनाओं से संकेत मिलता है कि सऊदी अरब का विमानन ढांचा हूती विद्रोहियों की रणनीति का महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया है। सऊदी अरब के लिए संकट केवल हवाई अड्डों तक सीमित नहीं है। उसकी अर्थव्यवस्था में तेल उत्पादन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, पर्यटन और विदेशी निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका है। देश तेल पर निर्भरता घटाकर पर्यटन, उद्योग और व्यापार का विस्तार करना चाहता है। लेकिन राजधानी के प्रमुख हवाई अड्डे पर लगातार हमले विदेशी निवेशकों का विश्वास प्रभावित कर सकते हैं। यात्री सुरक्षा पर संदेह बढ़ने से पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियों को भी नुकसान पहुंच सकता है। सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप किया जाता है तो यमन में संघर्ष और तेज हो सकता है। दूसरी ओर निष्क्रिय रहने से हूती विद्रोहियों को प्रोत्साहन मिलने की आशंका है। अमेरिकी कार्रवाई होने पर ईरान की संभावित प्रतिक्रिया और लाल सागर के समुद्री व्यापार पर उसके प्रभाव को भी ध्यान में रखना होगा। ब्रिटेन और अन्य पश्चिमी देशों ने भी हमलों पर चिंता जताई है।

अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने प्रश्न यह है कि क्या केवल सैन्य जवाब से हूती विद्रोहियों को रोका जा सकता है अथवा यमन के लंबे संघर्ष का राजनीतिक समाधान तलाशना आवश्यक है। पिछले वर्षों का अनुभव बताता है कि सैन्य हमलों के बावजूद हूती संगठन की आक्रमण क्षमता समाप्त नहीं हुई है। इस संघर्ष का आर्थिक प्रभाव सऊदी अरब से बाहर भी पड़ सकता है। पश्चिम एशिया विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का प्रमुख केंद्र है। तेल प्रतिष्ठानों और समुद्री मार्गों पर खतरा बढ़ने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनिश्चितता पैदा हो सकती है। भारत जैसे बड़े तेल आयातक देश के लिए यह विशेष चिंता का विषय है। भारत की प्राथमिकता अपने नागरिकों की सुरक्षा, सऊदी अरब के साथ सहयोग और क्षेत्रीय शांति की बहाली होनी चाहिए। रियाद की त्रासदी चेतावनी है कि पश्चिम एशिया में सैन्य टकराव अनियंत्रित हुआ तो उसके मानवीय, राजनीतिक और आर्थिक परिणाम पूरे विश्व को प्रभावित करेंगे।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। व उनके अपने विचार हैं।)
लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

पैरवी
रितीश उपाध्याय

न्याय की राह में आर्थिक मजबूरी न बने बाधा

न्याय केवल अदालतों के दरवाजे खुले होने से नहीं मिलता। उसके लिए यह भी जरूरी है कि आम नागरिक अपने अधिकारों को समझते हुए न्यायालय की प्रक्रिया में हिस्सा ले सके और उसे एक सक्षम वकील की सहायता मिल पाए, लेकिन जब वकील की फीस चुकाना ही किसी व्यक्ति के लिए नामुमकिन हो जाए, तो न्याय तक उसकी पहुंच एकदम सीमित हो जाती है। इसी प्रकार की असमानता को दूर करने के लिए भारत के संविधान ने निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था प्रदान की है। लेकिन अहम सवाल यह है कि क्या यह व्यवस्था जरूरतमंदों को सिर्फ वकील उपलब्ध करा रही है या सच में आमजन को प्रभावी प्रतिनिधित्व और न्याय दिला पा रही है? अनुच्छेद 39ए के अंतर्गत भारत के संविधान ने राज्य को यह निर्देश दिया है कि कानूनी व्यवस्था समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे और आर्थिक या किसी और प्रकार की अक्षमताओं के कारण किसी नागरिक को न्याय से वंचित न होने दिया जाए। यह राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय ने मुफ्त कानूनी सहायता को निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया के संवैधानिक सिद्धांत से जोड़ा है, साथ ही न्यायालय ने समय-समय पर यह माना है कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अर्थ केवल जीवित रहने का अधिकार नहीं, बल्कि कानून के अनुरूप निष्पक्ष प्रक्रिया और न्याय मिलना भी है। हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य 1979, में सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय से जेलों में बंद कैदियों की स्थिति पर ध्यान दिया और इस फैसले ने यह भी स्पष्ट किया कि गरीब व्यक्ति को मुफ्त कानूनी सहायता न मिलना निष्पक्ष न्याय के रास्ते में गंभीर बाधा है। कानूनी अधिकार तभी सार्थक हैं, जब व्यक्ति उन्हें इस्तेमाल करने की स्थिति में भी हो। लीगल सर्विसेज ऑथोरिटी एक्ट, 1987 ने इस संवैधानिक उद्देश्य को लागू करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य, जिला और तालुका स्तर पर संस्थागत व्यवस्था बनाई है। इस अधिनियम की धारा 12 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य, मानव तस्करी या बेगार के पीड़ित, महिलाएं, बच्चे जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, दिव्यांग व्यक्ति, निर्दिष्ट आपदाओं और हिंसा के पीड़ित, औद्योगिक श्रमिक तथा हिरासत में रखे गए व्यक्ति मुफ्त कानूनी सहायता के पात्र हैं। इन सब के अलावा सामान्य वर्ग के लोग जो निर्धारित आय-सीमा के भीतर आते हैं वो भी सहायता मांग सकते हैं। एनएएलएसए की हेल्पलाइन 15100 और उसकी आधिकारिक वेबसाइट भी जानकारी पाने के माध्यम हैं। सिर्फ वकील मिलना ही काफी नहीं है, कानूनी सहायता की असल परीक्षा अदालत में होती है। उम्मेद देवी बनाम राजस्थान राज्य 2026 के मामले में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसी अंतर को स्पष्टता से रेखांकित किया है। दहेज संबंधी मांग और कथित उत्पीड़न से जुड़े मामले में अपनी बेटी की मृत्यु के संबंध में आरोपित व्यक्तियों की बरी किए जाने के खिलाफ उम्मेद देवी ने अपील की थी। अपील को दाखिल करने में 19 दिन की देरी हुई और उसे माफ कराने के लिए जरूरी आवेदन नहीं लगाया गया था। हाई कोर्ट में उनकी ओर से कोई वकील उपस्थित नहीं हुआ और मामला बंद कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने अपील को स्वीकार करते हुए कहा कि अदालतों को ऐसे कठिनाइयों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। जहां वकील की अनुपस्थिति या अपर्याप्त सहायता से किसी व्यक्ति का कानूनी अधिकार प्रभावित हो सकता है, वहां अदालत को प्रभावी कानूनी सहायता सुनिश्चित करने पर विचार करना चाहिए। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज) रेगुलेशनस, 2010 में पैनल के वकीलों के चयन और उनके काम की निगरानी के प्रावधान हैं। जरूरत इस बात की है कि इन प्रावधानों को काग़ज से निकालकर व्यवहार में लागू किया जाए। नियमित समीक्षा, उचित प्रशिक्षण, मुवक्किलों से संवाद और खराब प्रदर्शन पर जवाबदेही तय करना भी अति आवश्यक है। मुफ्त कानूनी सहायता के समक्ष जागरूकता की कमी, अनुभवी वकीलों तक लोगों की पहुंच नहीं होना, सीमित संसाधन और कमजोर निगरानी जैसी चुनौतियां खड़ी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों, वंचित समुदायों और समाज के उस वर्ग तक जिसको इसकी सब से जादा जरूरत है, वहां लोगों में इसकी जानकारी नहीं है। न्याय तक पहुंच का अर्थ केवल अदालत में प्रवेश नहीं, बल्कि वहां अपनी बात प्रभावी ढंग से रखने का अवसर भी है। जब तक यह अवसर समाज में उपस्थित हर जरूरतमंद व्यक्ति को वास्तविक रूप से नहीं मिलता, समान न्याय का वादा अधूरा रहेगा।

(लेखक सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं, वे उनके अपने विचार हैं।)

संकलित
दर्शन

प्रसन्न रहने की शुरुआत घर से हो



महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रसन्न रहने की शुरुआत अपने घर से ही होनी चाहिए। हम बाहर तो बहुत खुश रहते हैं, लेकिन घर में अकारण क्रोध से भरे रहते हैं। सभी लोग, खासतौर पर युवा इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें घर में भी प्रसन्न रहना है। युवाओं को यह बात याद रहे, इसलिए एक नया मंत्र दे रहा हूं। वे घर और परिवार में भी शांति रखें। कई लोग बाहर से घर में आते ही क्रोधित हो जाते हैं। वे अकारण गुस्सा कर घर वालों को मायूस कर देते हैं। यह हत्या कर देने जैसा अपराध है। मुश्किल यह है कि वे लोग अपनी कमी को मानते भी नहीं। कम से कम वे यह मान लें कि उसमें यह कमी है तो कभी न कभी वह कमी दूर भी की जा सकती है। लंका में कोई मानता ही नहीं था कि वहां कोई रोगी है। परिणाम सबके सामने है। जो माने ही नहीं कि अस्वस्थ है, वह स्वस्थ कैसे हो सकता है? एक और मंत्र याद रखें-छोटी-मोटी बातों को अनदेखा करें। व्यर्थ विवाद में मत उलझें। बात-बात में उलझने की आदत से अशांति ही पैदा होती है। सच्ची प्रसन्नता चाहिए तो इधर-उधर की बातें सुनना ही छोड़ दें। अस्तित्व के संगीत को सुनने की कोशिश करें। याद रखें, जिसे प्रसन्न रहना है, उसे कोई रोक नहीं सकता और जिसे दुखी ही रहना है, उसे कोई प्रसन्न नहीं कर सकता। कुछ लोगों को प्रसन्न रहना ही नहीं है। वे परेशान और दुखी होने के बहाने खोजते रहते हैं। इस आदत को बदलने की कोशिश ईमानदारी के साथ की जानी चाहिए।

संकलित
प्रेरणा

घमंड न करें व दूसरों को कमजोर न समझें



महाभारत युद्ध में अर्जुन और कर्ण आमने-सामने थे। दोनों दिव्य अस्त्र-शस्त्रों से लड़ रहे थे। जब-जब अर्जुन के तीर कर्ण के रथ पर लग रहे थे तो कर्ण का रथ बहुत पीछे खिसक रहा था। दूसरी ओर जब-जब कर्ण के तीर अर्जुन के रथ पर लगते तो उसका रथ थोड़ा सा ही पीछे खिसकता था। ये देखकर अर्जुन को घमंड हो गया कि उसके बाणों में ज्यादा शक्ति है। अर्जुन ने ये बात श्रीकृष्ण से कही तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे बाणों से ज्यादा शक्ति कर्ण के बाणों में है। भगवान की बात सुनकर अर्जुन ने कहा कि ये कैसे संभव है, मेरा रथ तो थोड़ा सा ही पीछे खिसक रहा है। श्रीकृष्ण ने कहा कि तुम्हारे रथ पर मैं स्वयं बैठा हूं, ऊपर ध्वजा पर हनुमान जी विराजित हैं, तुम्हारे रथ के पहिए को शेषनाग ने थाम रखा है। इतना होने के बाद भी कर्ण के बाण ये रथ पीछे खिसक रहा है तो इसका मतलब यही है कि उसके बाणों में ज्यादा शक्ति है। यदि ये न होता तो पता नहीं तुम्हारे रथ की क्या स्थिति होती। ये बात सुनकर अर्जुन को अपनी गलती का अहसास हो गया और उसका घमंड टूट गया। इस कथा में श्रीकृष्ण ने अर्जुन को सीख दी है कि कभी अपनी शक्ति का घमंड न करें और शत्रु को कमजोर न समझें। यथा स्थिति का अच्छा से अवलोकन करें।

अंतर्मन



आज की पाती

सपनों को संकल्प में बदलने की सीख

विद्यार्थी किसी भी देश का भविष्य ही नहीं, उसकी संभावनाओं और प्रगति के सबसे मजबूत आधार भी होते हैं। उनके विचारों में नवीनता, आंखों में सपने और कुछ नया कर गुजरने का उत्साह समाज को आगे बढ़ाने की शक्ति देता है। इसी भावना के साथ भारत में प्रति वर्ष 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक और युवाओं के प्रेरणास्रोत डा. एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के कारण विशेष महत्व रखता है। हालांकि, यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को आधिकारिक रूप से विश्व छात्र दिवस घोषित नहीं किया है। इसके बावजूद भारत में यह अवसर विद्यार्थियों को कलाम के विचारों से जोड़ने और शिक्षा के महत्व को रेखांकित करने का माध्यम बन गया है। - दिलीप श्रीवास्तव, धमतरी

नोबेल पुरस्कार
डॉ. रविन्द्र ब्रह्मे



अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने किया बुनियादी मॉडल विकसित

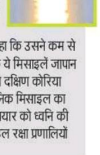
अमेरिकी अर्थशास्त्री रॉबर्ट हॉल और माइकल वुडफोर्ड को 2026 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। उन्हें यह पुरस्कार अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने के लिए दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों और वित्त मंत्रालयों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे बुनियादी मॉडल विकसित करने के दशकों के काम के लिए दिया गया। इनकी मदद से हम अर्थव्यवस्था में आने वाले झटकों, जैसे कि ऊर्जा संकट या परिवारों की खपत में अचानक बदलाव, से बेहतर ढंग से निपट सकते हैं। इस साल अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सम्मानित रॉबर्ट ई. हॉल और माइकल वुडफोर्ड ने नए वृहद आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं, जिनसे प्रभावशाली तरीके से अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी की स्थिति को नियंत्रित करने संबंधी नीतियों को लागू करने की हमारी क्षमता में काफी सुधार हुआ है। इन मॉडलों के आधार पर, सही समय पर राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के उपाय अपनाकर अर्थव्यवस्था में आने वाले उतार-चढ़ाव को कम किया जा सकता है। दोनों अर्थशास्त्रियों ने यह बताया कि कैसे वृहद आर्थिक मॉडल को सूक्ष्म आर्थिक आधारों पर फिर से बनाया जा सकता है-यह दिखाते हुए कि कैसे अलग-अलग परिवार और बिजनेस बचत और कीमत तय करने के बारे में भविष्य को ध्यान में रखकर फैसले लेते हैं, जिससे सेंट्रल बैंक और सरकारें लोगों की उम्मीदों को बेहतर ढंग से आकार दे सकती हैं और आर्थिक उतार-चढ़ाव को संतुलित कर सकती हैं। विजेताओं के कार्यों से नीति निर्माताओं को तेजी और मंदी से निपटने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होने में मदद मिलती है। नए ढांचे ने वैश्विक वित्तीय संकट के बाद नीति निर्माण में सहायता की है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के 70 वर्षीय वुडफोर्ड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'अधिकारियों को अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने के काम को सिर्फ ऐसे काम के तौर पर नहीं देखना चाहिए जिसमें लोग अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए लीवर खींचते हैं, और इसका अर्थव्यवस्था में मौजूद लोगों की समझ से कोई लेना-देना नहीं होता।'

-प्रोफेसर अर्थशास्त्र, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

करंट अफेयर

उ. कोरिया ने कई बैलिस्टिक मिसाइलें समुद्र की ओर दागीं

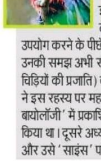
उत्तर कोरिया ने सोमवार को अपने पूर्वी समुद्री क्षेत्र की ओर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। दक्षिण कोरिया की सेना ने यह जानकारी दी। हाल के दिनों में हथियारों के प्रदर्शन की बढ़ती घटनाओं के बीच इस प्रक्षेपण से तनाव और बढ़ गया है। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत लंबे समय से ठप है। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने बताया कि ये मिसाइलें उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के आसपास के क्षेत्र से दागी गईं। उत्तर कोरिया ने हाल के वर्षों में अपने हवाई अड्डे का इस्तेमाल मिसाइलों के प्रक्षेपण के एक प्रमुख केंद्र के रूप में किया है। ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने तत्काल यह स्पष्ट नहीं किया कि कितनी मिसाइलें दागी गई या उन्होंने कितनी दूरी तय की। जापान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने कम से कम दो मिसाइलों का पता लगाया और आकलन किया कि ये मिसाइलें जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर समुद्र में गिरीं। यह प्रक्षेपण दक्षिण कोरिया द्वारा शुक्रवार को अपने देश में विकसित पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का उड़ान परीक्षण किए जाने के कुछ दिनों बाद हुआ। इस हथियार को ध्वनि की गति से कम से कम पांच गुना तेज उड़ान भरने और मिसाइल रक्षा प्रणालियों को चकमा देने के लिए तैयार किया गया है।



ऑफ बीट

केवल एक परमाणु पक्षी का रंग बदल सकता है

पूरे जंतु जगत में पक्षी सबसे रंगीन जीवों में से एक हैं। लेकिन इतने सारे रंगों वाले पक्षी अलग अलग कैसे होते हैं? रतमकीले लाल, नारंगी और पीले पंख या चोंच वाले लगभग सभी पक्षी अपने रंग उत्पन्न करने के लिए कैरोटीनॉयड नामक पिगमेंट के समूह का उपयोग करते हैं। लेकिन, ये पक्षी सीधे तौर पर कैरोटीनॉयड नहीं बना सकते। उन्हें अपने आहार में पौधों से ये तत्व प्राप्त करने होते हैं। तोते इस नियम के अपवाद हैं, जिन्होंने रंगीन रंगद्रव्य बनाने का एक बिल्कुल नया तरीका विकसित किया है, जिसे 'सिटाकोफल्विन'' कहते हैं। वैज्ञानिकों को इन विभिन्न रंगों के बारे में कुछ समय से जानकारी है, लेकिन पक्षियों द्वारा रंग में भिन्नता लाने के लिए इनका उपयोग करने के पीछे के जैव-रासायनिक और आनुवंशिकी आधार को लेकर उनकी समझ अभी सीमित है। हालांकि, तोते और 'फिंच' (रंग बिरंगी छोटी चिड़ियों की प्रजाति) के बारे में हाल ही में किए गए दो अलग-अलग अध्ययनों ने इस रहस्य पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। एक अध्ययन 'करेंट बायोलॉजी' में प्रकाशित हुआ है जिसका नेतृत्व हमने से एक (डैनियल हूपर) ने किया था। दूसरे अध्ययन का नेतृत्व पुर्तगाली जीवविज्ञानी रॉबर्टो अबेरे ने किया और उसे 'साइंस' पत्रिका में प्रकाशित किया गया।



अपने विचार
हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

प्रेरणा

संसार पर बलवानों ने नहीं, बुद्धिमानों ने शासन किया है। -नरेन्द्र कोहली

संपादकीय

नई चुनौतियों के लिए पुराने समाधान कारगर नहीं होंगे

लोक-प्रशासन के सिद्धांत के अनुसार जन-समस्याओं पर अफसरशाही का समाधान हमेशा घिसा-पिटा होता है, क्योंकि नए समाधानों के नाकाम होने के खतरे से अधिकारी-वर्ग डरता है। जेन-जी आंदोलन को किसान या मजदूर आंदोलन समझकर ट्रेनें और परिवहन के साधन रोकना, कर्फ्यू जैसी स्थिति पैदा करना, सड़कों पर लोहे के कीलें ठोकना, दिल्ली को छावनी बनाकर आंदोलनकारियों को बसों में ठूंसना आदि भी पुराने तरीके हैं। किसानों या मजदूरों के आंदोलन को विदेशी ताकतों का हाथ बताने की भी कोशिशें की गई थीं। लेकिन जेन-जी आंदोलन को भी जब विदेशी ताकतों के प्रभाव में आकर देश को अस्थिर करने की कोशिश करने वाला बताया गया तो लगा कि आंदोलन की प्रकृति को समझने में भूल हो रही है। भारत जैसी बड़ी इकोनॉमी को बाहरी ताकतें अगर अस्थिर कर सकती हैं तो इससे सरकार की कमजोर दिखेगी। ऐसे आरोप लगाना युवाओं की समझ को भी कमतर करके आंकना होगा। यह भी ध्यान रखें कि इन युवाओं को बसों में भर कर दूर कहीं छोड़ आएंगे तो उनका आहत भाव उन्हें फिर से वापस ला सकता है। इनको कष्ट पहुंचाने की खबर उनके अभिभावकों को भी चिंतित कर सकती है। नोएडा मजदूरों के आंदोलन में सामाजिक कार्यकर्ताओं पर एनएसए लगाने के फैसले पर पहले ही सवाल उठे हैं।

जीने की राह



पं. विजयशंकर मेहता

humarehanuman@gmail.com

हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो ईश्वर की शरणागति मिलेगी

भक्ति में शरणागति का बहुत महत्व है। हनुमान चालीसा शरणागति का मार्ग है। काकभुशुंडि जी ने श्रीराम जी से कहा था- भगत कल्पतरु प्रनत हित कृपा सिंधु सुखधाम, सोइ निज भगति मोहि प्रभु देहु दया करि राम। हे भक्तों के इच्छित फल देने वाले कल्पवृक्ष, हे शरणागति के हितकारी, कृपासागर सुखधाम राम जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए। यहां श्रीराम जी के लिए घोषणा की गई है कि वे शरणागत के हितकारी हैं और जो श्रीराम की शरण में गया, उसकी रक्षा होनी है। पिछले दिनों हमारी जहाज में रिमत मछर ने जिस तरह से हनुमान चालीसा को याद किया, वह इसी बात का प्रमाण है। जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हमें ईश्वर की शरणागति मिलती है। फिर ईश्वर अपनी शक्ति का कवच हमें देता है और वहीं से हमारा साहस परिणाम ले लेता है। रिमत मछर ने हवाई-हनुमान का अवतार करवाया है। हनुमान जी का यह रूप बड़ा अनूठा था। हमें समय रहते अपने बच्चों को हनुमान चालीसा से झसीलिए जोड़ना चाहिए कि उनके जीवन में जब ऐसी चुनौतियां आएं तो हनुमान चालीसा उनकी सहायक बने। • Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

विश्लेषण • चुनावी जनादेश पर देश में जारी है बहस

नागरिकता साबित करने का बोझ किस पर होना चाहिए?

एसआईआर



बरखा दत्त

फाउंडिंग एडिटर, मोजो स्टोरी

@BDUTT

इस बात से अंततः फर्क नहीं पड़ता कि आप भाजपा समर्थक हैं या कट्टीस समर्थक। लेकिन मतदाता सूचियों में संशोधन की जो प्रक्रिया एसआईआर के रूप में चली है, उसके परिणाम सबके सामने हैं। एक भारतीय के रूप में हम अक्सर अपने पड़ोसी देशों की राजनीतिक अस्थिरता को देखा करते थे। पाकिस्तान में सेना के नेतृत्व वाली सरकारें, बांग्लादेश में हिंसक अशांति, नेपाल और श्रीलंका में उथल-पुथल तथा म्यांमार में सैन्य तख्तापलट। ये दृश्य देखकर हमें अपने मजबूत लोकतंत्र पर स्वाभाविक गर्व होता था और रहत भी मिलती थी। हमारे यहां एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक सत्ता का हस्तांतरण हमेशा शांतिपूर्ण ढंग से होता रहा है।

लेकिन हमारे लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार चुनावी जनादेश पर सवाल हो रही है, उसे चुनौती दी जा रही है, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। माना कि ज्ञानेश कुमार पहले ऐसे सीईसी नहीं हैं, जिन पर राजनीतिक पक्षधरता का आरोप लगा हो। कट्टीस के शासनकाल में भी नवीन चावला पर ऐसे आरोप लगे थे। एम.एस.गिल तो चुनाव आयोग में भूमिका निभाने के बाद यूपीए सरकार में मंत्री भी बन गए थे। इन अर्थों में चुनाव आयोग के राजनीतिकरण का केवल झलिया इतिहास नहीं है। लेकिन इन दिनों जो हो रहा है, वह बिल्कुल अलग स्तर का है। हाल के वर्षों में चुनाव आयोग के आचरण को लेकर होने वाली बहसें मुख्यतः इस बात पर केंद्रित रही हैं कि क्या आदर्श आचार संहिता का पालन हुआ, या आयोग का कोई अधिकारी किसी खास नेता की हेट-स्पीच या हेलिकॉप्टर की चैकिंग को लेकर जरूरत से ज्यादा नरम या सख्त रहा। लेकिन यह पहली बार है, जब चुनावों को लेकर उठे विवाद ने संविधान-प्रदत्त मताधिकार को प्रभावित किया है।

चुनाव आयोग का काम और वास्तव में उसका कर्तव्य तो यही है कि वह ज्यादा से ज्यादा लोगों को चुनाव में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करे। इस पूरी कवायद की मूल भावना समावेशी ही होनी चाहिए। लेकिन एसआईआर की अपनी व्याख्या के तहत चुनाव आयोग ने इस भावना को उलट दिया और नागरिकों पर अपनी नागरिकता साबित करने की जिम्मेदारी डाल दी। अगर एसआईआर का मकसद भारत में अवैध रूप से रह रहे लोगों को मतदाता सूची से बाहर करना है, तो निश्चित रूप से इसका सबूत जुटाने की जिम्मेदारी राज्यसत्ता और उसकी सुरक्षा एजेंसियों की होनी चाहिए। फिर अचानक नागरिकों से नागरिकता साबित करने को क्यों कहा गया- वह भी इतनी जटिल प्रक्रिया के जरिए?

और हमेशा की तरह, इसकी मार गरीबों, बेघर लोगों और समाज के हाशिये पर जी रहे लोगों पर ज्यादा पड़ी है। शहरों से बाहर यात्रा करने वाला कोई भी व्यक्ति जानता है कि अगर आप किसी बुजुर्ग से उसकी उम्र पूछें, तो अक्सर उन्हें भी ठीक-ठीक पता नहीं होता। उनके पास जन्म प्रमाणपत्र जैसा कोई दस्तावेज सहेजकर रखा हुआ नहीं होता। ऐसे में एसआईआर को लेकर मौजूदा बहस के केंद्र में यही सवाल है कि नागरिकता साबित करने का बोझ किस पर होना चाहिए।

एसआईआर प्रक्रिया के समर्थकों ने विपक्ष के इस दावे को चुनौती देने के लिए चुनाव आयोग के आंकड़ों का हवाला दिया है कि देशभर में 13 करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। भाजपा ने हाल ही में बताया कि इनमें से 2.8 करोड़ नाम मृत लोगों के थे, जबकि 6.3 करोड़ लोग दूसरी जगह चले गए थे; एक करोड़ नाम दोहराव वाली प्रविष्टियां थीं और तीन करोड़ लोगों का पता नहीं चल पाया। इसके बावजूद, हर कोई किसी-न-किसी ऐसे व्यक्ति को जानता है, जिसे मतदाता सूची में

चुनाव आयोग का काम और वास्तव में उसका कर्तव्य तो यही है कि वह ज्यादा से ज्यादा लोगों को चुनाव में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करे। इस पूरी कवायद की मूल भावना समावेशी ही होनी चाहिए। इस पर सवाल उठना शुभ संकेत नहीं है।

अपना नाम जुड़वाने के लिए संघर्ष करना पड़ा है।

दिल्ली में तो निकट भविष्य में कोई चुनाव भी नहीं होना है, फिर भी मतदाताओं की संख्या 1.45 करोड़ से घटकर ड्राफ्ट लिस्ट में 97.53 लाख रह गई है। 33 लाख मतदाताओं को उन कारणों से नोटिस मिले, जिन्हें निर्वाचन आयोग ने 'तार्किक विसंगति' कहा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाया कि क्या ये नोटिस मशीनों से तैयार किए गए थे? बंगाल में तो नाम या उम्र में मेल न होने के चलते मतदाता सूचियों से 27.16 लाख नाम हटा दिए गए। निर्वाचन आयोग की इस कवायद के खिलाफ 22 लाख अपीलें दायर किए जाने की खबर है। अब तक केवल 1 लाख अपीलों का निपटारा हुआ है, जिनमें से 93 प्रतिशत मामलों में संबंधित लोगों को वैध मतदाता पाया गया।

आखिर ऐसी किसी व्यवस्था को कुशल कैसे माना जा सकता है, जो नागरिकों को अपने मतदान के अधिकार के लिए कानूनी पचड़ों से गुजरने पर मजबूर करती है? मतदान एक संवैधानिक अधिकार है, कोई विशेष सुविधा नहीं। **(ये लेखिका के अपने विचार हैं)**

दूरदृष्टि • विकास के साथ महंगाई बढ़ना नुकसानदेह

तेज आर्थिक ग्रोथ अब चुनावी सफलता की गारंटी नहीं है

इकोनॉमी



रुचिर शर्मा

ग्लोबल इन्वेस्टर व लेखक

breakoutnations@gmail.com

अमेरिकी राष्ट्रपतियों को अमूमन मिडटर्म चुनावों में नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन इस साल स्थिति असामान्य है। तीसरी तिमाही में आर्थिक वृद्धि की रफ्तार तेजी से बढ़कर 4% के करीब पहुंच गई, फिर भी ट्रम्प की लोकप्रियता में तेज गिरावट आ रही है। उनकी पार्टी का जनसमर्थन तेजी से खिसक रहा है। अगर अगले महीने वे कांग्रेस के दोनों सदनों में बहुमत खो देते हैं- जिसकी पूरी संभावना जताई जा रही है- तो 1950 के दशक के बाद यह पहला मौका होगा, जब अनुकूल आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद किसी सत्तारूढ़ राष्ट्रपति को ऐसी हार का सामना करना पड़ेगा।

ऐसा क्यों हो रहा है? वास्तव में, बहुत-से अमेरिकियों को यह उछाल गलत किस्म की आर्थिक तेजी लगती है। ऐसी तेजी, जिसके साथ जीवन-यापन की लागत बढ़ रही है और जिसका लाभ मुख्यतः अमीर उपभोक्ताओं को मिल रहा है। आर्थिक वृद्धि का बड़ा हिस्सा एआई में भारी निवेश से भी आ रहा है। लेकिन मतदाताओं में इस तकनीकी को लेकर पहले की किसी भी तकनीकी क्रांति के मुकाबले कहीं ज्यादा अंदेशा है।

ये सच है कि अर्थव्यवस्था को लेकर अमेरिकियों का असंतोष एआई और ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल, दोनों से पहले का है। कई दशकों से अमेरिकी अपने देश की स्थिति को लेकर लगातार अधिक असंतुष्ट होते गए हैं। लेकिन अमेरिका सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, ऐसा मानने वालों का अनुपात पिछले एक साल में 40% से गिरकर 20% रह गया है। इस निराशा की बड़ी वजह है- बढ़ती महंगाई और खर्च उठाने की मुश्किल। जीवन-यापन की लागत को सबसे अहम मुद्दा बताने वाले वोटरों का अनुपात छह गुना बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है- 25% से भी अधिक।

यह स्पष्ट है कि लोगों में सबसे अधिक नाराजगी किन चीजों की कीमतों को लेकर है- घर और एनर्जी। ईरान युद्ध के कारण तेल की आपूर्ति बाधित हुई है, जबकि एआई बिजली की मांग बढ़ा रहा है। पिछले एक साल में पेट्रोल की कीमतें 40% से अधिक बढ़ चुकी हैं और उपभोक्ता कीमतों में 3% से कहीं अधिक की दर से वृद्धि हो रही है। मॉर्गेज यानी होम लोन पर ब्याज दरें अब 7% से ऊपर पहुंच गई हैं। नतीजतन, अमेरिका में पिछले दो दशकों के किसी भी समय की तुलना में घर खरीदना अब अधिक मुश्किल हो गया है।

व्यापक धारणा यह है कि बिजली की भारी खपत करने वाले डेटा सेंटरों के कारण बिजली-पानी जैसे बुनियादी उपयोगों के बिल बढ़ रहे हैं। हर दस में से नौ अमेरिकी नहीं चाहते कि उनके शहर में ऐसा कोई डेटा सेंटर बने और ऐसी अधिकांश परियोजनाओं को स्थानीय स्तर पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के लिए कांग्रेस के चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए इन चिंताओं का समाधान करना मुश्किल है, क्योंकि उनके अपने राष्ट्रपति का कहना है कि डेटा सेंटरों का निर्माण धीमा करने से अमेरिका पिछड़ा और गरीब हो जाएगा!

इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि एआई डिजिटल युग का पहला ऐसा उत्पाद है, जिसे व्यापक स्तर पर नापसंद किया जा रहा है। पिछले दशकों में अमेरिकियों का स्मार्ट बहुमत कंप्यूटर और इंटरनेट को समाज के लिए बड़े लाभ के रूप में देखता आ रहा था। लेकिन अब अधिकांश लोग कहते हैं कि एआई को लेकर वे उत्साहित होने से अधिक चिंतित हैं। यह गिरावट बीस की उम्र वाले युवाओं में सबसे तेजी से बढ़ रही है, जिन्हें भविष्य में नौकरियां न रहने का डर सता रहा है। ईरान युद्ध की कीमत के रूप में मतदाताओं से महंगी चीजें

जीडीपी में तेज बढ़ोतरी भी अगर जमीनी स्तर पर लोगों के जीवन में नहीं झलकती तो राजनीतिक रूप से उसका कोई लाभ नहीं है। जनता का असंतोष कहीं सूक्ष्म आर्थिक पहलुओं से उपजता है। अमेरिका में ट्रम्प इसी का सामना कर रहे हैं।

स्वीकार करने और चीन से आगे बने रहने की कीमत के रूप में एआई को अपनाने की अपील करके ट्रम्प अमेरिकियों के मौजूदा मूड के विरुद्ध खड़े हो रहे हैं।

जीडीपी में तेज बढ़ोतरी भी अगर जमीनी स्तर पर लोगों के जीवन में नहीं झलकती तो राजनीतिक रूप से उसका लाभ नहीं है। जनता का असंतोष कहीं सूक्ष्म आर्थिक पहलुओं से उपजता है। मसलन, महंगाई के असर को समायोजित करने के बाद वेतन-वृद्धि की दर हाल की कुछ तिमाहियों में नकारात्मक हो गई है। इसका प्रमुख अपवाद वे कर्मचारी हैं, जिनके पास एआई स्किल्स हैं। उन्हें अपने समकक्षों की तुलना में 120% तक अधिक वेतन मिल रहा है। यह असंतोष भड़कने के लिए काफी है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

इस लेख को मोबाइल पर सुनने के लिए QR कोड को स्कैन करें।

दैनिक भास्कर

अब आप NYT के सभी आर्टिकल DB एप पर हर मंगलवार पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें डीबी एप।

© The New York Times

दैनिक भास्कर से विशेष अनुबंध के तहत

इस हफ्ते चर्चा में...

गोल्डमैन सॉक्स बैंक का अधिकारियों को तोहफा



4784 करोड़ रु.

इक्विटी के रूप में दिए हैं, गोल्डमैन सॉक्स बैंक ने कुल मिलाकर अपने बीस बड़े अधिकारियों को।

950 करोड़ रु.

का अनुबंध रिन्यू किया है, म्यूजिक कंपनी स्पोटिफाई ने अमेरिकन पॉडकास्टर जो रोगन के साथ।

287 करोड़ रु.

खर्च किए अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी ने अपने कैम्पस के गोल्फ कोर्स को फिर से बनाने पर।

टेक्नोलॉजी शीर्ष कंपनियों के 6 हजार अधिकारियों के सर्वे में 90 प्रतिशत ने माना- एआई से खास फायदा नहीं मिल रहा

एआई से रोजगार और प्रोडक्टिविटी में बहुत बदलाव नहीं, बचे समय का 37% आउटपुट सुधारने में ही खर्च

सारा कैस्टर

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से उत्पादकता बढ़ने और कामकाज में सुधार के बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कंपनियों में इसका असर उम्मीद के मुताबिक नहीं दिख रहा। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अटलांटा, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, बैंक ऑफ इंग्लैंड और ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट मेक्सिको के शोधकर्ताओं के सर्वे में करीब 6 हजार अधिकारियों में से 90% ने कहा कि एआई से उनकी कंपनियों को अब तक खास फायदा नहीं हुआ है। हालांकि, 69% ने बताया कि उनकी कंपनियां सक्रिय रूप से एआई का इस्तेमाल कर रही हैं।

एआई से होने वाली प्रोडक्टिविटी के फायदे भी व्यापक आर्थिक आंकड़ों में भी स्पष्ट नहीं दिख रहे। अपोलो के मुख्य अर्थशास्त्री टॉर्स्टन स्लोक के मुताबिक, फिलहाल एआई से उत्पादकता बढ़ने की उम्मीद एक पूर्वानुमान भर है। कंपनियों को नई तकनीक अपनाने और उसे कामकाज में प्रभावी ढंग से लागू करने में समय लगता है। एआई से काम तेजी से तैयार हो रहा है, लेकिन उसके नतीजों की जांच और सुधार के लिए इंसानों की जरूरत बनी हुई है। इसे 'वेरिफिकेशन टैक्स' यानी सत्यापन की अतिरिक्त लागत कहा जा रहा है। एआई के आउटपुट की सटीकता, सुरक्षा और उपयोगिता सुनिश्चित करने में समय लगता है।

मैसाचुसेट्स टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, स्लोन में एक शोध सहयोगी और व्याख्याता क्रिश्चियन कैटालिनी ने लिखा है केवल वही एआई उपयोगी है जो सत्यापित है। व्हार्टन स्कूल के शोधकर्ताओं ने गिटहब डेवलपर्स के विस्तृत आंकड़ों के विश्लेषण से पाया कि नए एआई कोडिंग टूल्स ने उनकी गतिविधि को बहुत बढ़ा दिया, 'लेकिन जैसे-जैसे काम कोड लिखने से सॉफ्टवेयर शिप करने की ओर बढ़ता है, इससे मिलने वाले फायदे तेजी से घटते जाते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि इसका मतलब है कि एआई से ज्यादा काम तैयार करना ही पर्याप्त नहीं है। उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की मानवीय क्षमता भी उत्पादकता तय करती है।

जांच करने के कारण उससे होने वाले फायदे कम होते हैं



एआई के काम को जांचने और उसे सुधारने का काम दक्षता से मिलने वाले कुछ लाभों को कम कर रहा हो सकता है। मानव संसाधन मंच कर्कडे द्वारा 3,200 कर्मचारियों और कंपनी प्रमुखों के सर्वेक्षण में पाया गया कि औसतन वे एआई के माध्यम से बचाए गए समय का लगभग 37 प्रतिशत हिस्सा कम क्वालिटी के आउटपुट को सुधारने, स्पष्ट करने या फिर से लिखने में उपयोग करते थे।

एआई आउटपुट की जांच जरूरी

गूगल के अर्थशास्त्रियों ने 600 वैज्ञानिकों के सर्वेक्षण में पाया कि एआई का उपयोग करने से उनके औसतन प्रति सप्ताह सात घंटे बचे। लेकिन उनमें से 90 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उन्होंने उस समय का दसवां हिस्सा एआई आउटपुट की जांच करने में बिताया। 46 प्रतिशत ने कहा कि उन्होंने एक चौथाई से अधिक समय बिताया।

परीक्षण में पिछड़ रहा

40% वैज्ञानिकों ने बताया कि तीन साल पहले की तुलना में उनके पास ऐसी धारणाओं की संख्या बढ़ गई है, जिनकी जांच जरूरी है। यह दर्शाता है कि एआई संभावित समाधान और भविष्यवाणियां तो तेजी से करता है, लेकिन उनका परीक्षण करने के लिए क्लिनिकल ट्रायल चलाना आवश्यक रूप से उतना तेज नहीं हुआ है। © The New York Times

हवाई यात्रा

ट्रम्प प्रशासन में यात्रियों के अधिकार कमजोर हुए

क्रिस्टीन लुंग

अमेरिका में ट्रम्प प्रशासन पर हवाई यात्रियों के अधिकार कमजोर करने के आरोप लग रहे हैं। परिवहन मंत्री सीन डफी के नेतृत्व में विभाग ने छिपे हुए शुल्कों, टिकट की कीमतों और उड़ानों में देरी पर मुआवजे से जुड़े कई उपभोक्ता संरक्षण नियमों को वापस लेने या कमजोर करने की दिशा में कदम उठाए हैं।

जून में विभाग ने उस नियम को छोड़ दिया, जिसके तहत एयरलाइंस को टिकट बुकिंग के दौरान सामान और टिकट में बदलाव जैसे अतिरिक्त शुल्क दिखाने थे। जुलाई में टिकट की अंतिम कीमत को अन्य शुल्कों से अधिक प्रमुखता से दिखाने की 15 साल पुरानी अनिवार्यता को बदलने का प्रस्ताव भी दिया गया। विभाग ने परिवारों को बिना अतिरिक्त शुल्क साथ बैठाने और उड़ानों में बड़े व्यवधान पर नकद मुआवजे से जुड़े प्रस्ताव भी छोड़ दिए हैं।

उपभोक्ता संगठनों के मुताबिक, डफी के कार्यकाल में विभाग ने एयरलाइंस पर कोई नया जुर्माना नहीं लगाया। साथ ही, कम से कम 239 करोड़ रुपए के पुराने जुर्माने भी माफ किए गए। विभाग का कहना है कि यात्रियों के अधिकार कम नहीं किए गए हैं और उसका ध्यान उड़ानों में व्यवधान के मूल कारण दूर करने पर है।

© The New York Times

हमला रियाद एयरपोर्ट पर हमले में 12 की मौत, 300 से ज्यादा घायल

हूतियों के खिलाफ सऊदी प्रिंस के पास विकल्प कम हैं

विवियन नेरीम और लिसा फ्रीडमैन

ईरान समर्थित हूती लड़ाकों के हमलों ने सऊदी अरब की सुरक्षा और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की महत्वाकांक्षी योजनाओं के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। पिछले एक सप्ताह में रियाद के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तीन घातक हमले हुए। शनिवार को यात्री टर्मिनल पर हुए हमले में कम से कम 12 लोगों की मौत हुई और 300 से ज्यादा घायल हो गए। इसके बाद हवाई अड्डे का संचालन रोकना पड़ा।

विश्लेषकों के मुताबिक, हूतियों को सैन्य कार्रवाई से पूरी तरह हराना मुश्किल है, जबकि उनकी बढ़ती मांगों के कारण राजनीतिक समझौता भी आसान नहीं है। सऊदी अरब को हूतियों के खिलाफ अमेरिका से सैन्य मदद मिल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हमले के बाद संघर्ष में सीधे हस्तक्षेप पर फैसला करने की बात कही है।



करीब एक दशक पहले सऊदी नेतृत्व में यमन में चलाए गए बमबारी अभियान के बावजूद हूती उत्तरी यमन पर अपना नियंत्रण बनाए रखने में सफल रहे। अब वे सऊदी अरब के बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि रियाद एयरपोर्ट पर हमले से विदेशी निवेशक सऊदी अरब में निवेश के फैसले पर दोबारा विचार कर सकते हैं। इससे देश को कारोबार और पर्यटन का वैश्विक केंद्र बनाने की योजना प्रभावित हो सकती है।

लाल सागर में नाकेबंदी

जुलाई में यमन की राजधानी सना के हवाई अड्डे पर हमले के बाद हूतियों ने 'नाकेबंदी के जवाब में नाकेबंदी' की नीति घोषित की। उन्होंने लाल सागर में सऊदी जहाजों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। होर्मुज से तेल की आवाजाही बाधित होने के बाद लाल सागर सऊदी तेल निर्यात का महत्वपूर्ण वैकल्पिक मार्ग बन गया है।

युद्धविराम टूटा, संघर्ष फिर तेज

2022 में हुए युद्धविराम से यमन में नाजुक शांति बनी थी। लेकिन ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमलों के बाद क्षेत्रीय युद्ध भड़क गया। पिछले सप्ताह यमन की सरकार ने हूतियों के खिलाफ नया सैन्य अभियान शुरू किया। सऊदी अरब ने भी सरकार के समर्थन में बमबारी अभियान शुरू किए। © The New York Times

समझौता

चीन-ईयू: हाइब्रिड कारों पर टला टैरिफ विवाद

कीथ ब्रैडशर

चीन और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच बीजिंग में हुई वार्ता में हाइब्रिड कारों के व्यापार को लेकर सहमति बनी है। दोनों पक्षों के बीच संभावित व्यापार युद्ध टलने की उम्मीद है। समझौते के तहत चीन अगले चार वर्षों में ईयू को हाइब्रिड कारों का निर्यात 50% तक घटाएगा। इसके बदले ईयू इन वाहनों पर तत्काल टैरिफ नहीं लगाएगा।

चीन के वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक, यह समझौता विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नियमों के अनुरूप है। इसका उद्देश्य यूरोपीय बाजार में चीनी कार कंपनियों के बीच अत्यधिक प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित करना भी है। पिछले तीन वर्षों में चीन से प्लग-इन हाइब्रिड कारों का निर्यात 10 हजार से कम मासिक इकाइयों से बढ़कर करीब 2 लाख इकाई प्रति माह हो गया था।

© The New York Times

सेहत 1.17 लाख से ज्यादा महिलाओं पर अध्ययन

स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से दिल को भी होता है फायदा, हार्ट अटैक का जोखिम 44% तक कम

हिलेरी ओब्रेर

1950 के दशक से वैज्ञानिक मानते आए हैं कि दौड़ना, तैराकी और साइकिल चलाने जैसी एरोबिक एक्सरसाइज दिल की सेहत के लिए फायदेमंद हैं। वहीं, वजन उठाने यानी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अब तक मुख्य रूप से मांसपेशियों और हड्डियों की मजबूती से ही जोड़कर देखा जाता था, लेकिन हालिया रिसर्च बताती है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी हृदय रोगों का जोखिम कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

1.17 लाख से ज्यादा महिलाओं पर 14 वर्षों से अधिक चले अध्ययन में पाया गया कि 48 से 66 वर्ष की जिन महिलाओं ने सप्ताह में कम से कम दो घंटे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, उनमें हार्ट अटैक का जोखिम 44% कम पाया गया। यह तुलना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करने वाली महिलाओं से की गई।



मेटाबॉलिज्म सुधरता है

अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने वाले वयस्कों में किसी भी कारण से मृत्यु का जोखिम लगभग 15% और हृदय रोगों का जोखिम 17% कम पाया गया है। हालांकि, केवल कार्डियो एक्सरसाइज करने वालों में भी इसी तरह के लाभ देखे गए।

© The New York Times

बाजार की दो तस्वीरें • दुनिया के 18 बड़े बाजारों में निफ्टी का प्रदर्शन दूसरा सबसे खराब, पर एसआईपी निवेशक डटे हुए हैं

सालभर में शीर्ष 10 कंपनियों का औसत रिटर्न -20 फीसदी

भास्कर न्यूज | मुंबई

महंगे कच्चे तेल, बढ़ते बॉन्ड यील्ड और विदेशी निवेशकों की बिकवाली से सोमवार को शेयर बाजार शुरुआती बहुत गंवाकर गिरावट में बंद हुआ। सेंसेक्स 547.65 अंक यानी 0.76% गिरा। दो साल से भारतीय मार्केट फ्लैट है, जबकि दुनिया के शेयर बाजारों में एआई की तेजी का फायदा कोरिया और ताइवान को मिल रहा है। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक, बीते एक साल में 18 प्रमुख बाजारों में निफ्टी का प्रदर्शन दूसरा सबसे कमजोर रहा। सिर्फ इंडोनेशिया का बाजार इससे ज्यादा गिरा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी इसी दौरान 86.7% और ताइवान का ताइएक्स 80.6% चढ़ा। दूसरी ओर, भारत की सबसे मूल्यवान 10 कंपनियों का संयुक्त रिटर्न करीब 20% निगेटिव रहा। टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर और रिलायंस की गिरावट ने दबाव बढ़ाया। भारतीय कंपनियों की कमाई बढ़ने के बावजूद निवेशक उनके शेयरों के लिए पहले जितनी कीमत देने को तैयार नहीं हैं। महंगे कच्चे तेल, कमजोर रुपए और विदेशी निवेशकों की निकासी ने चुनौती बढ़ाई है। अब रुपए में सुधार और वैश्विक अनिश्चितता कम होना अहम है।

एआई के दम पर दक्षिण कोरिया का बाजार 87%, ताइवान 81% चढ़ा; निफ्टी 11% टूटा

कोरियाई कंपनी सैमसंग ने लाभांश सहित 215%, एसके हाइनिक्स ने 352% और टीएसएमसी ने 74.6% रिटर्न दिया। कोरिया की शीर्ष 10 कंपनियों का संयुक्त रिटर्न 211% रहा। भारत में टीसीएस 34.5%, एचडीएफसी बैंक 34%, एचयूएल 30% और रिलायंस 21.6% गिरे। ब्लूमबर्ग के सैंपल में भारतीय कंपनियों का कुल मुनाफा 6% बढ़ा। फिर भी निफ्टी का कीमत-कमाई अनुपात 23.6 से घटकर 20.3 रह गया। यानी निवेशक हर 1 कमाई के लिए पहले 23.60 देते थे, अब 20.30 दे रहे हैं। ताइवान में यह अनुपात 23.1 से बढ़कर 27.9 हुआ। कोरिया में कमाई शेयर भाव से तेज बढ़ी, इसलिए अनुपात घटा।

दो साल में निफ्टी में ₹100 का निवेश 90, कोरिया में ₹255

बाजार	एक साल का बदलाव	दो साल में वृद्धि
कोस्पी	86.7%	₹255
ताइएक्स	80.6%	₹218
निक्केई 225	42.1%	₹176
स्ट्रेट्स टाइम्स	21.7%	—
एसऐंडपी 500	15.8%	₹135
एफटीएसई 100	10.9%	₹128
शंघाई कंपोजिट	3.1%	—
हैंगसेंग	9.5%	₹117
निफ्टी 50	10.6%	₹90
जकार्ता कंपोजिट	26.1%	—

स्रोत: ब्लूमबर्ग

एआई की तेजी पर संशय, भारत की लंबी अवधि पर भरोसा

इक्विनॉमिक्स रिसर्च के जी. चोकालिंगम के मुताबिक, महंगे तेल और कमजोर रुपए ने भारत पर दोहरा असर डाला है। विदेशी निवेश लौटने के लिए रुपए में सुधार जरूरी है। उन्हें एआई की तेजी टिकने पर संशय है, लेकिन भारत के अगले तीन-चार वर्षों को लेकर भरोसा है। हालांकि, युद्ध छह महीने और खिंचा तो बड़े झटके की आशंका भी जताते हैं।

एशिया की बड़ी लिस्टेड कंपनियों के बाजार मूल्य में ताइवान आगे

देश	बाजार मूल्य
ताइवान	4.59 लाख करोड़ डॉलर
भारत	3.67 लाख करोड़ डॉलर
दक्षिण कोरिया	3.62 लाख करोड़ डॉलर

डॉलर में निफ्टी 50 की कंपनियों का बाजार मूल्य एक साल में 17.3% घटकर 1.88 लाख करोड़ डॉलर रहा।

इक्विटी फंड में 31% निवेश बढ़ा, रिकॉर्ड एसआईपी भी

भास्कर न्यूज | मुंबई

शेयर बाजार में दो साल से जारी गिरावट के बीच निवेशकों का भरोसा कायम है। एम्फी के मुताबिक, बीते महीने सितंबर में निवेशकों ने इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में 38,307 करोड़ का शुद्ध निवेश किया। स्मॉलकैप में सर्वाधिक 9,039 करोड़ और मिडकैप में 7,835 करोड़ आए। दोनों मिलकर कुल इक्विटी निवेश का 44% रहे। इक्विटी की 13 में से 11 कैटेगरी में शुद्ध निवेश आया। केवल कॉन्ट्रा और ईएलएसएस से निकासी हुई। हालांकि, डेट योजनाओं से 1.83 लाख करोड़ निकलने से पूरे उद्योग में निवेश से ज्यादा निकासी हुई। महीने के अंत में म्यूचुअल फंडों के पास निवेशकों की कुल संपत्ति 82.64 लाख करोड़ रही। सितंबर में एसआईपी योगदान रिकॉर्ड 32,490 करोड़ रहा। अगस्त में यह 32,297 करोड़ था, यानी करीब 193 करोड़ (0.6%) की बढ़त।

एसबीआई म्यूचुअल फंड के मनीष मेहता के अनुसार एडवांस टैक्स और तिमाही-अंत अनुपालन के कारण संस्थागत निवेशकों ने पैसा निकाला। एसआईपी के आंकड़े लगभग स्थिर रहे, पर अस्थिरता का फायदा उठाने के लिए निवेशकों का एसआईपी पर भरोसा सुखद है।

लार्जकैप, सेक्टोरल फंड में निवेश लौटा, डेट से 1.8 लाख करोड़ निकले

कैटेगरी	अगस्त	सितंबर	मासिक बदलाव
इक्विटी फंड कुल	29,329	38,307	30.6%
स्मॉलकैप	7,973	9,039	13.4%
मिडकैप	6,989	7,835	12.1%
फ्लेक्सीकैप	5,059	6,702	32.5%
लार्जकैप	1,147	859	निवेश लौटा
सेक्टोरल	53	1,840	निवेश लौटा
डेट फंड कुल	8,127	1,83,156	22.5 गुना निकासी
हाइब्रिड फंड कुल	10,045	457	निकासी
पूरा उद्योग	41,354	1,33,376	निकासी

राशि करोड़ रुपए में, स्रोत: एम्फी

गोल्ड ईटीएफ में निवेश 71% बढ़कर 4,451 करोड़

कैटेगरी	अगस्त	सितंबर	मासिक बदलाव
गोल्ड ईटीएफ	2,597	4,451	71.4%
सिल्वर ईटीएफ	1,271	1,974	55.4%

राशि करोड़ रुपए में, स्रोत: एम्फी

एक्सपर्ट व्यू • सिर्फ किसी फंड में पुराने रिटर्न देख कर पैसा न लगाएं, आगे कमाई तय करेगी तेजी

फोन पे के म्यूचुअल फंड प्रमुख नीलेश डी नाइक के मुताबिक, पिछले वर्षों के बेहतर रिटर्न और कंपनियों के बढ़ते मुनाफे ने स्मॉलकैप-मिडकैप में निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। लेकिन बड़ी कंपनियों के मुकाबले इनके शेयर महंगे हैं। आगे तेजी के लिए कंपनियों की कमाई बढ़ना जरूरी होगा; पुराने रिटर्न दोहराए जाने की गारंटी नहीं है। मॉर्निंगस्टार के हिमांशु श्रीवास्तव चेताते हैं कि ऊंचे मूल्यांकन और ज्यादा उतार-चढ़ाव के कारण इनमें जोखिम भी अधिक है। पूरा पैसा एक श्रेणी में लगाने से बचें।

बजट सेगमेंट में सुस्ती

महंगे फोन 12 से 24 माह में बदलने का ट्रेंड

बिज़नेस संवाददाता | नई दिल्ली

इस त्योहारी सीजन में पहली बार फोन खरीदने के बजाय पुराना फोन बदलकर बेहतर मॉडल लेने का रुझान दिख रहा है। यह रुझान महानगरों से छोटे शहरों तक पहुंच रहा है। महंगे स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले ग्राहक अब जल्दी फोन बदल रहे हैं। सर्विफाई के संस्थापक और सीईओ श्रीवत्स प्रभाकर के मुताबिक, एक लाख रुपए से ज्यादा कीमत वाले फोन की मांग मुख्यतः उन ग्राहकों से आ रही है, जो हर 12-24 महीने में नया फोन लेते हैं। इसमें फोल्ड होने वाले फोन भी शामिल हैं। 60 हजार से एक लाख रुपए की श्रेणी में किस्तों और पुराने फोन के बदले नए लेने की सुविधा खरीद का बड़ा सहारा है। बिक्री में महंगे फोन का हिस्सा बढ़ने से कम फोन बिकने पर भी रकम बढ़ने का अनुमान है। सर्विफाई के मुताबिक, मध्यम कीमत वाले फोन के मुकाबले महंगे स्मार्टफोन के साथ सुरक्षा योजना लेने की दर 30-40% ज्यादा है। कंपनियां ऐसी योजनाओं को किस्तों और फोन बदलने के प्रस्तावों के साथ जोड़ रही हैं। सालाना तीन लाख से ज्यादा डिवाइस एक्सचेंज संभालने वाली सर्विफाई के मुताबिक, अक्टूबर-नवंबर में एक्सचेंज सामान्य महीनों से करीब 50% ज्यादा रहता है।

फेस्टिव सीजन में स्मार्टफोन की बिक्री 12% घटेगी, पर बिक्री मूल्य 5% बढ़ सकता है

पूरे बाजार की तस्वीर अलग है। काउंटरपॉइंट रिसर्च का अनुमान है कि त्योहारों में फोन की बिक्री संख्या 12% घटने, लेकिन बिक्री मूल्य 5% बढ़ने का अनुमान है। रिसर्च डायरेक्टर तरुण पाठक के मुताबिक, बढ़ती कीमतों से कई ग्राहक गैरजरूरी खरीद टाल रहे हैं।

10 हजार रुपए से सस्ते फोन की बिक्री 20% घटने का अनुमान: काउंटरपॉइंट के मुताबिक, 2026 में 10 हजार से सस्ते स्मार्टफोन की बिक्री संख्या 20% घट सकती है। मेमोरी और अन्य पुर्जे महंगे होने से कंपनियां कीमतें बढ़ा रही हैं और सस्ते फोन की श्रेणी में अपनी मौजूदगी घटा रही हैं। कंपनियों के पास बड़ी छूट देने की गुंजाइश सीमित है। इसलिए आसान किस्तें, पुराने फोन की बेहतर कीमत और तय शर्तों पर वापस खरीदने की योजनाएं बिक्री का सहारा बनेंगी।

बिज़नेस ब्रीफ

देश में पांच साल में 620 चिप स्टार्टअप आए

नई दिल्ली | भारत में घरेलू चिप उद्योग को बढ़ावा मिलने से पांच साल में 620 सेमीकंडक्टर स्टार्टअप बने हैं। इन्होंने कुल एक अरब डॉलर (9,600 करोड़ रुपए) से ज्यादा निवेश जुटाया। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, ट्रैक्सन और उद्योग के अनुमानों के मुताबिक, 2026 में सात अधिग्रहणों की घोषणा हुई है। स्टार्टअप ने 2025 में 47.4 करोड़ डॉलर और इस साल अक्टूबर की शुरुआत तक 22.87 करोड़ डॉलर जुटाए।

चीन ने सितंबर में रिकॉर्ड 23 टन सोना खरीदा

बीजिंग | अमेरिका में ऊंची ब्याज दरों और मजबूत डॉलर के दबाव से सितंबर में सोना 6% से ज्यादा गिरा। इस बीच चीन के केंद्रीय बैंक ने 23 टन सोना खरीदा, जो तीन साल की सबसे बड़ी मासिक खरीदी की है। चीन ने लगातार 23 महीने से खरीद जारी रखी है। चीन ने 2026 के पहले आठ महीनों में 1,000 टन से ज्यादा सोना आयात किया। पहली छमाही में वहां सोने की छड़ों और सिक्कों की मांग 28.42% बढ़ी।

टीसीएसः नई भर्तियों में 80% एआई वाले होंगे

बेंगलुरु | टीसीएस की नई भर्तियों में 80% कर्मचारी डिजिटल और एआई कौशल वाले होंगे। मुख्य परिचालन अधिकारी आरती सुब्रमणियन ने बताया कि सितंबर तिमाही में जोड़े गए करीब 4,500 कर्मचारियों में 25-30% एआई कौशल वाले थे। कंपनी के कुल राजस्व में एआई आधारित काम की हिस्सेदारी 10% पहुंच गई है। सीईओ के. कृतिवासन के मुताबिक, एआई सौदों का आकार बढ़ने से मुनाफे का मार्जिन सुधरेगा।

लग्जरी टूरिज्म... 5 साल दुनिया घूमेगा अटलांटिक, 12 लोगों के समूह के लिए 7 रातों का किराया ₹1.6 करोड़



मिलान | समुद्र के रास्ते दुनिया घूमने के शौकीनों के लिए आलीशान पाल नौका 'अटलांटिक' पांच साल की यात्रा पर निकलने वाली है। इसमें पूरे सफर के बजाय कम से कम सात रातों के लिए शामिल हो सकेंगे। अधिकतम 12 मेहमानों के लिए पूरी नौका बुक करने का किराया करीब 1.70 लाख डॉलर (1.64 करोड़ रुपए) से शुरू है।





छह आलीशान केबिन और 12 कर्मचारियों के रहने की जगह है। मेहमान गोताखोरी, स्नॉर्कलिंग और वाटर-स्की का आनंद ले सकेंगे।

नतीजे • टेक दिग्गज ने चौंकाया... आय 11.5% बढ़ी, 12 रुपए डिविडेंड का भी ऐलान

एचसीएल का मुनाफा 21% बढ़ा, एआई कारोबार में 78% उछाल; ट्रेंड के उलट 6,450 कर्मचारी भी जोड़े

भास्कर न्यूज | मुंबई

एचसीएल टेक्नोलॉजीज का जुलाई-सितंबर तिमाही में शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 21% बढ़कर 5,132 करोड़ रहा। आय 11.5% बढ़कर 35,620 करोड़ रही। तिमाही आधार पर मुनाफा 11% और आय आय 3% बढ़ी। मजबूत आईटी सेवाओं, धीमी खर्च-वृद्धि और कम टैक्स से फायदा मिला। एडवांस्ड एआई राजस्व 21.9 करोड़ डॉलर रहा; स्थिर विनिमय दर पर सालाना 78% और तिमाही 28.4% बढ़ा। नए सौदे करीब 2,102 करोड़ रुपए के रहे। सीईओ एवं एमडी सी. विजयकुमार के मुताबिक, छमाही की बुकिंग रिकॉर्ड रही और एआई पेशकशों को अच्छी प्रतिक्रिया मिली। कंपनी ने प्रति शेयर 12 रुपए डिविडेंड देने का भी ऐलान किया।

एचसीएल टेकः जुलाई-सितंबर तिमाही का रिजल्ट (कन्सॉलिडेटेड) एक नजर में

मापदंड	Q2 FY27	Q2 FY26	अंतर
ऑपरेटिंग आय	35,620	31,942	+11.5%
टैक्स पूर्व लाभ	6,467	5,702	+13.4%
ऑपरेटिंग मार्जिन	18.15%	17.38%	+0.77 pp
टैक्स बाद शुद्ध लाभ	5,132	4,235	+21.2%

आंकड़े करोड़ रुपए में, मार्जिन को छोड़कर। pp = प्रतिशत अंक। स्रोतः कंपनी फाइलिंग

HCL 12 अक्टूबर को बीएसई पर मार्केट कैप ₹3.31 लाख करोड़ रहा।

बिक्री से लगभग दोगुनी रफ्तार से मुनाफा क्यों बढ़ा?

खर्च धीमे बढ़े... राजस्व 11.5% बढ़ा, लेकिन कुल खर्च 10.1% बढ़कर 29,349 करोड़ रहा। कर्मचारी लाभ खर्च की बढ़त 8.3% रही।

आईटी सेवाओं से लाभ 30.3% बढ़कर 4,995 करोड़ पहुंचा।

टैक्स खर्च घटा... कर-पूर्व लाभ 13.4% बढ़ा, फिर भी टैक्स खर्च 1,466 करोड़ से घटकर ₹1,335 करोड़ रहा।

कर राहत की वजह... अधिग्रहण से मिली कुछ पूंजीगत संपत्तियों पर लाभ, अनिश्चित कर मामलों के समाधान और नई कर व्यवस्था में बदलाव से टैक्स खर्च कम हुआ।

कर्मचारियों की संख्या 2.3 लाखः टेक कंपनियों में छंटनी के दौर के बीच एचसीएल में बीती तिमाही 6,450 कर्मचारी जुड़े। कंपनी ने 6,136 नए ग्रेजुएट को भी जोड़ा।

एआई की बढ़ती कमाई से रणनीति पर भरोसा मजबूत

चेयरपर्सन रोशनी नाडर मल्होत्रा के मुताबिक, एडवांस्ड एआई राजस्व की तेज बढ़त कंपनी की कारोबारी रणनीति को सही साबित करती है। एआई सेक्टर में साझेदारियां और निवेश कंपनियों तथा सरकारों के लिए भरोसेमंद तकनीकी साझेदार बनने में मदद कर रहे हैं।

आगे का अनुमान...

कंपनी ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए स्थिर विनिमय दर पर राजस्व में 2.5-4% और सेवाओं में 3-4% बढ़त का अनुमान दिया है। परिचालन मार्जिन का अनुमान 17.5-18.5% बरकरार है। सितंबर तिमाही का मार्जिन 18.2% रहा।

टीवीएस परिवार में संपत्ति बंटवारे पर विवाद खुलकर सामने आया

वेणु श्रीनिवासन की पत्नी और बेटी बोलीं- आर्थिक हिस्सेदारी पर समझौता नहीं हुआ, समाधान चाहिए

बिज़नेस संवाददाता | मुंबई

टीवीएस ग्रुप के वेणु श्रीनिवासन परिवार में संपत्ति और मालिकाना हिस्सेदारी का विवाद खुलकर सामने आ गया है। उनकी पत्नी मल्लिका श्रीनिवासन और बेटी लक्ष्मी वेणु ने संयुक्त बयान में कहा कि परिवार के भीतर आर्थिक हिस्सेदारी का कोई समझौता नहीं हुआ है। कारोबार चलाने की जिम्मेदारियों को संपत्ति का बंटवारा बताना गलत है। हम सौहार्दपूर्ण समाधान चाहते रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह की बातें सामने रखी जा रही हैं, उसमें तथ्य स्पष्ट करना जरूरी है।'

विवाद की जड़ः किसे कितना आर्थिक हिस्सा मिलेगा?



लक्ष्मी वेणु

मल्लिका श्रीनिवासन

मां-बेटी को आशंका है कि बच्चों को संभालने के लिए मिले कारोबार ही संपत्ति बंटवारे का आधार बन सकते हैं। सुदर्शन वेणु ₹1.86 लाख करोड़ वाली टीवीएस मोटर संभालते हैं।

2020 का समझौता अलगः तब टीवीएस परिवार की चार शाखाओं के बीच आपसी शेयरधारिता खत्म कर कारोबार का स्वामित्व संबंधित शाखाओं से जोड़ने पर सहमति बनी थी। मल्लिका और लक्ष्मी के मुताबिक, परिवार के भीतर आर्थिक हिस्सेदारी के लिए वैसा पारदर्शी मूल्यांकन और समझौता नहीं हुआ।

ब्रांड का समझौता, संपत्ति का नहीं: मां-बेटी के अनुसार, ट्रेडमार्क, ब्रांड इस्तेमाल और एक-दूसरे के कारोबार में प्रतिस्पर्धा नहीं करने की शर्तों को बंटवारा नहीं माना जा सकता। ट्रैक्टर फर्म टाफे अलग अमलगमेशंस समूह का हिस्सा है। उसे आर्थिक हिस्सेदारी के विवाद से जोड़ना गलत है।

सीमेंट के दाम 10 से 15 रुपए बढ़ने के आसार

बिज़नेस संवाददाता | मुंबई

अक्टूबर के मध्य से सीमेंट के दाम 10 से 15 रुपए प्रति बोरी बढ़ सकते हैं। एमके रिसर्च के मुताबिक, ईंधन और पैकिंग महंगी होने से कंपनियों पर कीमतें बढ़ाने का दबाव है। पिछले 6-7 महीनों से उत्पादन लागत 300 से 400 रुपए प्रति टन बढ़ी है। पहली तिमाही में भी कंपनियों ने 10 से 15 रुपए प्रति बोरी दाम बढ़ाए थे, लेकिन इससे बढ़े खर्च की पूरी भरपाई नहीं हुई। जुलाई-अगस्त में मानसून के कारण भाव नरम पड़ने से मुनाफे पर दबाव बढ़ा। रिपोर्ट के अनुसार, निर्माण गतिविधियां तेज होने से अगले 18 महीने मांग मजबूत रह सकती है। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में बिक्री की मात्रा सालाना 7 से 8% बढ़ने का अनुमान है।

संकट • टेंडर पूरा होने के बाद लागू करने में एक साल लग सकता है

ईपीएफओ 3.0 का टेंडर अधूरा, गिग वर्कर्स की बीमा-पेंशन योजनाओं में देरी की आशंका

अहोना मुखर्जी | नई दिल्ली

देश के 1 करोड़ से ज्यादा गिग, असंगठित और कंस्ट्रक्शन वर्कर को पेंशन व सरकारी योजनाओं का फायदा मिलने में अभी और वक्त लगेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) का नया 'ईपीएफओ 3.0' प्लेटफॉर्म चालू होने में कम से कम एक साल और लगेंगे। इसकी वजह यह है कि तकनीकी पार्टनर चुनने के लिए टेंडर का दस्तावेज तैयार ही हो रहा है। ईपीएफओ ने अक्टूबर 2025 तक टेंडर पूरा कर एक साल में इसे लागू करने का लक्ष्य रखा था, जो पीछे छूट गया है। नए सिस्टम से कोर बैंकिंग, क्लाउड और एपीआई-आधारित आईटी सिस्टम तैयार होना है। इसी पर श्रम मंत्रालय गिग वर्कर्स के लिए बीमा व यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाएगा। श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ ने इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।

मांग • सिस्टम बनने तक अधिकार न रोके सरकार

गिग वर्कर्स एसोसिएशन के संगठन सचिव नितेश कुमार दास ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा सुविधा नहीं, वर्कर की सबसे बड़ी जरूरत है। नया प्लेटफॉर्म बनने में समय लग सकता है, लेकिन तकनीक के इंतजार में वर्कर्स को हादसों, बीमारी और बुढ़ापे के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता।

चुनौती • गिग वर्कर पर पुराना पीएफ लागू नहीं

टीमलीज रेगटेक के सीईओ ऋषि अग्रवाल का कहना है कि पीएफ का पुराना तरीका गिग वर्कर पर लागू करना मुश्किल है। नौकरीपेशा लोगों को तय सैलरी मिलती है, जबकि गिग वर्कर को हर काम के हिसाब से पैसा मिलता है। ऐसे में नियम साफ होने चाहिए।

आयकर विभाग • जोमैटो-स्विगी के डेटा से बड़ा खुलासा

रेस्तरां कारोबार में ₹25 हजार करोड़ की कर चोरी का संदेह

बिज़नेस संवाददाता | नई दिल्ली

आयकर विभाग रेस्तरां कारोबार में 25,000 करोड़ की संदिग्ध टैक्स चोरी को लेकर अभियान चलाने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, स्विगी, जोमैटो के आंकड़ों की जांच में 8,000 ऐसे रेस्तरां मिले, जिनकी कमाई पर टीडीएस कटा, लेकिन उन्होंने आईटीआर नहीं भरा। अनुमानित टैक्स चोरी 2021-22 से 2024-25 के बीच 7,500 करोड़ बताई गई है। कई रेस्तरां सालाना 2-5 करोड़ कमाते हैं। विभाग कम आय दिखाने वाले प्रतिष्ठानों की पहचान कर उनसे रिटर्न भरने और बकाया कर चुकाने को कहेगा।

आखिर टैक्स चोरी का संदेह कैसे गहराया?

कमाई का रिकॉर्ड, रिटर्न गायबः जोमैटो, स्विगी जैसी डिलीवरी मंचों से भुगतान और टीडीएस के आंकड़े मिले, लेकिन संबंधित रेस्तरां के रिटर्न नहीं मिले।

ऑनलाइन स्विग्गी पूरी तस्वीर नहीं: रेस्तरां में बैठकर खाने से कमाई डिलीवरी की तुलना में तीन-चार गुना होती है। इसलिए वास्तविक कारोबार ज्यादा होने की आशंका।

पहले भी कम आय दिखाईः करीब 1.8 लाख रेस्तरां के पुराने आकलन में औसतन 30-35% आय कम दिखाने की बात सामने आई थी।

बिज़नेस एंकर लोग खर्च कैसे तय करते हैं, कंपनियां दाम कैसे बढ़ाती हैं-इन फैसलों को समझकर ब्याज दरों की नीति का आधार दिया

महंगाई-मंदी रोकने का फॉर्मूला देने वाले हॉल-वुडफोर्ड को अर्थशास्त्र का नोबेल

The New York Times
दैनिक भास्कर से विशेष अनुबंध के तहत

एरो नेल्सन | न्यूयॉर्क

तेल महंगा हो जाए तो महंगाई कैसे रोकें कि कारोबार और नौकरियों पर ज्यादा चोट न पड़े? लोग अचानक खरीदारी घटा दें तो अर्थव्यवस्था को कैसे संभालें? ऐसे सवालों के जवाब तलाशने में मदद करने वाले अमेरिकी अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट हॉल और माइकल वुडफोर्ड को अर्थशास्त्र का 2026 का नोबेल स्मृति पुरस्कार मिला है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के हॉल और कोलंबिया विश्वविद्यालय के वुडफोर्ड ने परिवारों और कंपनियों के फैसलों को पूरी अर्थव्यवस्था के उतार-चढ़ाव से जोड़कर समझाया। इनके शोध से सरकारों और केंद्रीय बैंकों को यह आकलन करने का बेहतर आधार मिला कि कब अर्थव्यवस्था को सहारा देना है और कब महंगाई रोकने के लिए मांग धीमी करनी है। इनके शोध से विकसित आर्थिक मॉडल दुनिया के केंद्रीय बैंक और वित्त मंत्रालय पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं। अहम योगदान यह है कि नीति बनाते समय केवल महंगाई, उत्पादन और खपत के पुराने संबंधों पर निर्भर रहने के बजाय लोगों और कंपनियों के व्यवहार को भी समझा जाए। इससे आर्थिक झटकों का असर और नीतिगत उपायों के संभावित परिणाम आंकने में मदद मिलती है।

रॉबर्ट हॉल का बड़ा आर्थिक सिद्धांतः आज की खरीद के पीछे छिपा होता है कल की कमाई का पक्का भरोसा



हॉल का काम परिवारों की मांग और खर्च पर केंद्रित रहा।

भविष्य की उम्मीदें: खरीदारी का फैसला केवल मौजूदा आय से नहीं बनता; भविष्य की आय को लेकर अपेक्षाएं भी मायने रखती हैं। नई जानकारी मिलने पर ये अपेक्षाएं बदल सकती हैं।

उदाहरण से समझें: किसी परिवार को आगे कमाई कमजोर पड़ने की आशंका हो तो वह आज पैसा होने पर भी बड़ी खरीद टाल सकता है।

नीतिगत सीखः लोगों की जेब में रकम बढ़ाने का असर समझते समय उनके भविष्य के भरोसे को भी देखना होगा।

• परिवारों के खर्च में अचानक बदलाव पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। पुरस्कार समिति के अध्यक्ष जॉन हैस्लर के मुताबिक, हॉल और वुडफोर्ड के काम से ऐसे झटकों और ऊर्जा संकट से निपटने की तैयारी बेहतर हुई है। इनके शोध से सरकारों और केंद्रीय बैंकों को उतार-चढ़ाव घटाने वाली खर्च और ब्याज संबंधी नीतियां बनाने में मदद मिलती है।

वुडफोर्ड ने समझायाा • कंपनियों के कीमत तय करने के व्यवहार से तय होती है बाजार में महंगाई की असली तस्वीर



वुडफोर्ड ने कंपनियों के कीमतें तय करने के व्यवहार को आर्थिक मॉडल में जोड़ा। उनकी 2003 की पुस्तक में परिवारों और कंपनियों के निर्णयों पर आधारित व्यापक ढांचा सामने आया। इससे ब्याज दरों, मांग और महंगाई के बीच संबंध समझने में मदद मिली। दोनों का काम आधुनिक 'न्यू कीन्सियन' मॉडलों का आधार बना। आम परिवार तक कैसे पहुंच सकता है फायदा?

घर का बजटः महंगाई लंबे समय तक बेकाबू न रहे, इसके लिए उचित समय पर नीति बनाने में मदद। कम बचत वाले परिवारों पर आर्थिक झटकों की चोट ज्यादा पड़ती है।

रोजगार- कारोबारः मंदी गहरी होने पर मांग को सहारा देने वाले उपाय तय करने का बेहतर आधार। उद्देश्य कमजोर वृद्धि, ऊंची बेरोजगारी का दौर लंबा होने से रोकना है।

कर्ज और निवेशः ब्याज दरों में बदलाव का खपत और कारोबार पर संभावित असर समझने में मदद। इसका अर्थ हर परिस्थिति में सस्ता कर्ज देना नहीं है।

अमेरिकी विरोधाभास

विश्व राजनय में विडंबना या विरोधाभास की पराकाष्ठा बेहद दुखद और शर्मनाक है। अमेरिका ने रूस के साथ डीजल आयात के लिए समझौता किया है। वह रूस से पहले ही यूरेनियम और उर्वरक आयात करता रहा है। स्वयं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार देर रात घोषणा की है कि अमेरिका चरणबद्ध तरीके से रूस से 48 लाख टन डीजल इंधन खरीदेगा, इसमें से तीन लाख टन की तत्काल आपूर्ति होगी। अमेरिका ने अपने लोगों के हित में रूस से डीजल आयात करने का फैसला लिया है। बेशक, यह हक अमेरिका को है, लेकिन गौर कीजिए, अमेरिका यही हक भारत या चीन जैसे देशों को नहीं देना चाहता। बीते महीने ही ट्रंप प्रशासन ने रूस से तेल के निर्यात को रोकने के लिए बाकायदा कानूनी आदेश पारित किया है। रूस से तेल आयात करने वाले किसी भी देश पर अमेरिका 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने का इरादा रखता है, पर ऐसा कोई संकल्प उसने स्वयं के लिए नहीं लिया है। अमेरिकी नीतियों के इस विरोधाभास से यूक्रेन को मानो झटका लगा है। हम भूले नहीं हैं, बीते दिनों भारत और चीन पर 100 प्रतिशत टैरिफ से सर्वाधिक खुशी यूक्रेन को हुई थी, पर यह खुशी जिस देश ने दी, उसी ने छीन भी ली।

पल में तोला पल में माशा मुहावरे को अपने व्यवहार से लगातार साबित कर रहे डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन व यूरोप के खिलाफ युद्ध में रूस का और भी दृढ़ता से साथ देते दिखने लगे हैं। खुद अमेरिका में ट्रंप के ऐसे व्यवहार की आलोचना हो रही है।

रूस से तेल लेने वाले किसी भी देश पर अमेरिका 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने का इरादा रखता है, पर ऐसा कोई संकल्प उसने स्वयं के लिए नहीं लिया है।

राजनयिक ईमानदारी को ताक पर रखकर अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने रूस पर लगे कुछ प्रतिबंध 7 अप्रैल तक हटा दिए हैं, ताकि रूस डीजल का निर्यात कर सके। ट्रंप बहुत खुश हैं कि उनके इस कदम से डीजल की कीमतों में गिरावट आएगी। माना यह भी जा रहा है कि इससे तीन हफ्ते बाद होने वाले मध्यावधि चुनावों में उनकी रिपब्लिकन पार्टी को मदद मिलेगी। दूसरी तरफ, खुद अमेरिका में यह बताया जा रहा है कि इस ताजा समझौते से रूस के खूनी युद्ध को वित्तीय मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, रूसी तेल शोधक कारखानों के प्रति भी अमेरिकी प्रेम इस तरह उमड़ा है कि अमेरिका ने यूक्रेन के हमले रोकने की धमकी तक दे डाली है। यहां तक कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को हटाने की चर्चा हो रही है और युद्ध-विराम न होने का ठीकरा यूक्रेन के सिर फोड़ा जा रहा है। वैसे, सितंबर महीने में ही ट्रंप ने डीजल की कमी के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया था। साफ है, ट्रंप स्वार्थ में किसी हद तक जा सकते हैं।

दुनिया को उलझाने और घातक होने अमेरिकी रुख पर अब गंभीर चर्चा होनी चाहिए। ध्यान रहे, यूक्रेन वास्तव में अमेरिका या नाटो के उकसाने पर ही युद्ध लड़ रहा है। आज ट्रंप यूक्रेन को अकेला छोड़ते दिख रहे हैं। ठीक इसी तरह सऊदी अरब भी अकेला पड़ रहा है। सऊदी अरब हूती विद्रोहियों के निशाने पर है, लगातार हवाई हमले झेल रहा है, पर अमेरिका बचाव में सामने आने को तैयार नहीं है। अमेरिका ने ईरान में युद्ध शुरू कर पूरी दुनिया को भंवर में फंसा रखा है। अमेरिका अपने मित्र देशों को लगातार निराश और परेशान कर रहा है। ठीक यही हाल भारत के साथ है, अमेरिका और उसकी आईटी कंपनियों को मजबूती देने में भारतीय कंपनियों व इंजीनियरों का बड़ा योगदान है, पर ट्रंप की बेरुखी दोनों देशों के संबंधों को खराब करती चली जा रही है। अमेरिकी उद्यमी भारत में खुली छूट चाहते हैं, पर खुद अपने यहां ऐसी छूट देने के पक्षधर नहीं हैं। सोचकर देखिए, विश्व का महाशक्ति देश ही अगर तर्क और तथ्य से नाता तोड़ लेगा, तो दुनिया में क्या होगा ?

सीजेपी की फसल काट रहा विपक्ष



यहां स्कैन करें

नीरजा चौधरी | वरिष्ठ पत्रकार

कोई दोराय नहीं कि लोगों की सोच बदल रही है और सियासी हालात करवट ले रहे हैं, लेकिन इसे भुनाने के लिए विपक्ष को सांगठनिक रूप से मजबूत बनना होगा।



राजनीतिक प्रतिक्रिया को जिस तरह कोई 'उत्प्रेरक' गति दे देता है, ठीक वही काम मौजूदा राजनीति में कांकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने किया है। उसने सियासत में एक नई ऊर्जा भर दी है, जिसका लाभ अब विपक्ष को मिल रहा है।

यह सब अजीबो-गरीब तरीके से हुआ। प्रधान न्यायाधीश ने 'कांकरोच' कहा, अगले दिन अभिजीत दीपके ने इस नाम से एक संगठन बना दिया- कांकरोच जनता पार्टी। छह दिन में ही इसके दो करोड़ 'फॉलोअर्स' हो गए। फिर वह भारत आए, जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ। सख्ती से उससे निपटा गया, जिससे अन्य लोग भी जुड़े। इससे विपक्ष को मौका मिला और वह भी मैदान में उतर गया। पहले नीट का मामला उठा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद माहौल कुछ शांत हुआ, पर 'एसआईआर' को लेकर दो चुनाव आयुक्तों द्वारा दस महीने में 14 बार आपत्तियां दर्ज करने की खबर आगई। चुनाव आयोग द्वारा इसका लिखित खंडन न किए जाने से विपक्ष पूरे दम-खम के साथ मैदान में आ गया। राहुल गांधी एसआईआर के खिलाफ पहले से ही मुखर थे। इस खोजी खबर ने उनके मुद्दे को धार दे दी।

अभी सवाल केवल चुनाव आयोग पर नहीं है, या फिर सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त के रिश्ते पर भी नहीं, बल्कि मुद्दा लोगों के वोट का है। लोगों के मन में अब यह धारणा पनपने लगी है कि मतदान का उनका सांविधानिक अधिकार उनसे छीना जा रहा है। उनको डर है कि कहीं इससे उनकी नागरिकता ही न खत्म हो जाए, या फिर उनको मिल रही जन-कल्याणकारी सुविधाएं न छीन ली जाएं। यह गरीब व वंचित तबकों के लिए खास तौर पर अहम बन गया है, क्योंकि इस तरह की योजनाएं उनके जीवन से जुड़ी होती हैं।

राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर इन दिनों हम जो कुछ देख रहे हैं, वह इस मामले में बातचीत के बजाय सख्ती के जरिये निपटने का परिणाम है। हमारा यह ऐतिहासिक अनुभव रहा है कि सरकारें जितना सख्त रुख अपनाती हैं, जन-प्रतिक्रिया उतनी ही उग्र होती है। खासकर छात्रों-नौजवानों, महिलाओं और बुजुर्गों के साथ होने वाली सख्ती समाज बर्दाश्त नहीं करता।

अब सवाल यह है कि विपक्ष इससे कितना फायदा उठा पाएगा ? कांकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का लाभ विपक्ष को मिला है और विपक्षी दलों में भी सबसे अधिक फायदे में कांग्रेस रही है, क्योंकि वह 'इंडिया' ब्लॉक का सबसे बड़ा घटक है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि उसके नेता राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उठाते आ रहे हैं। हालांकि, वह इसे वोट में बदल पाएंगे या नहीं, फिलहाल कहना मुश्किल है। दरअसल, जब तक आंदोलन वोट में नहीं बदलते, इसे हवा हवाई ही माना जाता है। बेशक बड़ी-बड़ी रैलियां की जाएं, 'छात्रों की गूंज' हो, लेकिन यदि ईवीएम में लोग विपक्षी नेताओं के नाम के आगे बटन नहीं दबाएंगे, उनको खाली हाथ ही माना जाएगा।

चुनावी सफलता के लिए दो चीजें अहमियत रखती हैं- संगठन और विपक्षी एकजुटता। संगठन विपक्ष को खुद खड़ा करना होगा। वह दौर चला गया, जब सत्ता पक्ष के खिलाफ हवा बनते ही एकतरफा उसके खिलाफ वोट पड़ जाते थे। अब भी यह स्थिति बन सकती है, पर तब, जबकि सरकार के खिलाफ लोगों में गहरा आक्रोश हो। फिलहाल ऐसा नहीं दिख रहा। बेशक, लोगों की सोच बदल रही है और सरकार के खिलाफ असंतोष भी दिख रहा है, लेकिन इसे भुनाने के लिए विपक्ष को सांगठनिक रूप से मजबूत बनना होगा।

इसी तरह, विपक्ष की एकता पर अभी भरोसा नहीं जम पा रहा। असल में, कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि इस दल को थोड़ी-सी भी सफलता मिलती है, तो वह 'बड़े भाई' की भूमिका ओढ़ लेता है। क्षेत्रीय पार्टियों के खिलाफ उसकी यह सोच नुकसानदेह हो सकती है। कई राज्यों में उसके पास क्षेत्रीय दलों की तरह चुनावी तंत्र नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में ही समाजवादी पार्टी के पास जैसी चुनावी व्यवस्था है, वैसी कांग्रेस के पास कहां है ? ऐसे में, उसे सबको साथ लेकर चलना होगा। ऐसा करके ही वह भाजपा के चुनावी प्रबंधन से पार पा सकेगी।

हालांकि, इस पूरे आंदोलन की एक बड़ी उपलब्धि राहुल गांधी की छवि में आया बड़ा सुधार है। वह अब खुलकर बोल रहे हैं और साहस भी दिखा रहे हैं। विपक्ष में आज वही एकमात्र नेता हैं, जिन पर सर्वसम्मति बन सकती है। लोग उनको भी बारीकी से तौल रहे हैं। हालांकि, इन सबके अलावा एक और चीज है, जो उन्होंने कांग्रेस के लिए की है, वह है- इसे सड़कों पर लड़ने वाली पार्टी बनाना। पहले इस 'ग्रैंड ओल्ड पार्टी' को 'ड्राइंग रूम' की पार्टी कहा जाता था, जो जोड़-तोड़ से सत्ता चलाने में माहिर मानी जाती थी। अब आलम यह है कि राहुल, प्रियंका जैसे नेता सड़कों पर लेटे दिखते हैं, उनको हिरासत में भी लिया जाता है, तो बाहर आकर वे फिर मैदान में उतर जाते हैं। पसीने से तरबतर उनकी तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं।

इस सूरते-हाल में सत्ता पक्ष के पास बहुत कम रास्ता बचा है। अगर वह इस मुद्दे को कानून-व्यवस्था के जरिये ही सुलझाने का प्रयास करती रहेगी, तो उसे नुकसान होता रहेगा। खास तौर से बच्चों और छात्रों के खिलाफ होने वाली कार्रवाई लोगों को नाराज कर रही है। फिर, गौरतलब यह भी है कि 18-19 फीसदी मतदाता ही भाजपा के 'कोर वोटर' हैं। ऐसे में, वह यदि 2024 के आम चुनाव में 37 फीसदी मत पाने में सफल रही, तो इसकी वजह ये मतदाता हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आकर्षित रहे हैं। यह आंदोलन ऐसे मतदाताओं को विपक्ष की ओर मोड़ सकता है।

नौजवानों के अलावा मध्यवर्ग भी सत्ता पक्ष पर सवाल उठा रहा है। महंगाई, रोजगार जैसे मुद्दे उसे लगातार मथ रहे हैं। हालांकि, भाजपा में हालात संभालने की जबर्दस्त क्षमता है और माना यही जा रहा है कि वह कोई-न-कोई रास्ता जरूर निकाल लेगी।

जाहिर है, यह रास्ता संवाद से ही निकलेगा। नौजवानों की नाराजगी उसे दूर करनी ही होगी। इस तबके में अपने भविष्य के लेकर कई तरह की आशंकाएं पनप गई हैं। मौजूदा आंदोलन इसी नाराजगी का प्रतीक है। ऐसे में, भारतीय जनता पार्टी को इन लोगों तक सिर्फ पहुंचना ही नहीं होगा, बल्कि उनके भरोसे को भी जीतना होगा। अन्यथा, विपक्ष का जो रुख हम इन दिनों दिल्ली की सड़कों पर देख रहे हैं, वह आने वाले दिनों में देश के हर कोने में दिख सकता है।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

हिन्दुस्तान | 75 साल पहले | 13 अक्तूबर, 1951

अम्बेडकर का त्यागपत्र

भारत सरकार के कानून मंत्री डा. अम्बेडकर ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। समाचारपत्रों में उनके त्यागपत्र की पहले से चर्चा थी और यही अनुमान किया जा रहा था कि मुख्यत: स्वास्थ्य के कारण ही वह मंत्री-पद से अलग होने जा रहे हैं। इसलिए उनका अपने त्यागपत्र के कारणों पर प्रकाश डालने वाला लम्बा-चौड़ा वक्तव्य लोगों के सामने आया, तो उनके लिए यह आश्चर्य का कारण बन गया है। प्रधानमंत्री नेहरूजी ने यह स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी कि डा. अम्बेडकर चार वर्ष तक साथ काम कर चुकने के बाद इस प्रकार आरोपों से भरा हुआ वक्तव्य देंगे। प्रधानमंत्री ने संसद के सामने उनके और डा. अम्बेडकर के बीच हुआ जो पत्र-व्यवहार प्रकट किया है, उसमें इस आरोपों का कहीं जिक्र तो दूर रहा, संकेत तक नहीं है। इस पत्र व्यवहार से प्रकट होता है कि डा. अम्बेडकर स्वास्थ्य के आधार पर मंत्री पद से अलग होना चाहते थे।

अब डा. अम्बेडकर के वक्तव्य से प्रकट हुआ है कि उन्हें लम्बे समय से शिकायत चली आ रही थी। उन्हें शिकायत थी कि मंत्रिमंडल में उन्हें अधिक जिम्मेदारी का काम नहीं सौंपा गया। परिगणित और पिछड़ी जातियों के साथ भेदभावमूलक व्यवहार पुराने जमाने की भांति ही अब भी जारी है और उनकी स्थिति सुधरने के बजाय और खराब हो गई है। डा. अम्बेडकर भारत की विदेश नीति से भी सहमत नहीं थे। उन्हें यह भी शिकायत है कि सरकारी निर्णय विशेष कमेटियों में पहले ही कर लिये जाते थे और मंत्रिमंडल का काम केवल उन पर मुहर लगाना मात्र रहता था। डा. अम्बेडकर के कथनानुसार उन्हें सबसे अधिक निराशा इस बात पर हुई है कि संसद में हिन्दू कोड विधेयक स्वीकृत नहीं हो सका। निश्चय ही डा. अम्बेडकर की शिकायतों की सूची काफी लम्बी-चौड़ी है, किन्तु हम यह नहीं समझ पाये कि जब उन्हें प्रधानमंत्री से इतनी गम्भीर शिकायतें थीं, तो उन्होंने प्रधानमंत्री को उनसे अब तक अवगत क्यों नहीं किया और क्यों उनको अपने दिल के किसी अन्धेरे कोने में पिछले चार वर्षों तक छिपाये रखा ? उन्होंने इस लम्बे अर्से में कभी यह प्रकट नहीं होने दिया कि सरकार की किसी नीति से उन्हें मौलिक मतभेद है। यदि उन्हें मौलिक मतभेद था, तो इमानदारी का तकाजा था कि इतने दिन तक वह मौन नहीं बैठते और बहुत पहले ही सरकार से अपना संबंध विच्छेद कर लेते।

तमिलनाडु उप-चुनावों में मिली जीत विजय के लिए संदेश



दक्षिण एक्सप्रेस

यहां स्कैन करें

एस श्रीनिवासन | वरिष्ठ पत्रकार

तमिलनाडु में हाल ही में संपन्न हुए दो नहीं विधानसभा उप-चुनावों में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की टीवीके पार्टी को जीत तो मिल गई है, लेकिन इसके लिए पार्टी को जी-तोड़ मशक्कत करनी पड़ी। ये सीटें- पश्चिमी तमिलनाडु की धारापुरम और उत्तर की मथुरंथगम अन्नादुमुक का गढ़ रही हैं, जिन्हें मई के विधानसभा चुनावों में उसकी महिला उम्मीदवारों ने जीता था। दोनों सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं और नतीजों के तुरंत बाद विधायकों ने टीवीके में शामिल होने के लिए विधानसभा और पार्टी से इस्तीफा दे दिया था।

विजय के लिए यह जीत आसान नहीं थी। जब टीवीके की दोनों महिला उम्मीदवार वोट मांगने के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्रों में गईं, तो उन्हें मतदाताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। फिर टीवीके ने बिना किसी मुफ्त सुविधा के उप-चुनाव लड़ने का वादा किया था। दोनों महिलाओं को खूब खरी-खोटी सुनाई गई, यहां तक कि अपशब्द भी कहे गए। विजय ने दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार की जिम्मेदारी एक-एक कैबिनेट मंत्री को दी थी। वे लगभग एक महीने तक वहां डटे रहे और विजय ने खुद जीत सुनिश्चित करने के लिए चार दिनों तक लगातार चुनाव प्रचार किया। मतदाताओं का दिल जीतने के लिए उन्हें खेतों में ट्रैक्टर चलाना पड़ा, नवजात शिशुओं को गोद में लेना पड़ा, सरकारी बस में यात्रा टिकट बांटने पड़े और कई अन्य काम करने पड़े।

दोनों विधानसभा सीटों पर जीत के बावजूद उन्हें एहसास हो गया होगा कि जनादेश कितना अस्थिर और अनिश्चित हो सकता है!

बहरहाल, उन्हें एहसास जरूर हो गया होगा कि जनादेश कितना अस्थिर और अनिश्चित हो सकता है। विधानसभा में बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत है, जबकि विजय की पार्टी के पास अभी 109 सीटें हैं। उन्होंने सहयोगी कांग्रेस पार्टी और केंद्र में भाजपा सरकार के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। विजय ने गत 10 अक्तूबर को राहुल गांधी के लिए लंच का आयोजन किया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगले दिन वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मेट्रो की पहली सवारी करने वाले हैं। हालांकि, उन्होंने एसआईआर में गड़बड़ियों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कांग्रेस के विरोध-प्रदर्शन का समर्थन किया है, लेकिन उनके प्रशासन ने कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर कोई नरमी नहीं बरती और जानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे 100 से ज्यादा वामपंथी छात्रों और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया।

इन उप-चुनावों में अन्नादुमुक पार्टी दोनों जगह तीसरे स्थान पर रही। विजय के लिए यह एक सुखद सफलता है, क्योंकि लंबे समय में वह धीरे-धीरे अन्नादुमुक के समर्थन आधार पर कब्जा करना चाहेंगे। उधर डार के बावजूद, द्रमुक को उम्मीद की एक किरण दिखी है, क्योंकि यह पार्टी दोनों जगहों पर दूसरे नंबर पर रही। पार्टी नेताओं को लगा है कि यह इस बात का प्रमाण है कि वे टीवीके सरकार के मुख्य प्रतिद्वंद्वी हैं। पार्टी नेता एम के स्टालिन ने टीवीके पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया और इस जीत को एक अस्थायी घटना बताया। मन ही मन, उन्हें भारतीय जनता पार्टी से दूर रहने के अपने फैसले से संतुष्टि भी मिली होगी।

इन उप-चुनावों में भाजपा की भूमिका नगण्य रही। वैसे भी, पार्टी केंद्र की मुश्किलों से निपटने में व्यस्त है और कांग्रेस के नेतृत्व वाले 'इंडिया' ब्लॉक के समर्थकों और नवगठित सीजेपी को कोई नई राजनीतिक जगह हासिल करने से रोकने में जुटी है। आखिरकार, विजय की पार्टी जीत गई है, लेकिन विधानसभा पर पूरी तरह से नियंत्रण पाने के लिए उसे अभी लंबा सफर तय करना है। अन्नादुमुक के दो विधायकों के अलावा पांच अन्य विधायक, जिनमें एडप्पाडी की सरकार के पूर्व वरिष्ठ मंत्री शामिल हैं, भी कतार में हैं। उन्होंने भी अन्नादुमुक के टिकट पर जीतने के बाद अपनी-अपनी विधानसभा सीटों से इस्तीफा दे दिया है और टीवीके में शामिल हो गए हैं। उप-चुनाव की जीत उनके मनोबल को बढ़ाने वाली है।

इस जीत का इस्तेमाल करते हुए, अभिनेता विजय को अपनी सरकार को स्थिर करने के लिए कुछ राजनीतिक और प्रशासनिक कदम उठाने होंगे। हालांकि, उनकी सरकार को तत्काल कोई खतरा नहीं है, फिर भी वह मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं, क्योंकि सहयोगी दल उनके शासन की आलोचना करके सरकार को अलग-अलग दिशाओं में खींच रहे हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं।)

मनसा वाचा कर्मणा

इंसानियत की जीत

फ्लाईदुबई की घटना के विवरण देख *शोले* का वह मशहूर सवाल याद आया, 'कितने आदमी थे ?' मुख्य किरदार हमारे जांबाज भारतीय कैप्टन का था, जिन्होंने अपनी जान से ज्यादा दूसरों की फिक्र की। भारत में सिर्फ उसी के चर्चे हो रहे हैं, लेकिन चूंकि इज़रायली यात्रियों से भरा हुआ विमान था, इसलिए वहां के पत्रकार भी इस घटना का अपने नजरिये से विश्लेषण कर रहे हैं।

भारतीय पायलट स्मित मच्छार जिस अजीबो-गरीब तरीके से बचे, उसकी गहराई में जाएं, तो लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति इन लोगों में काम कर रही थी। इजरायल के *हार्वर्ड* पत्रिका में डैनपेरी नामक एक यहूदी पत्रकार ने इजरायली यात्रियों के योगदान के बारे में लिखा है कि यह चमत्कार से कम नहीं है। इजरायली यात्रियों ने हमलावर को काबू करने में मदद की, जबकि यात्री के तौर पर यात्रा कर रहे पायलटों ने विमान को सऊदी अरब में सुरक्षित उतारने में सहायता की। डॉक्टर कैप्टन स्मित का बहता हुआ खून रोकने की कोशिश करते रहे। उनका जिम्मा यह भी था कि कैप्टन बेहोशी में न चले जाएं। इसलिए डॉक्टर उनसे कहते रहे, 'सोना मत, हमें आपकी जरूरत है, आपने हमारी जान बचाई है।'

उस समय न किसी का धर्म आड़े आया, न देश और न जाति। ये सब तो फुरसत की बातें हैं। मौत सामने हो, तो एक ही जाति होती है, इंसानियत। एक ऐसी उड़ान, जो बड़ी दुर्घटना बन सकती थी, अविश्वसनीय कहानी बन गई है, जिसमें आम लोग हीरो बनकर उभरे।

इस कहानी की सादगी में अद्भुत ताजगी है। बिना किसी नेता के, सामान्य यात्री अपने आप बचाव-कार्य में जुट गए। उनमें कोई प्रशिक्षित था, तो सिर्फ हमलावर, जो पूरी तैयारी से आया था, लेकिन वही असफल हुआ। इस घटनाक्रम को देखने वालों ने ऐसे हालात में एक राष्ट्रीय खूबी उभरते हुए देखी : सूझ-बूझ वाले, साहसी, बेबाक और मुश्किलों से निपटने के लिए असाधारण रूप से तैयार इजरायली। उनके पास चंद सेकंड थे, जब वे विमान को बचा सकते थे, साथ ही हमलावर को रोक सकते थे और भारतीय पायलट की जान बचा सकते थे।

इजरायल के एक पूर्व प्रवक्ता एलन लेवी ने इसका मजेदार पहलू बयान किया है : 'यह इजरायल में ही हो सकता है कि इजरायलियों से भरे विमान में दो अतिरिक्त पायलट, कम से कम एक डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक, वकील और हीरे का व्यापारी मौजूद होगा।'

उस विमान में किसी को भी अपनी सुरक्षा का ख्याल नहीं था, हर कोई दूसरों के बारे में सोच रहा था। यह कैसे हुआ ? एकता की ताकत। वहां आदमी बहुत थे, लेकिन आदमियत एक थी।

वेन ने केवल मौजूद थे, वरन सारे के सारे फौरन अपने-अपने कौशल का उपयोग करने लगे। सबसे बड़ी बात, किसी को भी अपनी सुरक्षा का ख्याल नहीं था, हर कोई दूसरों के बारे में सोच रहा था। यह कैसे हुआ ? एकता की ताकत। वहां आदमी तो बहुत थे, लेकिन आदमियत एक थी, जिसने विनाश से बचा लिया।

अमृत साधना

राजनाथ सिंह | रक्षा मंत्री



महान व्यक्तित्व वटवृक्ष की तरह होते हैं, जो सबको आश्रय देते हैं। वे समाज के लिए जीते हैं। कोई उनकी उदारता का लाभ उठाए या उनकी जड़ों को कमजोर करने का प्रयास करे, फिर भी वे अपने मूल स्वभाव और उदारता को नहीं छोड़ते।

लोकतंत्र में सबको विरोध का अधिकार

लोकतंत्र केवल चुनाव कराने, सरकार बनाने और शासन करने की व्यवस्था का नाम नहीं है। इसकी वास्तविक शक्ति नागरिकों को अपनी बात कहने, असहमति जताने और अपनी सरकार से प्रश्न पूछने की आजादी में निहित है। जिस व्यवस्था में नागरिक अपनी शिकायतें खुलकर सामने रख सकें, शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर सकें और अपनी मांगों के समर्थन में आवाज उठा सकें, वही व्यवस्था लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करती है। हालांकि, जब विरोध-प्रदर्शन और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच टकराव की स्थिति पैदा होती है, तब नागरिक अधिकारों की रक्षा व कानून का पालन सुनिश्चित करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर हो रहे विरोध-प्रदर्शनों के बीच सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

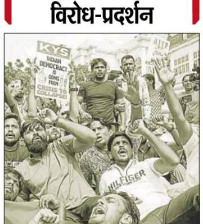
निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित विवाद का एक व्यापक पक्ष जनता का विश्वास है। मतदाता सूची का पुनरीक्षण आवश्यक हो सकता है, क्योंकि समय के साथ मृत्यु, स्थान परिवर्तन और अन्य कारणों से अभिलेखों में बदलाव करना पड़ता है, लेकिन इस प्रक्रिया में किसी पात्र नागरिक का नाम गलत तरीके से हटाना उसके मताधिकार को प्रभावित कर सकता है। इसलिए सूची में संशोधन करते समय पारदर्शिता, स्पष्ट मानदंड, उचित सूचना और शिकायतों के निवारण की प्रभावी व्यवस्था जरूरी है। राजनीतिक दलों और नागरिकों की आपत्तियों का समाधान प्रमाणों के आधार पर होना चाहिए। विरोध-प्रदर्शन भी लोकतंत्र में संवाद का माध्यम है। नागरिक जब किसी निर्णय से असहमत होते हैं, तब शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग रखना उनका सांविधानिक अधिकार है। शासन-प्रशासन को प्रदर्शनकारियों के साथ संवाद स्थापित करना चाहिए, ताकि तनाव कम किया जा सके और सार्वजनिक सेवाएं बाधित न हों। दोनों पक्षों की जिम्मेदारी से ही मौजूदा समस्या का समाधान संभव है।

आज आवश्यकता इस बात की भी है कि लोकतांत्रिक असहमति को सिर्फ कानून-व्यवस्था की समस्या के रूप में न देखा जाए। असहमति तो लोकतंत्र को जीवंत बनाती है। किसी लोकतंत्र की वास्तविक मजबूती तब दिखाई देती है, जब उसके नागरिक बिना किसी भय या दबाव के अपनी बात रख सकें, प्रशासन निष्पक्षता से अपने दायित्व निभाए और न्यायपालिका आवश्यकता पड़ने पर सांविधानिक सीमाओं की रक्षा करे। विरोध की आवाज सुनना, असहमति का सम्मान करना और कानून का समान रूप से पालन सुनिश्चित करना ही एक उन्नतशील लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहचान है।

महेंद्र तिवारी, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

विरोध-प्रदर्शन



प्रदर्शनों के नाम पर बंद हो हुड़दंगबाजी

पितृपक्ष समाप्त हो गया। शक्ति की देवी मां दुर्गा की आराधना शुरू हो गई है। लोग खरीदारी करने के लिए बाजार की ओर निकल पड़े हैं, जिनसे बाजारों में रौनक लौट आई है। छोटे-बड़े-मझले व्यापार आंशे हो गए हैं। देश का प्रमुख उत्सव दीपावली भी आने वाला है। इन त्योहारों के लिए हर वर्ग को जरूरत की वस्तुएं खरीदने बाजार जाना पड़ रहा है। ऐसे में, देश को राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ राजनीतिक/अराजनीतिक दल बेवजह प्रदर्शन/आंदोलन में झोंक रहे हैं, जिसका खासा नुकसान हो रहा है।

माना कि अपने अधिकारों के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रदर्शन या आंदोलन का सांविधानिक अधिकार हर व्यक्ति, संस्था या राजनीतिक दल को है, लेकिन यह सब कुछ जनभावनाओं को देखते हुए ही जरूरी हो, तो अमल में लाना उचित है। मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण, यानी एसआईआर में गड़बड़ियों के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त का इस्तीफा मांगना और इसके लिए प्रदर्शन करके जगह-जगह बाधाएं उत्पन्न करना, लोगों की दिनचर्या प्रभावित करना, रेल-मेट्रो-सड़क यातायात में रुकावटें पैदा करना, आम लोगों को परेशान करना, उनके महत्वपूर्ण समय को बर्बाद करना कितना उचित है ? सारी सुरक्षा व्यवस्था, जो इन दिनों त्योहारों में बाधाएं पहुंचाने वालों से आम महिलाओं या बच्चों की सुरक्षा के लिए होनी चाहिए, उनको विरोध-प्रदर्शन या आंदोलन में लगवा देना कितना उचित है ? क्या विपक्षी नेताओं या गैर राजनीतिज्ञों को इसकी जरा भी समझ नहीं है कि इन सबसे देर रात तक चलने वाले त्योहारी उत्सव के रंग में भंग पड़ने की आशंकाएं बढ़ गई हैं ? इतने संवेदनशील मामलों में आखिर इनकी बुद्धिमत्ता कहां चली गई ? क्या एजेंडा निगल गया ? मुख्य चुनाव आयुक्त का अगर इस्तीफा नहीं होता है, तो कौन सा पहाड़ देश पर टूट जाएगा ? क्या लाल बहादुर शास्त्री ने जब इस्तीफा दिया था, तो उसके बाद रेल दुर्घटनाएं बंद हो गई थीं ? समस्याओं के हल के लिए आंदोलन उचित है, लेकिन हुड़दंग मचाने के लिए इसे कैसे उचित बताया जा सकता है ?

अच्छा तो यही होगा कि बातचीत के जरिये समाधान खोजने की पहल की जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त का इस्तीफा आम लोगों की परेशानी से बढ़कर नहीं है। हमारे राजनेताओं, बुद्धिजीवियों और प्रदर्शनकारियों को इस बारे में सोचना चाहिए। अन्यथा, अदालत स्वतः संज्ञान ले और आम लोगों के हित में फैसले सुनाए। तभी स्वार्थी आंदोलनकारियों को समझ में आएगा कि आम लोगों की परेशानी क्या होती है। उनको व्यावहारिक सोच का प्रदर्शन करना चाहिए।

शकुंतला नेनावा, टिप्पणीकार

शक्ति के सदुपयोग से आगे बढ़ें

शक्ति प्रकृति के कण-कण में मौजूद है। विवेक भी एक शक्ति है। विद्या भी एक शक्ति है। अर्थ का ज्ञान-विज्ञान भी एक शक्ति है। समाज, परिवार और देश को एक सूत्र में बांधना भी एक शक्ति है। शक्ति के बिना इंसान का सांसारिक जीवन भी अधूरा है, इसलिए इस नवरात्र पर हम शक्ति के सही अर्थ को समझें।



अध्यात्म
आनंदमूर्ति गुरुमां

नौ दिनों की आराधना और अनुष्ठान-विधि को 'नवरात्र' के नाम से जाना जाता है। यह सर्वमान्य है कि जिन्हें दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी, बगलामुखी आदि नामों से जाना जाता है, वह एक ही शक्ति के बदले हुए स्वरूप हैं। सारे ब्रह्मांड में व्याप्त यह चैतन्य शक्ति हर मनुष्य के भीतर कुंडलिनी के रूप में मौजूद है।

शव के शिव हो जाने की यात्रा

कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र में सुप्त है। मूलाधार आदि सात चक्र मनुष्य के स्थूल शरीर में नहीं, अपितु सूक्ष्म शरीर में स्थित हैं। मूलाधार चक्र में उलटे त्रिकोण के रक्त वर्ण स्वरूप में स्थित यह आदिशक्ति कुंडलिनी जब तक सुप्त अवस्था में रहती है, तब तक मनुष्य का जीवन उन्नत नहीं हो पाता। योग विशेषकर राजयोग और चक्रानुसंधान-योग इस सुप्त शक्ति को जागृत करने के लिए विभिन्न प्रकार की साधनाओं को इंगित करते हैं।

तंत्र के प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शक्ति हर मानव शरीर में कुंडलिनी के रूप से मूलाधार चक्र में विराजमान है। प्रायः यह शक्ति मूलाधार में सुप्त ही रह जाती है और मनुष्य की चेतना निम्न तलों पर रहते हुए ही नष्ट हो जाती है। चूंकि शिव सातवें सहस्रार चक्र में स्थित हैं, तो जब तक इन शिव और शक्ति का मिलाप नहीं हो जाता, तब तक मनुष्य का जीवन पूर्ण रूप से उन्नत और परिपक्व नहीं हो पाता। कुंडलिनी शक्ति का जागरण मनुष्य के जीवन में एक ऐसे रूपांतरण को ले आता है, जिससे शव हो जाने वाली देह शिव रूप हो जाती है।

कण-कण में मौजूद शक्ति

शक्ति प्रकृति के कण-कण में मौजूद है। विवेक भी एक शक्ति है। विद्या भी एक शक्ति है। ललित कलाएं भी शक्ति हैं। अर्थ का ज्ञान-विज्ञान भी एक शक्ति है। भोजन को पकाना भी एक शक्ति है। किसी भी कला में कुशलता एक शक्ति है। समाज, परिवार और देश को एक सूत्र में बांधना भी एक शक्ति है। बिना शक्ति के जब ईसान का सांसारिक जीवन भी अपूर्ण है, तो आध्यात्मिक जीवन कैसे पूर्ण हो सकता है? यह बात स्मरण में रहनी चाहिए कि जब तक मनुष्य के भीतर इस पराशक्ति का जागरण नहीं होता है, तब तक मनुष्य का जीवन एक पशु की भांति आहार, निद्रा, भय और भोग का सेवन करने तथा पदार्थों का संग्रह करने में ही व्यर्थ हो जाता है। इसी शक्ति के जागरण हेतु हमारे

आजकल नवरात्र का अर्थ बहुत रूढ़िवादी हो गया है। नौ दिनों तक दुर्गा के मंदिर में पूजा करना, तामसी चीजों से परहेज, इतना भर कर लेने से नवरात्र का अनुष्ठान पूरा नहीं होता है।



ऋषियों ने नवरात्र का नौ दिवस का साधना अनुष्ठान दिया है, ताकि पहले दिन से लेकर नवमी तक उपवास और साधना का सात्विक जीवन जीने का अवसर मनुष्य को मिले।

देवी का वास्तविक स्वरूप ज्ञान

आजकल नवरात्र का अर्थ बहुत रूढ़िवादी और परंपरावादी हो गया है। नौ दिनों तक दुर्गा के मंदिर में पूजा करना, शाकाहारी रहना, तामसी चीजों से परहेज, इतना भर कर लेने से नवरात्र का अनुष्ठान पूरा नहीं होता है। योगासन, प्राणायाम, षट्कर्म, धारणा, इन चारों को आधार बनाकर विशेषतः कुंडलिनी का जागरण करना, यही है नवरात्र के अनुष्ठान का सांकेतिक रहस्य। बहुत-से लोग दुर्गा पूजा का अर्थ सिर्फ इतना ही मानते हैं कि स्थूल रूप से नवी दुर्गा की मूर्ति अथवा चित्र के सामने फल-फूल चढ़ा देना है। प्रायः समाज का बहुत बड़ा वर्ग इसी को दुर्गा पूजा मानता है। मात्र इंद्रिय सुख, शारीरिक सुख और भौतिक सुख ही अगर आपके जीवन का लक्ष्य है, तो आपने अभी दुर्गा के उस वास्तविक स्वरूप को जाना नहीं है, क्योंकि दुर्गा का वास्तविक स्वरूप है ज्ञान। जिस अंतःकरण में यह ज्ञान स्थिर हो जाता है, उसी अंतःकरण में एक दिन महासंबोधि घटित हो ही जाती है। जिस अंतःकरण में महासंबोधि घटित हो चुकी है, उस व्यक्ति के लिए फिर यह समस्त जगत उसी ऊर्जा का ही संघटित रूप है। पदार्थ और पदार्थ का सूक्ष्म रूप है ऊर्जा। हम ऊर्जा के इसी दिव्य परा-स्वरूप को शक्ति कहते हैं।

शक्ति के अनेक रूप

भारत में शक्ति के हजारों चिह्न और धारणाएं मानी जाती हैं। 'दुर्गा' के रूप में वह सभी संकटों का निवारण करती है। 'काली' के रूप में वह काल और अहंकार को मारती है। 'सरस्वती' के रूप में वह ज्ञान-विज्ञान की दात्री है। 'लक्ष्मी' के स्वरूप में वही देवी धन-संपदा और समृद्धि का वरदान देती है। 'तारा' के स्वरूप में वह जीवन में ज्ञान की दिशा दिखाती हैं और 'जगदंबा' के स्वरूप में समस्त सृष्टि की जननी और माता कहलाई जाती हैं। देवी के इन सभी स्वरूपों की उपासना में दया, क्षमा, करुणा, वीरता इत्यादि महिमापूर्ण शक्तियों का आह्वान और जागरण किया जाता है।

मेरी दृष्टि में दुर्गा के बाहरी स्वरूप भी विभिन्न हैं। हर स्त्री में दुर्गा है। सृष्टि के कण-कण में दुर्गा है। अपने भीतर और बाहर व्याप्त इस पराशक्ति के साथ एकाकार हो जाने के लिए इस साधना-अनुष्ठान की ओर अग्रसर हों। नवरात्रि के इस पर्व में हम अपने अंतर्मन में मौजूद उस पराशक्ति के साथ एकाकार होने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारी मूल प्रकृति यानी यह मन, पदार्थ और भौतिक जगत उत्पन्न हुआ है। उस मूल आद्या शक्ति, पराशक्ति की ओर अपनी अंतर्यात्रा को बढ़ाना, यही नवरात्रि के इस विशिष्ट आध्यात्मिक अनुष्ठान का लक्ष्य है।

आस्था-अनास्था

समीर उपाध्याय ज्योतिर्विद्

सूर्य का तुला में गोचर देगा मिलाजुला प्रभाव

सूर्य के अपनी नीच राशि तुला में आने पर बारह राशियों पर क्या प्रभाव होंगे?
-आदित्य गर्ग, नोएडा



सूर्य 17 अक्तूबर, 2026 को शाम 07.57 पर कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। यहां सूर्य 16 नवंबर, 2026 को शाम 07.48 तक रहेंगे। तुला को सूर्य की नीच राशि माना जाता है। सूर्य के तुला राशि में गोचर के दौरान बारह राशियों पर कैसा प्रभाव रहेगा :

मेष : पारिवारिक जीवन में संघर्ष। नए कार्य में सफलता। उच्च अधिकारियों का सहयोग। मतभेद से बचें।

वृष : विवादित मामलों में सफलता- असफलता दोनों। घर में खर्च की अधिकता। संघर्षपूर्ण प्रगति। सेहत पर ध्यान दें।

मिथुन : घर में मांगलिक कार्य। अचानक आर्थिक लाभ। नई योजना पर कार्य प्रारंभ। आमदनी के नए स्रोत की प्राप्ति।

कर्क : घरेलू सुख सामग्री एवं चल संपत्ति की खरीदारी। स्वास्थ्य एवं मरम्मत पर खर्च। कार्य स्थल में परिवर्तन।

सिंह : आर्थिक लाभ। नए संपर्क बनेंगे। स्वास्थ्य में अस्थिरता। मेहनत से कार्य एवं व्यापार में तरक्की।

कन्या : लाभ-हानि दोनों। घर में खर्च की अधिकता। मरम्मत एवं स्वास्थ्य कार्य पर खर्च। मानसिक अशांति। घर के किसी सदस्य के निवास स्थल में परिवर्तन।

तुला : स्वास्थ्य को छोड़कर अन्य मामलों में अच्छी प्रगति। बड़ा आर्थिक लाभ। तरक्की के अवसर बनेंगे।

वृश्चिक : महत्वपूर्ण कार्य में संघर्ष। अवांछित परिवर्तन। कुछ विवादित मामलों में सफलता, कुछ में निराशा। महत्वपूर्ण कार्य में अतिरिक्त प्रयास से कुछ काम बनेंगे।

धनु : शुभ समाचार। आर्थिक लाभ। रुके हुए काम बनेंगे। नए कार्य में पूंजी निवेश। स्वास्थ्य समस्या हो सकती है।

मकर : मिश्रित सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में लाभकारी परिवर्तन। निकटवर्ती लोगों से मतभेद। घर में अशांति।

कुंभ : घरेलू सुख सामग्री एवं मरम्मत पर खर्च होगा। नई जिम्मेदारी, नए कार्य में संलग्नता। पूर्वानुमान लगाने की अपेक्षा अतिरिक्त श्रम लाभप्रद रहेगा।

मीन : शुभ-अशुभ दोनों। गलत निर्णय से आर्थिक क्षति। संबंधों में तनाव। स्वास्थ्य, मरम्मत एवं नई खरीदारी पर खर्च।

सप्ताह के व्रत-त्योहार

13 अक्तूबर से 19 अक्तूबर 2026 तक

13 अक्तूबर (मंगलवार) : आश्विन शुक्ल तृतीया तिथि रात्रि 11.28 मिनट तक। जमादि उल्लावल (मु.) मास प्रारंभ।

14 अक्तूबर (बुधवार) : आश्विन शुक्ल चतुर्थी तिथि रात्रि 01.14 मिनट तक। भद्रा दोपहर 12.21 मिनट से रात्रि 01.14 मिनट तक।

15 अक्तूबर (गुरुवार) : आश्विन शुक्ल पंचमी तिथि रात्रि 03.26 मिनट तक। उपांग ललिता व्रत। ललिता पंचमी।

16 अक्तूबर (शुक्रवार) : आश्विन शुक्ल षष्ठी तिथि रात्रि 05.55 मिनट (सूर्योदय पूर्व) तक। गंडमूल विचार।

17 अक्तूबर (शनिवार) : आश्विन शुक्ल सप्तमी तिथि (दिन-रात)। कार्तिक संक्रांति। भद्रकाली अवतार। आकाश दीपदान प्रारंभ। गंडमूल प्रातः 09.47 मिनट तक।

18 अक्तूबर (रविवार) : आश्विन शुक्ल सप्तमी तिथि प्रातः 08.29 मिनट तक पश्चात अष्टमी तिथि। भद्रा प्रातः 08.29 मिनट से रात्रि 09.41 मिनट तक। ओली प्रारंभ (जैन) चतुर्थी पक्ष।

19 अक्तूबर (सोमवार) : आश्विन शुक्ल अष्टमी तिथि प्रातः 10.52 मिनट तक पश्चात नवमी तिथि। श्री दुर्गाष्टमी। महाष्टमी। सरस्वती विसर्जन श्रवण। महानवमी (व्रत, पूजा एवं होम हेतु)।

-पं. ऋषुकांत गोस्वामी

भेजें अपने सवाल

स्वर्ग-नरक की कल्पना का आधार क्या है?

पाप क्या है, पुण्य क्या है? धर्म क्या है, अधर्म क्या है? ईश्वर की आराधना कैसे करें? ऐसे सवाल अकसर हमारे मन में उठते हैं, पर इनका जवाब हमारे पास नहीं होता। मन-मस्तिष्क में आने वाले ऐसे ही सवालों के जवाब हमारे पैनल में शामिल धर्माचार्य आपको देंगे।

अपने सवाल हमें इस पते पर भेजें :
धर्मक्षेत्रे, हिन्दुस्तान, 19वां तल, द आइकॉन टॉवर, एफ सी-24 सी, फिल्म सिटी, सेक्टर-16ए, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर-201301 (उत्तर प्रदेश)

मोह-माया ही सब दुखों का मूल

चिंतन



यदि हमें भगवत चिंतन करते हुए संसार की चीजें भी अच्छी लगती हैं, तो समझना चाहिए कि अभी हम भगवत्प्रेम से कोसों दूर हैं। जब हमें संसार की बढ़िया-से-बढ़िया चीज देख कर भी घृणा हो, तभी समझना चाहिए कि अब भगवान का अनुराग हुआ। भगवद्भक्तों को सभी चीजें तुच्छ जान पड़ती हैं।

एक बार बादशाह ने सुकरात से पूछा, 'आपके लिए कुछ जवाहरात भेज दूं?' सुकरात ने कहा, 'हम जवाहरात का क्या करेंगे? वे तो पत्थर के टुकड़े हैं।' फिर बादशाह ने पूछा, 'कुछ रेशमी वस्त्र भेज दूं?' सुकरात ने कहा, 'हमें उनकी आवश्यकता नहीं, वे तो कीड़ों के थूक हैं।' यह प्रसंग बताता है कि सभी दुखों की जड़ मोह है।

मोह-ममता से ही दुख होता है, जैसे- अनेक मकान हैं। उनके नष्ट होने से तुम्हें कोई दुख नहीं होता; किंतु जो मकान आपने खरीद लिया, उसकी यदि कोई एक ईंट भी निकालता है, तो ममत्व हो जाने के कारण बहुत दुख होता है। इसलिए किसी पदार्थ में ममत्व न करके सबको ईश्वर का समझते हुए सेवक की भांति सबकी रक्षा और संभाल करो। इससे उनके संयोग-वियोग में दुख नहीं होगा, क्योंकि सब पदार्थों का बनाने वाला तो ईश्वर ही है।

यदि कोई कहे कि यह मकान मैंने बनाया है, तो उसे सोचना चाहिए कि मिट्टी और पत्थर आदि कहां से आए। रेल, मोटर आदि भले ही मनुष्य के बनाए हुए हों, किंतु लोहा न होता, तो ये कैसे बनते। इन सब पदार्थों का वास्तविक रचयिता और स्वामी तो ईश्वर ही है, इसलिए हमें इनमें ममता नहीं करनी चाहिए।

प्रतिष्ठा ने ही जीव को भगवान से दूर कर रखा है। यदि दैववेगा से प्रतिष्ठा होने लगे, तो उससे घृणा ही करनी चाहिए। सर्वदा दूसरों को ही मान देने की चेष्टा करें। जब तक प्रवृत्ति का बोझा सिर पर लदा हुआ है, इष्ट की प्राप्ति नहीं हो सकती। इष्ट तो निवृत्ति होने पर ही प्राप्त होता है।

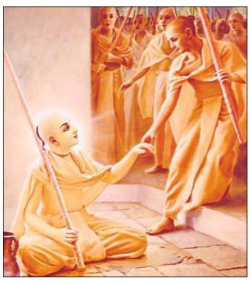
जन्म और मृत्यु का दुख एक सहस्र बिच्छुओं के काटने के समान माना गया है। मनुष्य तो एक बिच्छू के काटने से ही बेचैन हो जाता है; फिर अनेक बिच्छुओं के काटने की पीड़ा के विषय में क्या कहा जाए। यह तो अनुभव का ही विषय है। जन्म का दुख तो मृत्यु के दुख से भी बढ़कर है। यदि मनुष्य शरीर पाकर यह जन्म-मरण का दुख दूर नहीं हुआ, तो यह जन्म व्यर्थ ही रहा। इस जन्म का लाभ तो यही है कि जीव जन्म-मरण के दुख से छूट जाए।

मनुष्य मंसार के जंगल से तो छूट सकता है, परंतु शास्त्र के जंगल से उसका छूटना कठिन है। हम वैराग्य की बातें तो खूब करते हैं। दूसरों के वैराग्य को देखकर उसकी प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन बात जब स्वयं पर आती है, तो वैराग्य कहीं पीछे छूट जाता है, जबकि असली वैराग्य वही है, जो व्यक्ति स्वयं में जीता है।

-उड़िया बाबा

समस्या का एक कारण नहीं होता

विचार



कभी-कभी हम कर्म सिद्धांत का गलत अर्थ निकाल कर, हर बात का दोष कर्मों को देने लगते हैं। यह स्वयं कोशिश करने या जिम्मेदारी से बचने की प्रवृत्ति होती है। कर्म को निष्क्रिय और गतिहीन न मानकर, इसे सक्रिय समझना चाहिए। यह इस बात को दर्शाता है कि कर्म प्रक्रिया में कोई कर्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए, कोई साधारण कार्य या साधारण उद्देश्य जैसे भोजन की अपनी जरूरत को पूरा करना। इस साधारण उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। हमें भोजन तलाशना होगा, फिर उसे खाना पड़ेगा और इस बात से यह पता लगता है कि किसी छोटे-से उद्देश्य को पूरा करने के लिए भी कार्य करना पड़ता है।

ईश्वर में विश्वास करने वाले लोग कठिन परिस्थितियों को ईश्वर की रचना या उसकी योजना मानकर, उन्हें अधिक सरलता से स्वीकार कर लेते हैं। हालांकि, वह स्थिति नकारात्मक है, लेकिन ईश्वर बहुत दयालु व शक्तिशाली है, इसलिए उस परिस्थिति का अवश्य कोई कारण, कोई अर्थ होगा, जिसे वे समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस तरह का विश्वास कष्ट के समय उनकी मदद करता है।

मेरे विचार से वैज्ञानिक आमतौर पर किसी भी समस्या पर तटस्थ भाव से सोचते हैं और ज्यादा भावुक हुए बिना उसका अध्ययन करते हैं। इस तरीके से आप समस्या को यों देख सकते हैं, 'यदि समस्या को सुलझाने का कोई तरीका है, तो उसे सुलझाओ, चाहे उसके लिए आपको न्यायालय जाना पड़े!'

कठिन या जटिल स्थितियों का तटस्थ विश्लेषण बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इसी तरीके से आप जान सकते हैं कि उसके पीछे कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके बॉस ने आपके साथ ऑफिस में दुर्व्यवहार किया, तो हो सकता है कि उसके पीछे कुछ और कारण हों। हो सकता है, वह किसी और बात से परेशान हो। उनके व्यवहार का आपके साथ कोई संबंध न हो और न ही वह आपसे नाराज हों। निश्चित रूप से, आपको सामने आई परिस्थिति को झेलना पड़ेगा, लेकिन कम-से-कम इस तरीके से आपको अतिरिक्त चिंता नहीं सताएगी।

क्या इस तरह का 'वैज्ञानिक' रवैया, जिसमें व्यक्ति परिस्थिति का निष्पक्ष भाव से आकलन करता है। व्यक्ति की उन तरीकों को जानने में भी मदद कर सकता है, जिनके द्वारा वह स्वयं अपनी समस्या में योगदान देता है? और क्या ऐसा करने से उस कठिन परिस्थिति से जुड़े 'अनुचित' के भाव को कम करने में मदद मिलेगी?

प्रायः हम अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को या बाहरी कारणों को दोष देते हैं। इसके अतिरिक्त हम एक ही कारण पर ध्यान देते हैं और फिर स्वयं को उस उस जिम्मेदारी से मुक्त करने का प्रयास करते हैं। जब-जब भी हम भावुक होते हैं, तो चीजें जैसी दिखती हैं और वास्तव में जैसी होती हैं, उनमें अंतर होता है। इस मामले में अगर आप जागे जाएं और बहुत ध्यान से स्थिति का आकलन करें, तो आप पाएंगे कि समस्या का कोई एक कारण नहीं है। उसके अलावा और भी कई कारण हैं। एक बार यह बात समझ में आ जाए, तो आपकी पहले वाली सोच कि वही एकमात्र कारण है, अपने आप समाप्त हो जाती है और सच्चाई प्रकट हो जाती है।

-दलाई लामा

रोजनामचा



पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

मेष : मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। संतान की सेहत का ध्यान रखें। कारोबार में वृद्धि होगी। लाभ के अवसर भी मिलेंगे। मधन सुख में वृद्धि हो सकती है। खर्च बढ़ेंगे।

वृष : मन परेशान हो सकता है। धैर्यशीलता बनाए रखें। लेखनादि कार्यों में व्यस्तता बढ़ सकती है। आय में वृद्धि भी होगी। नौकरी में कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलेगी।

मिथुन : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परंतु मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। कारोबार में बदलाव की संभावना बन रही है। पिता से धन मिल सकता है। मागदौड़ बढ़ेगी।

कर्क : संयत रहें। व्यर्थ के क्रोध से बचें। किसी मित्र के सहयोग से नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। तरक्की के अवसर भी मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होगी।

सिंह : मन परेशान रहेगा। धैर्यशीलता बनाए रखें। नौकरी में कठिनाइयां आ सकती हैं। कार्यक्षेत्र में बदलाव के साथ स्थान परिवर्तन हो सकता है। खर्च बढ़ेंगे।

कन्या : मन परेशान रहेगा। संयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखने के प्रयास करें। पढ़ाई के कार्यों में सफलता मिलेगी। परिवार की किसी महिला से धन की प्राप्ति हो सकती है।

तुला : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। कला व संगीत के प्रति रुझान बढ़ सकता है। माता की सेहत का ध्यान रखें। पिता का सान्निध्य मिलेगा। खर्चों में वृद्धि होगी।

वृश्चिक : मन परेशान रहेगा। धैर्यशीलता बनाए रखें। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा, परंतु कार्यक्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है। जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखें।

धनु : मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। आत्मविश्वास में कमी भी रहेगी। कारोबार में वृद्धि होगी। मागदौड़ अधिक रहेगी। रहन-सहन अव्यवस्थित रहेगा। आय में वृद्धि भी होगी।

मकर : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परंतु धैर्यशीलता में कमी रहेगी। परिवार का साथ मिलेगा। कारोबार में वृद्धि होगी। लाभ के अवसर मिलेंगे।

कुंभ : मन परेशान रहेगा। संयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखें। किसी मित्र से कारोबार का परतावा मिल सकता है। परिवार से दूर किसी दूसरे स्थान पर भी जा सकते हैं।

मीन : आत्मसंयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करें। नौकरी में कार्यक्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है। स्थान परिवर्तन की संभावना भी बन रही है।

वर्ग पहेली : 8480



बाएं से दाएं

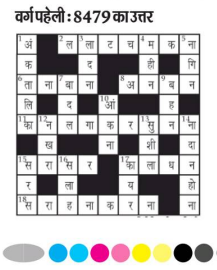
3. सहिष्णु; संतोषी; सहने वाला (5)
5. चिह्नित करना; गुण दोष जानना; परख करना (5)
6. शुभ कार्य निषेध वाला माह; पौष एवं चैत्र मास जिनमें विवाह आदि शुभ कार्य वर्जित हैं (4)
8. अभिलाषा; अरमान; टीस; साल; पुराना बैर (3)
10. एकांत; खाली; जनहीन; निर्जन; रिक्त; शून्य (2)
11. नित्य; प्रतिदिन (2)
13. तल नीचा होना; बोझ के नीचे आना; विवश होना; बात छुपना (3)
15. कटे हुए टुकड़े; काटने के बाद बचा अंश (4)
16. अंतिम क्रिया; जलाया जाना (2,3)
17. खामोश रहना; मौन रहना; शांति रखना; चुप लगाना (2,3)

ऊपर से नीचे

1. अनादर सूचक; अपमान वाला; निंदासूचक; तिरस्कारात्मक (7)
2. गति देने वाला; चलाने वाला; संचालन करने वाला; प्रबंध करने वाला (4)
3. आलेपित; गीला; तर; लिपा; पुता (2)
4. अस्वीकृत करना; मना करना; रद्द करना (4)
7. सामाजिक कुरीतियां दूर करने वाला; समाज को सुधारने वाला (3,4)
9. फंदा; फंदेदार रस्सी जिसके सहारे चोर ऊंचे मकानों पर चढ़ जाते थे (3)
12. सदा; सदैव; सर्वदा हमेशा (2,2)
14. अरुचिकर; अरोचक; जो पसंद न हो (4)
16. अन्न कण; अनाज; चबेना; कन; मनका (2)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली : 8479 का उत्तर



सुडोकू : 8434

* आसान

8		2				7		4
	5			2			9	
9			8		5			3
		7	1	8	2	9		
		5	9	6	4	3		
6			5		3			2
	3			1			6	
5		9				1		8

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3×3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 8433

2	6	8	7	3	1	9	5	4
7	5	4	2	9	8	3	1	6
9	3	1	4	6	5	8	7	2
5	9	6	1	4	3	2	8	7
3	4	7	5	8	2	1	6	9
8	1	2	9	7	6	5	4	3
4	2	9	8	5	7	6	3	1
6	7	5	3	1	9	4	2	8
1	8	3	6	2	4	7	9	5

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋषुकांत गोस्वामी

13 अक्तूबर, मंगलवार,2026, शक संवत्: 21 आश्विन (सौर) 1948, पंजाब पंचांग: 27 आश्विन मास प्रविष्टे 2083, इस्लाम: 01 जमादि उल्लावल,1448, विक्रमी संवत्: आश्विन शुक्ल तृतीया तिथि रात्रि 11.28 मिनट तक। अनुराधा नक्षत्र, प्रीति योग रात्रि 08.24 मिनट तक पश्चात आयुष्मान योग, तैतिल करण। चंद्रमा तुला राशि में सायं 07.13 मिनट तक उपरांत वृश्चिक राशि में। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। शरद ऋतु। अपराह्न 03 बजे से सायं 04.30 मिनट तक राहुकालम्। जमादि उल्लावल (मु.) मास प्रारंभ।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

कुछ ऐसे उपाय, जिससे घर और व्यापार में बरकत बनी रहे :

- प्रत्येक सप्ताह या महीने में दो बार अपनी रसोई की सफाई अवश्य करें। गैस के चूल्हे की नीचे से सफाई नियमित रूप से करें। मंगलवार को कुछ मिठाई बांटें। किसी मंदिर में या अपने घर के मंदिर में मंगलवार को सात बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। ब्रह्म स्थान पर कपूर जलाएं। अपने घर की ईशान कोण या पश्चिम दिशा में ये दो लाइन लिखकर लगाएं : 'सुख-संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का।' अपनी तिजोरी में एक आईना रखें। कुबेर का चित्र या छोटी सी मूर्ति रखें। शुक्रवार की शाम को लक्ष्मीजी के आगे चांदी के दिये में गाय के घी का दीपक जलाएं। उसमें एक हरी इलाइची भी डालें।